

सब को समर्पित समाचार पत्रिका

10 अगस्त 2020, मूल्य ₹25

# आँखें

SUBSCRIBER COPY NOT FOR RESALE

www.outlookhindi.com



## हिंदी पढ़ी के

# दंड

अपराध-राजनीति-अफसरशाही के नापाक गठजोड़ से  
पनपे दबंगों के कारनामे और नए सरगनाओं के किस्से

RNI NO. DELHIN/2009/26981





**SAGE**  
UNIVERSITY  
—INDORE—

WHERE  
YOUR  
DREAM  
COMES  
TRUE

ADMISSIONS  
**OPEN**  
2020-21

## SAGE Institute of Law & Legal Studies

### Courses Offered

#### B.A. LL.B. (Hons.)

5 years Degree Course after 12th (Any Discipline)

#### B.B.A. LL.B. (Hons.)

5 years Degree Course after 12th (Any Discipline)

#### LL.B. (Hons.)

3 years Degree Course after Graduation  
(Any Discipline)

#### LL.M.

after Law Graduation

#### Ph.D.

### OUR PROGRAMS

- SAGE Institute of Agriculture Sciences
- SAGE Institute of Advance Computing
- SAGE Institute of Architecture
- SAGE Institute of Arts & Humanities
- SAGE Institute of Biological Sciences
- SAGE Institute of Commerce
- SAGE Institute of Computer Application



Hostel Facility Available  
Bus Facility Available  
Secured Campus for Girls



Institute of Law & Legal Studies Team



Moot Court

### Accomplishments of SAGE University



Top Private University in  
Central India Award by  
Hon. Vice President Venkaiya Naidu



Emerging University of the Year in Central India  
by ASSOCHAM in 13th Higher Education,  
Skill & Livelihood Conclave



Ms. Shivani Agrawal Received  
The Young Entrepreneur Award by  
Ms. Aishwarya Rai Bachchan



Most Innovative  
Private University Award  
by ABP News 2019

Kailod Kartal, Rau Bypass, Indore - 452020 (M.P.), Website : [www.sageuniversity.edu.in](http://www.sageuniversity.edu.in)  
Contact : 95225 78382, 75093 33368, 95225 78482

Sister Concerns



**SAGE**  
UNIVERSITY  
BHOPAL



**SIRT** SAGAR GROUP  
OF INSTITUTIONS  
The SAGE Group

**SAGE**  
INTERNATIONAL  
SCHOOL  
BY SAGE GROUP OF INSTITUTIONS



**M/s Agrawal**  
Construction Co.

**AGRAWAL**  
POWER PVT. LTD.  
[www.agrawalpower.in](http://www.agrawalpower.in)

**True Sage**  
Foundation



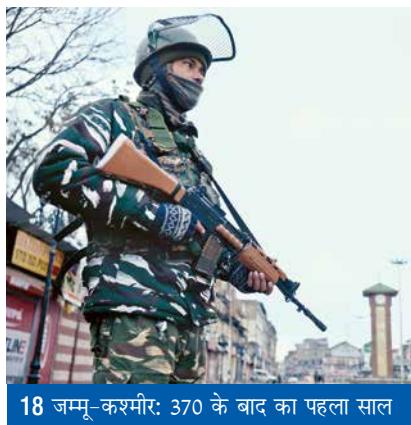
# 26 गैंगस्टर भैया

हिंदी पढ़ी, खासकर यूपी, बिहार,  
झारखंड में अपराध के नए सूरमा

**38** सत्ता के सहरे बिहार के दबंग

**41** झारखंड के कोयला माफिया

**43** बॉलीवुड भी डॉन का दीवाना



**18** जम्मू-कश्मीर: 370 के बाद का पहला साल

**08** राजस्थान: गहलोत-पायलट संघर्ष अभी बाकी

**10** बंगाल: कोरोना काल में चुनाव की सरगर्मी

**46** कांवड़ यात्रा पर कोरोना की मार

**48** बैंक कर्मचारियों पर विजनेस का दबाव

**50** कैसे घटे चीन पर निर्भरता

**52** नेपाल में ओली कथा



कवर डिजाइन: दीपक शर्मा, इलस्ट्रेशन: साहित

## आउटलुक्

वर्ष 12, अंक 8

प्रधान संपादक: लेन बनर्जी  
कार्यकारी संपादक: गिरिधर जा  
डिप्टी एडिटर: सुजील कुमार सिंह  
एसोसिएट संपादक: प्रयांत्र श्रीवास्तव  
वरिष्ठ सहायक संपादक: हरीश मानव  
सहायक संपादक: आकाशा पारे काशिव  
वेब टीम: उपासना पांडे, अक्षय दुबे  
एडिटोरियल कंसल्टेंट: हरिमोहन मित्र  
डिजाइन: दीपक शर्मा (आर्ट डायरेक्टर) लीला, प्रवीण  
कुमार. जी, विनय डॉमनिक (सीनियर डिजाइनर)  
रोहित कुमार राय (डिजाइनर), रंजीत सिंह (विजुअलाइजर)  
फोटो सेक्यूरिटी: जिवेंद्र गुप्ता (फोटो एडिटर), त्रिभुवन  
तिवारी (चीफ फोटोग्राफर), संदीपन चट्टर्जी, अपूर्व  
सलकड़े (सीनियर फोटोग्राफर) सुशील कुमार पाण्डि (स्ट्यूक्या  
फोटोग्राफर), जे.एस. अधिकारी (सीनियर फोटो रिसर्चर)  
संर्वेत: अलका गुप्ता

विजनेस का यांत्रिय:  
चीफ एक्सीक्यूटिव ऑफिसर: इन्द्रनील राय  
प्रकाशक: संदीप कुमार शोष  
सीनियर वाइस प्रेसिडेंट: मीनाक्षी आकाश  
सीनियर जनरल मैनेजर: देववाणी टैगोर,  
रोहित बोहरा  
डिजिटल टीम: अमित मिश्र  
पार्किटिंग:  
वाइस प्रेसिडेंट: ब्रह्मिका दीवान  
संकुलेशन एंड सबक्रिक्शन: गगन कोहली, जी.  
मेंस (साउथ), कपिल ढल (नार्थ),  
अरुण कुमार ज्ञा (ईंडर)

प्रोडक्शन:  
जनरल मैनेजर: शशांक दीक्षित  
मैनेजर: सुधा शर्मा, गोविंद श्रीवास (एसोसिएट  
मैनेजर), गणेश साह (डिप्टी मैनेजर)  
अकाउंटंट:  
वाइस प्रेसिडेंट: दीवान सिंह विप्ट  
कंपनी सेक्रेटरी एवं लॉ ऑफिसर: अंकित मांगल  
प्रधान कार्यालय: ए.बी.-10 सफदरजंग एकलेव,  
नई दिल्ली-110029  
संपादकीय कार्यालय: ए.बी.-10 सफदरजंग  
एकलेव, नई दिल्ली-110029  
टेलीफोन: 011-71280400, फैक्स: 26191420

संपादकीय ईमेल  
edithindi@outlookindia.com  
ग्राहकों के लिए संरक्षक: 011-71280433,  
71280462, 71280307  
yourhelpline@outlookindia.com  
अन्य कार्यालय:  
मुंबई: 022-50990990  
कोलकाता: 46004506, फैक्स: 46004506  
चेन्नई: 42615224, 42615225 फैक्स: 42615095  
बैंगलूरू: 43715021  
प्रधान संपादक: लेन बनर्जी  
आउटलुक् प्रालिंग (ईंडिया) प्रा.लि. की तरफ से  
इन्हींल रोय द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित। एसपी प्रिंटर्स  
(ए.शून्य ऑफ.डी.बी.कॉर्प., लिमिटेड), बी-220/  
223, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेज 2 नोएडा, यूपी से  
मुद्रित और ए.बी.-10 सफदरजंग एकलेव, नई  
दिल्ली से प्रकाशित।



## एसईजेड का हो उपयोग

आउटलुक हिंदी के 27 जुलाई अंक की आवरण कथा बहुत अच्छी लगी। टिकटॉक के बहाने इसमें चीनी एप और चीन के साथ व्यापार की अच्छी पड़ताल की गई है। अब देश में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को अधिकतम प्रोत्साहन देने और विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाना जरूरी है। भारत के अब तक नियंत्रण मोर्चे पर पीछे रहने का एक बड़ा कारण सेज का अपने मकसद में कामयाब न होना भी है।

शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी | फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश

## श्रेष्ठ पत्र को उपहार स्वरूप 1000 रुपये मूल्य की पुस्तकें

तकनीकी विकास ने पत्र लेखन की विधा को हाशिए पर जरूर धकेला है, लेकिन यह विधा पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। पत्र लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए आउटलुक हिंदी पत्रिका अपने पाठकों के लिए एक योजना ला रही है। यह पत्रिका के लिए प्रतिक्रिया स्वरूप मिलने वाले पाठकों के पत्र महत्वपूर्ण होते हैं। आउटलुक हिंदी पत्रिका में प्रकाशित लेखों पर 150 शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया भेजें और पाएं हिंदी के प्रतिष्ठित सामयिक प्रकाशन की ओर से एक हजार रुपये मूल्य की पुस्तकें। हर अंक में उपरे वाले पत्रों में से एक सर्वश्रेष्ठ पत्र चुना जाएगा।

द्यान सर्वे किं पत्र साफ लिखे गए हैं और लेखे न हों। संबंधित लेख का उल्लेख जरूर करें और अपनी टिप्पणी सटीक रखें। चुने गए पत्र पत्रिका में प्रकाशित किए जाएंगे। अपना नाम एवं पिन कोड सहित पूरा पता जरूर लिखें। संपादकीय निर्णय सर्वोपरि होगा।



## चुनाव की सुगबुगाहट

आउटलुक के 27 जुलाई अंक में, यशवंत सिन्हा का साक्षात्कार पढ़ा। साल के अंत में बिहार में चुनाव होने हैं। ऐसे में जरूरी है कि बिहार की बुनियादी जरूरतों और समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। पिछले 27 साल से बिहार में कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है। कोरोना के चलते लगातार मजदूरों के लौटने से रोजगार का संकट बढ़ गया है। जनता अब वहीं सरकार चुने, जो इन मसलों पर पूरा ध्यान दे सके।

रोहित शर्मा | दिल्ली

## राजनीति का अपराधीकरण

अपराधी को जब तक कड़ा दंड नहीं मिलता, उसके हाँसले बुलंद रहते हैं। विकास दुबे के कारनामे राजनीतिक मिलीभगत का नतीजा है। दुबे के नेताओं के साथ संबंधों की जांच जरूरी है, ताकि कल फिर कोई नया विकास दुबे पैदा न हो।

अमृतलाल मारू | धार, मध्य प्रदेश

## पुलिस सुधार

पुलिस की छवि में सुधार के लिए जरूरी है सभी बीट कॉन्स्टेबल को उसके क्षेत्र में हो रहे अवैध कामों की रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी दी जाय। और उसकी निगरानी सीनियर स्तर के प्रत्येक अधिकारी के जिम्मे हो। अवैध काम को बंद कराने के लिए क्या कदम उठाए गए, इसकी भी गोपनीय रिपोर्ट तैयार हो। ऐसा करने से सुधार की किरण दिख सकती है।

सुरेन्द्र कुमार | गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

## पुरस्कृत पत्र

### शांतिपूर्ण हों संबंध

आउटलुक 13 जुलाई के अंक में 'हर पड़ोसी मोर्चे पर दबाव बढ़ा' लेख पढ़ा। हाल के दिनों में भारत-नेपाल, चीन संबंधों में तनाव देखने को मिल रहा है। दोनों ही देशों के साथ हमारा सीमा विवाद है। इस बीच नेपाल सरकार ने भारतीय मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसका कहना है कि भारतीय मीडिया नेपाल की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। नेपाल के साथ संबंधों में गिरावट भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इससे चीन को नेपाल में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिल रहा है। नेपाल की अति महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति को देखते हुए भारत को कोशिश करना चाहिए कि दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण संबंध हों। चीन के साथ भी हमें संबंध मध्यर रखना चाहिए। पड़ोसी देश के साथ विवाद भारत के विश्वगुरु बनने के सपने में बाधा बन सकता है।

शोषमणि शर्मा | इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश

अब आप अपने पत्र इस मेल पर  
भी भेज सकते हैं:

[hindioutlook@outlookindia.com](mailto:hindioutlook@outlookindia.com)

## आउटलुक पत्रिका प्राप्त करने के स्थान

**दक्षिण:** हैदराबाद यादगिरी बुक स्टॉल, 040-66764498, सिंकंदराबाद उस्मान बुक स्टॉल, 9912850566

**उत्तर:** दिल्ली - आईबीएच बुक्स एंड मैग्जीन डिस्ट्रिब्यूटर्स, 011-43717798, 011-43717799, लखनऊ - सुभाष पुस्तक भंडार प्रा. लिमिटेड, 9839022871, चंडीगढ़ - पुरी न्यूज एंजेसी, 9888057364, देहरादून - आदित्य न्यूज एंजेसी, 9412349259, भोपाल - ईंडियन न्यूज एंजेसी, 9826313349, रायपुर - मुकुंद पारेख न्यूज एंजेसी, 9827145302, जयपुर-नवरत्न बुक सेलर, 9829373912, जम्मू - प्रीमियर न्यूज एंजेसी, 9419109550, श्रीनगर - जैपी न्यूज एंजेसी, 9419066192, दुर्ग (छत्तीसगढ़) - खेमका न्यूज एंजेसी, 9329023923

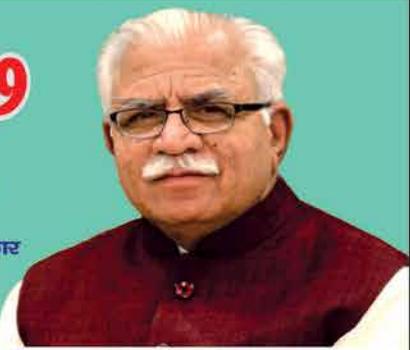
**पूर्व:** पटना - ईस्टर्न न्यूज एंजेसी, 9334115121, बरानी - ज्योति कुमार दत्ता न्यूजपेपर एंडेंट, 9431211440, मुजफ्फरपुर-अन् नू मैग्जीन सेंटर, 9386012097, मोतीहारी- अंकित मैग्जीन सेंटर, 9572423057, कोलकाता - विशाल बुक सेंटर, 22523709/22523564, रांची- मॉडर्न न्यूज एंजेसी, 9835329939, रवि कुमार सोनी, 9431564687, जमशेदपुर-प्रसाद मैग्जीन सेंटर, 2420086, बोकारो-त्रिलोकी सिंह, 9334911785, भुवनेश्वर-ए. के. नायक, 9861046179, गुवाहाटी- दुर्गा न्यूज एंजेसी, 9435049511

**पश्चिम:** नागपुर- नेशनल बुक सेंटर, 8007290786, पाठक ब्रदर्स, 9823125806, नासिक- पाठक ब्रदर्स, 0253-2506898, पुणे- संदेश एन एंजेसी, 020-66021340, अहमदाबाद-के वी अजमेरा एंड संस, 079-25510360/25503836, मुंबई- दंगत न्यूज एंजेसी, 22017494

# कोरोना वायरस कोविड-19

## की रोकथाम एवं रोग प्रतिरोधक

## क्षमता बढ़ाने के आयुर्वेदिक उपाय



श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

### रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाएं

- ✓ पूरे दिन केवल गर्म पानी पिएं।
- ✓ प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान करें।
- ✓ हल्दी, जीरा, धनिया एवं लहसुन आदि मसालों का भोजन बनाने में प्रयोग करें।



### सामान्य आयुर्वेदिक प्रक्रियाएं

- ✓ नस्य - सुबह एवं शाम तिल/नारियल का तेल या धी नाक के दोनों छिद्रों में लगाएं।
- ✓ केवल एक चम्मच तिल/नारियल तेल को मुँह में लेकर दो से तीन मिनट कुल्ले की तरह मुँह में ही धुमाएं। उसके बाद उसे कुल्ले की तरह ही थूक दें। फिर गर्म पानी से कुल्ला कर लें। ऐसा दिन में एक से दो बार करें।

### खांसी/गले में खराश के लिए

- ✓ दिन में कम से कम एक बार पुदीना के पत्ते/अजवायन डाल कर पानी की भाप लें।
- ✓ खांसी या गले में खराश होने पर लौंग के चूर्ण में गुड़ या शहद मिलाकर दिन में दो से तीन बार लें। (अगर ये लक्षण बने रहते हैं तो डॉक्टर से परामर्श लें)

### रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय

- ✓ च्यवनप्राश 10 ग्राम (एक चम्मच) सुबह लें। मधुमेह के रोगी शुगर फ्री च्यवनप्राश लें।
- ✓ तुलसी, दालचीनी, कालीभिर्च, सोंठ (सूखी अदरक) एवं मुनक्का से बनी हर्बल टी/काढ़ा दिन में एक से दो बार पिएं (स्वाद के अनुसार इसमें गुड़ या ताज़ा नीबू रस मिला सकते हैं)
- ✓ गोल्डन मिल्क (हल्दी वाला दूध) - 150 एम.एल. गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी चूर्ण दिन में एक से दो बार लें।

मंत्रालय, जन सम्बन्ध एवं भाषा विभाग, हरियाणा | www.phrajyana.gov.in





कुछ लोगों को लगता है कि राम मंदिर बनने से कोरोना अत्म हो जाएगा।

शरद पवार, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी

## कौन बनेगा पोस्टर ब्वॉय

**म**ध्य प्रदेश में भले ही भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहारे सत्ता हासिल कर ली है, लेकिन अब उसके साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। मामला उपचुनाव में पोस्टर ब्वॉय बनने का है। असल में जिन क्षेत्रों में उपचुनाव होने वाले हैं, वहां पर ज्यादातर प्रभाव ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। ऐसे में स्थानीय नेता प्रचार में यह नहीं समझ पा रहे हैं कि पोस्टर पर प्रमुखता से सिंधिया की फोटो लगाई जाय या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। समाधान के लिए मामला जब दोनों नेताओं के पास पहुंचा तो वहां भी बात नहीं बनी। साफ है कि भले ही पार्टी एक हो गई है, लेकिन नेताओं के दिल अभी एक नहीं हुए हैं।



## रिटायरमेंट की तैयारी

**ए**क प्रमुख सरकारी बैंक के चेयरमैन इस साल दिसंबर में रिटायर होने वाले हैं। लेकिन उनकी रिटायरमेंट बाद की पारी की अभी से सुगबुगाहट होने लेगी है। ऐसी चर्चा है कि इसके लिए वह अभी से किसी अच्छे पद की तलाश में हैं। बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों में भी यह बात होने लगी है कि साहब के तेवर पिछले कुछ समय से बदले नजर आ रहे हैं और वे रिटायरमेंट बाद की तैयारी में पूरी तरह से जुट गए हैं। देखना यह है कि उनकी मुराद पूरी होती है या नहीं। हालांकि पिछले चेयरमैन का रिकॉर्ड देखते हुए यह आसान दिखता है।

## संन्यास का इरादा

**ल**गता है कि भाजपा के बाद कांग्रेस में भी अब वरिष्ठ नेताओं को संन्यास की राह पकड़ाई जाएगी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, जो काफी लंबे समय से कांग्रेस परिवार के करीबी भी रहे हैं, उनके संन्यास लेने की चर्चा है। उनको लेकर पार्टी में कई बार कुछ वरिष्ठ नेताओं ने वह मांग उठाई थी, कि अब उन्हें सक्रिय राजनीति से किनारा कर लेना चाहिए। जिस तरह से सचिन पायलट का मामला सामने आया है, लगता है कि शीर्ष नेतृत्व इन संभावनाओं को तलाश रहा है। हालांकि कांग्रेस में ऐसा आसानी से हो जाए, ऐसा इतिहास तो नहीं रहा है।

## अध्यक्ष के बहाने दो शिकार

**ह**रियाणा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भाजपा ने फिर से जाति के समीकरण का कार्ड खेला है। जाट चेहरे सुभाष बराला की जगह दूसरे जाट चेहरे ओमप्रकाश धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। हालांकि दौड़ में धनखड़ से कहीं दिग्गज जाट चेहरा कैप्टन अभिमन्यु का भी था, पर उन्हें दरकिनार करते हुए भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने धनखड़ पर दांव खेला है। अध्यक्ष पद के लिए अभिमन्यु पिछले छह महीने से दिल्ली में रहकर कड़ी लॉबिंग कर रहे थे। अभिमन्यु और किसी अन्य जाट नेता का खेल बिगड़ने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर

ने हाइकमान से यहां तक कह दिया था कि बराला की जगह किसी अन्य जाट नेता को ही अध्यक्ष बनाना है तो क्या बराला ही इस पद पर नहीं बने रहे सकते। जाट चेहरे की काट में मुख्यमंत्री खट्टर ने ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले अपने खासमखास सांसद नायब सिंह सैनी का नाम भी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए आगे बढ़ाया, पर इस खेल में खट्टर भी पूरी तरह से हाशिए पर आ गए। भाजपा हाइकमान ने भी धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एक तीर से दो निशाने साधे। एक तो विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड़ा की टक्कर में उनके ही इलाके के जाट नेता को मौका दिया, वहां सरकार के समानांतर पार्टी संगठन में हस्तक्षेप से मुख्यमंत्री खट्टर को दूर रखा।



# BANASTHALI VIDYAPITH

(Notified Under Section 3 of the UGC Act)

University for women: University with a difference

## Banasthali Vidyapith

is re-accredited by **NAAC** with



**'A++'**

with a **CGPA of 3.63 -**

the highest for a private multi-disciplinary university.  
Banasthali also becomes the only university in Rajasthan  
and only women's university to attain 'A++'.

Banasthali Vidyapith is the largest fully residential and 2nd highest ranked women's university in the world having more than 15000 students on its 850-acre campus situated amidst rural setting in Rajasthan and having a distinct educational ideology and offering a variety of programmes from nursery up to doctoral level across a wide spectrum of disciplines to prepare enlightened citizens with strong value-base.

### COURSES

Arts | Humanities | Social Sciences | Biotechnology | Bioscience | Computer Science | Mathematical Science | Physical Sciences | Earth Sciences | Electronics | Engineering | Nanotechnology | Fine Arts | Management | Commerce | Aviation Science | Law Education | Physical Education | Home Science | Design | Pharmacy | Journalism & Mass Communication | Nursing



INDIA TODAY 2nd Rank

P. O. Banasthali Vidyapith (Raj.) 304022 • Phone : 01438-228787/228373

<http://www.banasthali.org>

# परदा गिरा नहीं, खेल अभी

पहली बाजी भले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम रही लेकिन पायलट और भाजपा की चुनौती जल्दी खत्म



सभी फोटो पीटीआई

## पुनीत निकोलस यादव

**रा**जस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहचान धैर्यवान और अपनी भावनाओं को सार्वजनिक न करने वाले नेता की रही है। वे चतुराई से परदे के पीछे की राजनीति करने में माहिर हैं। अपनी इन खासियतों की वजह से वे पिछले 45 साल से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को बड़ी असानी से मात भी देते आए हैं। शह-मात के इस खेल में उन्होंने पहले परसराम मदरणा, सी.पी.जोशी को और अब सचिन पायलट को मात देते दिख रहे हैं। करीब दो हफ्ते पहले ऐसा लग रहा था कि सचिन पायलट के बागी तेवर के आगे गहलोत सरकार जल्द ही गिर जाएंगी। उस वक्त शायद वे पहली बार इन्हें अधीर दिखें। उसी अधीरता में दो बार उन्होंने ऐसे बयान दिए, जो उनकी छवि से मेल नहीं खाते थे।

असल में 11 जुलाई को पायलट 18 कांग्रेस विधायकों के साथ जब जयपुर छोड़कर दिल्ली आ गए, तब राजस्थान में गिरती सरकार बचाने के लिए कांग्रेस आलाकमान सीधे हस्तक्षेप कर रहा था। लेकिन सचिन पायलट प्रियंका गांधी से छह बार बात

करने के बावजूद, गहलोत के साथ किसी समझौते के लिए तैयार नहीं थे। उधर भारतीय जनता पार्टी की भी उम्मीदें बढ़ गई थीं। उसे लग रहा था कि वह मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी सरकार बना लेगी। शायद यही वजह रही कि गहलोत ने अपना आप खो दिया।

गहलोत, पायलट को उप-मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटवाने में कामयाब रहे। आलाकमान भी पायलट के रवैये को देखते हुए गहलोत की बात मानने पर मजबूर हो गया। इस बीच विधानसभा

अध्यक्ष सी.पी.जोशी से भी बागी सदस्यों को नोटिस जारी कर दिया है।

बढ़ते खतरे को देखते हुए पायलट और उनके साथियों ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी पैरवी में वरिष्ठ वकील हरीश सालवे और मुकुल रोहतगी उतरे। हाइकोर्ट से पायलट कैप को 24 जुलाई तक राहत मिल गई, तो विधानसभा अध्यक्ष जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी (इन पक्षियों के लिखे जाने तक सुप्रीम कोर्ट से कोई खबर नहीं थी)।

राजस्थान में जारी इस राजनीतिक संकट के बीच तीन ऑडियो टेप 'लीक' होने से मामला गरमा गया है। टेप में कांग्रेस के बागी विधायक भंवरलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत और एक अन्य भाजपा नेता संजय जैन के बीच हुई कथित बातचीत सामने आई है। बातचीत से पता चलता है कि तीनों नेता मिलकर विधायकों की खरीद-फरोख्त कर गहलोत सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं। बात यहीं नहीं रुकी। कांग्रेस के एक अन्य विधायक गिरिराज मलिंगा ने सचिन पायलट पर आरोप लगाया है कि उन्हें भाजपा में

# जारी

होती नहीं दिखती



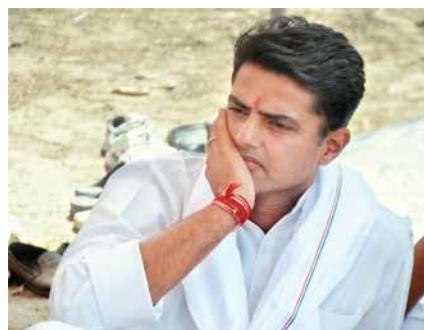
**फिलहाल तो एकजुटः** जयपुर के फेयरमांट होटल में विधायक दल की बैठक में गहलोत

शामिल होने के लिए 35 करोड़ रुपये देने की पेशकश की गई थी। हालांकि इस बीच कांग्रेस के कदाचर नेता दिवंगत राजेश पायलट के 42 वर्षीय बेटे सचिन पायलट ने सार्वजनिक तौर पर यह कहा है कि वे कांग्रेस में ही हैं और भाजपा में शामिल नहीं होंगे। अब बात करते हैं सार्वजनिक तौर पर गहलोत की उस प्रतिक्रिया की, जिसमें उन्होंने पायलट के खिलाफ खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। हो सकता है कि जिस चालाकी से पायलट ने उनके खिलाफ खेमबंदी की, उससे वे अपना गुस्सा संभाल नहीं पाएं या फिर 69 साल के एक वरिष्ठ के साथ पायलट ने जैसा सलूक किया, वह उन्हें रास नहीं आया। एक बात तो साफ है कि जिस तरह पायलट पूरी मजबूती से गहलोत को चुनौती दे रहे हैं, वैसी चुनौती उन्हें कांग्रेस तो छोड़ दिए, भाजपा से भी कभी नहीं मिली है।

इसके पहले गहलोत ने पायलट पर हमला बोलते हुए कहा था कि वे 26 साल की उम्र में लोकसभा

संसद बने और 40 साल की उम्र तक उप-मुख्यमंत्री बन गए। वे यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा, “केवल अच्छा दिखने और अच्छी अंग्रेजी-हिंदी बोलने से कोई नेता नहीं बना जाता है। उसके लिए आपके पास विचारधारा और प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए।” इस सार्वजनिक हमले के बाद गहलोत ने एक और बयान दिया, जिसमें उन्होंने पायलट को नकारा और निकम्मा बताया। पायलट पर जिस तरह के शब्दों के जरिए गहलोत ने हमला किया है, उससे कांग्रेस पार्टी का आलाकमान भी खुश नहीं है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने आउटलुक को बताया कि गहलोत को साफ तौर पर संदेश दिया गया है कि वे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करें। पार्टी का एक तबका अभी भी चाहता है कि पायलट को समझाकर मामले को सुलझा लिया जाए। कांग्रेस पार्टी में पायलट से सहानुभूति रखने वाले नेताओं का मानना है कि पायलट ने अभी तक पार्टी के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। इसके अलावा उनके गांधी परिवार से रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं।

पायलट की आगे रणनीति क्या होगी? एक, तो यह कि वे भाजपा का दामन थाम लें, दूसरे यह कि वे नई पार्टी बनाएं। आलकमान के संदेश के बाद सार्वजनिक तौर पर भले ही गहलोत ने यह कहा है कि अगर पायलट अपने विद्रोही तेवर वापस ले लेते हैं, तो वे उन्हें गले लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि अब ऐसा होना असंभव है। राजस्थान के नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसारा का कहना है, “अगर पायलट



**पायलट टकराव के उस मोड़ पर पहुंच गए हैं, जहां से वापसी संभव नहीं दिखती।**  
**कांग्रेस के केंद्रीय नेता उनकी वापसी चाहते हैं मगर गहलोत के तेवर कड़े**

यह कहते हैं कि वे कांग्रेस में ही रहेंगे तो वे बातचीत के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? उनके लिए भाजपा के करीबी वकील हरीश सालवे और मुकुल रोहतगी अदालत में पैरवी कर रहे हैं। बागी विधायक जिस होटल में हैं वह भी भाजपा शासित हरियाणा में है।”

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और बात सार्वजनिक तौर पर कही है कि वे पहले से जानते थे कि सचिन पायलट और उनके साथी पिछले कई महीनों से भाजपा के साथ मिलकर सरकार विरोधी काम कर रहे थे। इसके तहत सरकार गिरने के बाद योजना थी कि पायलट एक क्षेत्रीय दल बनाएंगे और उपचुनाव में भाजपा उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगी। इसके बाद पायलट भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाते।

पायलट के एक करीबी नेता ने आउटलुक को बताया कि गुर्जर नेता नई पार्टी बनाने के विचार पर अमल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं किया गया है। अभी पायलट टोंक से कांग्रेस के विधायक हैं। पूरे मसले पर भाजपा का आधिकारिक बयान यही है कि गहलोत सरकार के संकट के लिए कांग्रेस की अंदरूनी कलह जिम्मेदार है। भाजपा का यह बयान उसी तरह का है जैसा उसने मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिधिया की बगावत के समय दिया था। हालांकि भाजपा के सूत्रों ने आउटलुक को बताया कि सिधिया के पास सरकार गिराने के लिए पर्याप्त संख्या में विधायक मौजूद थे, लेकिन पायलट के साथ ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने साथ 30 विधायकों के आने का दावा किया था, लेकिन अभी तक 18 विधायक ही उनके साथ खड़े हैं। ऐसे में हम सार्वजनिक तौर पर उनका समर्थन क्यों करें, जब भाजपा की सरकार बनने की गांठटी नहीं है।

एक अन्य वरिष्ठ विधायक का कहना है कि राज्य में भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी गहलोत सरकार गिराने के पक्ष में नहीं हैं। वे तब तक ऐसा नहीं करेंगी, जब तक उन्हें भरोसा नहीं होगा कि वे फिर से मुख्यमंत्री पद संभालेंगी। पार्टी के 72 विधायकों में से 45 विधायक वसुंधरा के समर्थक हैं। एक और बात समझने वाली है कि वसुंधरा किसी भी सूरत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पनिया, विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत को मुख्यमंत्री पद देने का समर्थन नहीं करेंगी। ऐसे में राजस्थान में भाजपा की भी स्थिति पायलट जैसी हो गई है। इस बीच, कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि अभी राजनीतिक ड्रामा लंबा चलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 200 सदस्यों वाली विधानसभा में 109 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। हालांकि भाजपा भी इतनी आसानी से चुप बैठने वाली नहीं है। ऐसे में गहलोत और कांग्रेस आलाकमान को भी राजस्थान के रण में फाइनल जीत के लिए मजबूत तैयारी करनी होगी। लेकिन सत्ता के इस खेल में जनता की फिक्र किसे है!



संदीपन चटर्जी

# लाल झंडे फिर लहराए

नए दफ्तरों और रैलियों से माकपा  
में जान फूँकने की कोशिशें और  
अगले साल विधानसभा चुनावों में  
बेहतर नतीजों की उम्मीद

◀ कोलकाता से शुभोजित बागची

**स**मूचा पश्चिम बंगाल कोरोनावायरस संक्रमण की बेकाबू लहर और रह-रहकर लॉकडाउन के थपेड़ों से झुलस रहा है। बावजूद इसके, यहाँ कई लोगों, खासकर सियासी सरपरस्तों की नजरें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों पर जमी हुई हैं। 40 बरस के बढ़ई कादर मुल्ला कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल के रोनॉल्ड रॉस बिल्डिंग के गलियारे के आखिरी कोने में डॉक्टर के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। सुंदरबन इलाके के रहने वाले मुल्ला ने कुछ साल पहले माकपा से नाता तोड़ तृणमूल कांग्रेस की ओर रुख कर लिया था, जैसा अमूमन चलन रहा है। उनके हिसाब से 2021 में विधानसभा चुनावों के नतीजे इस सवाल से तय होंगे कि, “क्या 2019 में भाजपा की ओर चला गया वामपंथी पार्टियों के बोटों का 20 फीसदी या कम से कम उसका आधा लौट आता है या नहीं?”

भले यह इकलौती वजह न हो, लेकिन निश्चित रूप से महत्वपूर्ण वजह है कि तृणमूल कांग्रेस यह आश्वस्त करे कि माकपा हर जगह अपने दफ्तर खोले और रैलियां करे। खासकर वहाँ, जहाँ 2011

में तृणमूल के सत्ता में आने के बाद माकपा के दफ्तर तोड़ दिए गए या कब्जा लिए गए। मुल्ला कहते हैं, “हमारे इलाके में माकपा ने अपने दफ्तर खोल लिए हैं और अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं।” तृणमूल का गणित यह है कि वामपंथीयों की चुनावी मैदान में दमदार वापसी से आक्रामक भाजपा से लड़ाई उसके हक में आ जाएगी। इस गणित के अनुसार, अगर तृणमूल विरोधी बोट वाम मोर्चे और भाजपा में बंट जाता है तो उसकी जीत तय है, जो 2019 के लोकसभा चुनावों में नहीं हुआ और भाजपा राज्य की कुल 42 संसदीय सीटों में से 18 जीत गई थीं। 2019

में 294 विधानसभा क्षेत्रों में से 121 पर भाजपा की बढ़त ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी को डरा दिया है।

पिछले छह वर्षों में बंगाल के लेपट मतदाताओं के दक्षिणपंथ की ओर झुक जाने का साफ सबूत 2019 में मिला, जब वाम मोर्चे की वोट हिस्सेदारी 25.69 फीसदी (2016 के विधानसभा चुनावों में) और 29.99 फीसदी (2014 के लोकसभा चुनाव में) से घटकर 7.53 फीसदी रह गई। भाजपा की वोट शेयर 17 से 40 फीसदी पर पहुंच गया।

सो, तृणमूल मशक्त में जुट गई है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं, “अगर माकपा के कम से कम 2-4 फीसदी वोट भी उसकी ओर लौट जाते हैं, तो हमारी राह सुक्षित हो जाती है।” जमीन पर ऐसी हलचल दिख भी रही है। माकपा अममन कांग्रेस के साथ मिलकर पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम जैसे अपने पुराने गाँवों में बड़ी रैलियां कर रही हैं, जहां भूमि अधिग्रहण विवाद के खिलाफ हुए बहुर्चित आंदोलन से ही वाममोर्चे की गर्दिश शुरू हुई थी। पिछले हफ्ते विधानसभा में वाम विधायक दल के नेता सुजोन चक्रवर्ती और कांग्रेस के अब्दुल मन्नान ने नंदीग्राम से सटे खेजुरी ब्लॉक में साझा रैली की। इसी खेजुरी में 2006 और 2011 के बीच हुई हिंसा से लेपट की ताकत टूटी थी और तृणमूल को शह मिल गई थी। अब 2020 में भाजपा और तृणमूल के बीच लगातार जारी जुबानी बयानबाजी और हिंसक वारदातों से तंग आ चुके और सरकार विरोधी रुझान से असंतुष्ट वोटरों का मन बदला है इसलिए इन इलाकों में फिर माकपा को बढ़त मिलने लगी है।

यही कहानी उत्तर बंगाल के कूचबिहार की भी है। वहां हाल में दिनहाटा में कथित तौर पर स्थानीय तृणमूल नेताओं ने स्टूटेंड्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआइ) के राज्य सचिवालय सदस्य शुभ्रलोक दास को परेशान करने के लिए लड़कों को भेजा, तो उन्होंने तत्खोलिक (फौरन) रैली करने का फैसला किया। दास कहते हैं, “हमने रैली के लगभग 12 घंटे पहले फेसबुक पर इसकी घोषणा की तो करीब 500 लोग जुट गए।” वार्कइं, एक साथ कॉविड-19 और अमफेन चक्रवात के झटकों से हलकान राज्य के हर जिले हसुआ-हथौड़ी वाला लाल झंडा पूरे भरोसे से लहराने लगा है। माकपा के राज्यसभीय नेताओं का कहना है कि यह कठिनाई के दौर में स्वयंसंरूप प्रतिक्रिया है।

राज्य समिति के एक सदस्य कहते हैं, “कुछ महीने पहले तक, हमारे पास अग्रिम मोर्चे पर लड़के-लड़कियों की फौज कम ही दिखती थी। लेकिन अमफेन चक्रवात के राहत कार्य में हमारे साथ बहुत-से ऐसे जुड़े, जो बीसेक साल उपर के हैं। यह वार्कई उत्साहवर्द्धक है।” दास की भी यही राय है। वे कहते हैं, “भाजपा और उसके छात्र विंग

के पास हिंदुत्व है, तो एसएफआइ के पास असली मुद्दे हैं।”

माकपा के दक्षिण 24 परगना जिला कार्यालय में लाल रंग से पुस्ते कोने वाले कमरे में बैठे सुजोन चक्रवर्ती पार्टी के लिए हालात बदलने में स्थानीय मुद्दों के साथ वैश्विक घटनाक्रम को जोड़कर देखते हैं। वे कहते हैं, “लोगों का पूँजीवाद से मोर्खभंग हो रहा है। आखिर उन्हें एकाधिकार दबदबे वाले पूँजीवाद से क्या मिल रहा है?” उनका यह भी कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार रोजगार सृजन के अपने वादे को निभाने में नाकाम रही है। वैश्विक कीमतें कम हो रही हैं मगर “यहां तेल की कीमतें बढ़ रही

का “ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने” का नजरिया है। वे मानते हैं कि “सांप्रदायिक आधार पर खासकर मुसलमानों और वामपंथियों के खिलाफ ध्रुवीकरण से तृणमूल और भाजपा दोनों को फायदा होगा।”

इन मुद्दों पर संसदीय और विधानसभा चुनाव में अलग-अलग तरह के दाव थे, इसके बावजूद टीएमसी को 2014 में 39 फीसदी वोट शेयर के साथ 34 सीटें मिलीं और पांच साल बाद 44 फीसदी उच्चतम वोट शेयर के बाद बमुशिक्ल 22 सीटें मिलीं। मतलब यह कि ध्रुवीकरण की राजनीति जैसे जोर पकड़ी, तृणमूल को सीटों के मद में और वाम दलों को सीटों और वोट शेयर दोनों मामले में नुकसान उठाना पड़ा। इसका दोष तृणमूल पर भी है, क्योंकि उसने वाम दलों को आक्रामक तरीके से हाशिए पर धकेल दिया। इस तरह तृणमूल समूचे बंगाल में भाजपा की लगातार बढ़त को शायद ही रोक पाए और दोतरफा दिखती जंग को त्रिकोणीय मुकाबले में शायद ही बदल पाए।

उत्तरी 24 परगना के छोटा जागुलिया गांव के फारवर्ड ब्लॉक के एक स्थानीय नेता यूनस अली भाजपा में शामिल होने वाले शुरूआती वामपंथी जमीनी कार्यकर्ताओं में से एक हैं। उनके घर पर हमला किया गया, पीटा गया, उनके माकपा कार्यकर्ता भाई को जेल में बंद कर दिया गया। उनके पास भाजपा में शामिल होने के अलावा विकल्प कम थे। ताकत के जोर से “विपक्ष-मुक्त” माहौल बनाने के प्रयास में, तृणमूल ने अली जैसे हजारों को लोगों को भाजपा की झाली में डाल दिया।

आरएसएस के स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह-संयोजक और भाजपा के आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रभारी धनपत राम अग्रवाल का कहना है कि टीएमसी के लिए सत्ता बरकरार रखना मुश्किल होगा। वह कहते हैं, “भाजपा का वोट फिर माकपा को मिलने की कोई संभावना नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि न तो टीएमसी और न ही सीपीआई (एम) विकल्प हैं, तो वे लोग भाजपा की ओर आ रहे हैं। बांग्लादेश से घुसपैठ और उद्योग दो प्रमुख कारक हैं और यहां, दोनों विफल रहे हैं।” उनका मानाना है कि जहां कांग्रेस और माकपा कुछ समर्पित वोटों पर कब्जा करेंगे, वहां टीएमसी का वोट शेयर भाजपा को फायदा पहुंचाएगा। एक हद तक तृणमूल सत्ता-विरोधी लहर की बात स्वीकारती है, लेकिन वह ममता बनर्जी के करिश्मे और नेतृत्व पर उम्मीद जताती है। मुल्ला कहते हैं कि बंगाल में एक बार किसी को चुन लेने के बाद मतदाता सरकार बदलने में समय लेते हैं, यह दर्शाता है कि टीएमसी सत्ता में रहेगी। सुंदरबन के ये बढ़ई कहते हैं, “माकपा के उदय से मुकाबला फिर त्रिकोणीय हो जाएगा, जो तृणमूल के लिए महत्वपूर्ण है।”



## भाजपा की लगातार बढ़त ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी तनाव में ला दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव उनके लिए अग्निपरीक्षा की तरह होंगे

हैं।” श्रमिकों के अधिकार तेजी से गायब हो रहे हैं, जबकि बंगाल में तो पूरी अराजकता है। चक्रवर्ती कहते हैं, “ये तमाम हालात वामपंथ के लिए जगह बना रहे हैं।” वे इस बात को सिरे से नकार देते हैं कि तृणमूल वामपंथी दलों को सरकार विरोधी वोट बांटने के लिए बढ़ावा दे रही हैं।

वे कहते हैं, “तृणमूल की जमीन खिसक रही है, उसके लोग छोड़कर जा रहे हैं, उसके पास हमें रोकने का कोई उपाय नहीं है।” लेकिन असली सबाल वही है, जो कोलकाता में मुल्ला ने उठाया कि क्या क्या वामपंथ से मुंह मोड़ चुका 20 फीसदी वोट उसकी ओर लौटेगा? चक्रवर्ती लगभग बुद्धिमत्ता हुए कहते हैं, “यही लाख टके का सवाल है।” लंबी चुप्पी के बाद थोड़ा संभलकर वे कहते हैं, “हमें बड़ी संख्या में अपने वोट वापस पाने की उम्मीद है। संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दो बातें महत्वपूर्ण हैं।” बकौल उनके, एक तो तृणमूल और भाजपा

## भावना विज-अरोड़ा

**ज**म्मू-कश्मीर, अब इस नाम से न तो पर्वतों, वादियों और कलकल करती पहाड़ी नदियों का एहसास होता है, न ही कश्मीरियत में डूबे सूफी

अध्यात्म का। वैसे तो यहाँ 1947 से ही परिस्थितियां कभी सामान्य नहीं रहीं, लेकिन तीन दशकों से सीमापार आतंकवाद, कफ्यू और अलगाववादी आंदोलन जैसी घटनाएं, दो केंद्र शासित प्रदेशों में बंट चुके इस राज्य की नई पहचान बन चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कभी अपने इस इरादे को नहीं छिपाया कि वह अनुच्छेद 370 को खत्म करना चाहती है, जिसके तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था। यह बात पार्टी के केंद्रीय एजेंडे में रही है और 2014 तथा 2019 के आम चुनाव के घोषणापत्रों में भी इसे शामिल किया था। 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 35ए और 370 को निष्प्रभावी बना कर एक तरह से भाजपा ने अपना वादा पूरा किया था।

एक साल से कश्मीर घाटी लॉकडाउन में है, हालांकि अब इसका एक कारण कोविड-19 महामारी भी है। मोबाइल फोन और इंटरनेट अब भी प्रतिबंधित हैं। जून 2018 तक भाजपा के साथ गठबंधन सरकार का हिस्सा रही पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अभी तक सार्वजनिक सुरक्षा कानून (पीएसए) के

तहत नजरबंद हैं। अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अबुल्ला और उमर अबुल्ला भी नजरबंद थे, उन्हें इस साल मार्च में रिहा किया गया। रिहाई के बाद से पिता-पुत्र सार्वजनिक रूप से ज्यादा नहीं बोल रहे। राम माधव जैसे भाजपा नेताओं ने यह कहकर उनका मजाक भी उड़ाया है कि ये लोग फेसबुक वॉल और ट्रिवर हैंडल के पीछे छिप गए हैं। (आगे पढ़िए राम माधव के साथ बातचीत)

भाजपा की पूर्व सहयोगी शिवसेना का कहना है कि 2016 की नोटबंदी की तरह अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने का मकसद भी अधूरा रह गया। सुरक्षा के नजरिए से हालात नहीं सुधरे हैं। शिवसेना ने अपने मुख्यपत्र सामना में लिखा है, “हर दिन सड़कों पर खून बह रहा है और निर्दोष लोगों की जान जा रही है।”

विशेषज्ञों के अनुसार अनुच्छेद 370 को

# सन्नाटे में दहकते सवाल

सरकार की नजर में स्थिति सामान्य, पर न नाकेबंदी हटी, न मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकार हुए बहाल



संगीनों के साथ में:

श्रीनगर में एक महिला  
को रोक कर पूछताछ  
करता सुरक्षाकर्मी



निष्प्रभावी बनाने से कश्मीर मुद्दे का अनावश्यक रूप से अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया, जिससे भारत तीन दशकों से बचता रहा था। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन ने चुनाव प्रचार में कश्मीरियों के अधिकारों को भी मुद्दा बनाया है। एक पूर्व विदेश सचिव ने कहा, “हमेशा भारत का समर्थन करने वाले ईरान ने पहली बार जम्मू-कश्मीर में भारत के रवैये की आलोचना की है। वह चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत को बाहर रखते हुए चीन के करीब जा रहा है। यह भारत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका असर कश्मीर के शिया मुसलमानों पर भी होगा।”

अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाना भी कोई अंतिम परिणाम नहीं है। 3 डी यानी डोमिसाइल, डिलिमिटेशन और डेमोग्राफिक्स के रूप में काम अभी जारी है। निष्प्रभावी लोग नए डोमिसाइल नियमों के खिलाफ हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह आबादी की संरचना बदलने का प्रयास है। अनुच्छेद 370 पर सरकार का समर्थन करने वाले जम्मूवासियों ने भी विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि अब सरकारी नौकरियां उनके लिए असंभवित नहीं हैं।

जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता वाला आयोग जम्मू-कश्मीर के साथ असम, नगालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन कर रहा है। इसे भी आबादी की संरचना में बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे संभवतः हिंदू बहुल जम्मू में भाजपा को फायदा होगा। परिसीमन पूरा होने के बाद ही इस केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होंगे। टिप्पणीकार प्रो. बद्री रैना जम्मू-कश्मीर में आबादी की संरचना में बदलाव को लेकर आश्वस्त हैं। वे कहते हैं,



**राजनीतिक पहल जरूरी:** फारस्क और उमर अब्दुल्ला तो रिहा, पर महबूबा मुफ्ती नजरबंद

“हिंदुत्वादी ताकतें हमेशा यह मानती रही हैं कि इस तरह का बदलाव ही समस्या का समाधान है। उन्हें लगता है कि परिसीमन से हिंदू विधायकों की संख्या बढ़ने पर अगली विधानसभा में हिंदू मुख्यमंत्री बनाया जा सकेगा।”

रणनीतिकारों और सुरक्षा विशेषज्ञों का मत है कि भारत के इस नए केंद्र शासित प्रदेश को राजनीतिक गतिविधियों से अब ज्यादा दिनों तक महरूम नहीं रखा जाना चाहिए। मौलिक और इंटरनेट जैसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर भी लंबे समय तक पाबंदी

उचित नहीं। विकास के लिए आर्थिक गतिविधियां (कोविड लॉकडाउन से इतर) शुरू करना जरूरी है। पर्यटन यहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और अनिश्चितता के कारण यहां पर्यटन के दो सीजन बर्बाद हो गए। सुरक्षा को देखते हुए निजी निवेशक यहां पैसा लगाने को तैयार नहीं हैं।

अनुच्छेद 370 निरस्त करने के बाद घाटी में हिंसक प्रदर्शन नहीं हुए। स्थानीय लोगों के अनुसार इसकी वजह संचार पर प्रतिबंध, मुख्यधारा के नेताओं की गिरफ्तारी और सुरक्षाबलों की बड़ी संख्या में तैनाती है। आरएसएस से जुड़े राजनीतिक विश्लेषक शेषाद्रिचारी ने आउटलुक से कहा, “पहले कोई अनुच्छेद 370 खत्म करने की बात करता था तो यह धमकी दी जाती थी कि देश जल उठेगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ।” चारी इसकी तुलना 2009 में मारे गए लिट्टे नेता प्रभाकरण से करते हैं। वे कहते हैं, “उसे तमिलनाडु के प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल था। माना जाता था कि उसे मारने पर न सिर्फ तमिलनाडु में सरकार गिर जाएगी, बल्कि लोग आत्मदाह करने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी तरह कश्मीर में 50 लोग भी प्रदर्शन के लिए नहीं निकले। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस धमकी देती थी कि अनुच्छेद 370 को छुआ गया तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। अब हुर्रियत कहाँ है ?”

पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के अनुसार विरोध प्रदर्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी किए जाने से कश्मीरी स्तब्ध रह गए और अपाराधिक महसूस करने लगे। सेंटर फॉर डायलॉग ऐंड रिकॉन्सिलिएशन की तरफ से सिन्हा कई बार घाटी का दौरा कर चुके हैं। वे बताते हैं, “अधिकारी बार में नवंबर में गया, तो एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने शांति या भारत की बात की हो। पहले ऐसा नहीं होता था। अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाए जाने से पहले लोगों में उम्मीद थी।”

रैना विरोध प्रदर्शन नहीं होने की एक और वजह बताते हैं। उन्होंने कहा, “मानसिक रूप से लोगों पर काफी बुरा असर हुआ है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि परिजनों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाकर रखना ही सबसे अच्छा है।” रैना के अनुसार अनुच्छेद 370 को लेकर जम्मू-कश्मीर के दो प्रमुख दलों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के हित ज्यादा थे। इनके नेताओं को हिरासत में लेकर केंद्र ने आश्वस्त किया कि उनका जनाधार कोई चुनावी न बने। अंतरिक मतभेद से ग्रस्त हुर्रियत की प्रतिबद्धता इस अनुच्छेद को लेकर उतनी नहीं थी। ज्यादातर हुर्रियत नेताओं का मत था कि जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। जहां तक आम लोगों के विरोध की बात है, तो बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती से वे इन डरे हुए थे कि विरोध की बात सोच भी नहीं सकते थे।

पीटीआइ



रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के पूर्व विशेष सचिव आनंद अर्नो मानते हैं कि इस तरह के बल प्रयोग से हिंसा कम हो सकती है, लेकिन यह रणनीति लंबे समय में काम नहीं करेगी। उन्होंने कहा, “लोकतंत्र में यह संभव नहीं, इसकी निंदा की जानी चाहिए। लोगों को ताजी हवा में जाने की इजाजत दी जानी चाहिए। यह एक तरह का सेफटी वाल्ट भी है, वरना पाकिस्तान के लिए हालात का इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा।”

पूर्व रॉ प्रमुख और कश्मीर मामलों में दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सलाहकार रहे ए.एस. दुल्लत मानते हैं कि हिंसक प्रतिक्रिया इसलिए नहीं हुई कि आम कश्मीरी अमन पसंद हैं और सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। उन्होंने कहा, “मैंने भी कुछ लोगों को यह कहते सुना कि वहां लावा धधक रहा है जो फूटेगा, पर मैं ऐसा नहीं मानता। कश्मीरी बिना 370 के भी जी सकते हैं। अगर सरकार बात करे तो पाकिस्तान भी इसे स्वीकार कर लेगा।”

दुल्लत मानते हैं कि राजनीतिक प्रक्रिया यथाशीघ्र शुरू की जानी चाहिए। वे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव की तरह कदम उठाने की बात कहते हैं। राव ने छह साल तक राष्ट्रपति शासन के बाद 1996 में जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने का ऐलान किया था। दुल्लत के अनुसार, “राव का तरीका सबसे अच्छा था। कश्मीर को इसी की दरकार है। चाहे कोई एक पार्टी सत्ता में आए या त्रिशंकु विधानसभा हो, यह तय करने का अधिकार लोगों को दीजिए।”

दुल्लत के मुताबिक सरकार सुरक्षा को ज्यादा तबज्जों दे रही है, जबकि बड़ी समस्या लोगों की है। सुरक्षा का पहलू उत्तर कश्मीर में ज्यादा अहम है जहां विदेशी आतंकवादी घुसपैठ करते हैं। दक्षिण

कश्मीर में आतंकवाद मुख्य रूप से स्थानीय युवाओं से जुड़ा है जो भविष्य को लेकर उनकी निराशा से उपजा है। दुल्लत के अनुसार स्थानीय पुलिस को इन युवाओं को मारने के बजाय उन्हें समझाना चाहिए। उन्होंने कहा, “उत्तर कश्मीर में किसी को बच्चा नहीं जाना चाहिए, लेकिन बंदूक उठाने वाले स्थानीय युवकों को मारने से कुछ हासिल नहीं होगा। आप एक को मारेंगे तो गुस्से में चार और खड़े होंगे और फिर वे भी मारे जाएंगे। 1990 के दशक में आतंकवादियों का जीवनकाल दो से ढाई साल होता था, अब यह दो-तीन महीने रह गया है। मुझे डर है कि श्रीनगर उत्तर और दक्षिण कश्मीर के बीच फंस सकता है और वहां कोई बढ़ी आतंकी वारदात हो सकती है।”

जम्मू-कश्मीर में हिंसा बढ़ने को लेकर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी भी सशक्तिकृत हैं। वे कहते हैं, “आतंकवाद के तीन चरण होते हैं— अलगाव, उत्प्रवादी विचार और हिंसा। हाल के दिनों में अलगाव बढ़ा ही है। जम्मू में भी असंतोष की ध्वनि सुनाई देने लगी है। सुरक्षा के लिहाज से हालात शायद ही बेहतर हुए हैं।” तिवारी के अनुसार किसी इलाके को कर्फ्यू में रखकर हालात सुधारने का दावा नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि निजी निवेशक वहां उद्योग स्थापित करने को तैयार नहीं।

**कश्मीर में कब लौटेगा लोकतंत्रः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह**

वे अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री डोनाल्ड रम्सफील्ड की बात दोहराते हैं कि पैसा डरपोक होता है और यह सबसे सुरक्षित जगह ही जाना चाहता है। पूर्व वित्त मंत्री सिन्हा भी मानते हैं कि कोई निवेशक तभी पैसे लगाएगा जब स्थिति सामान्य हो, जबकि हालात इससे कोसों दूर हैं। वहां तो पहले से तय निवेशक सम्मेलन भी नहीं हो सका। नई परियोजनाओं की बात दूर, पीएम डेवलपमेंट पैकेज के तहत घोषित परियोजनाओं की गति भी काफी धीमी है। प्रधानमंत्री ने 2015 में 58,627 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी, इसमें से 49 फीसदी राशि का ही इस्तेमाल हुआ है। कुल 54 प्रोजेक्ट में से नौ पूरी हुई हैं और आठ पूरी होने के करीब हैं।

रैना खुद कश्मीरी पंडित हैं। उन्हें नहीं लगता कि उनके समुदाय के लोग अभी वापस जाएंगे, क्योंकि वे जिस तरह की सुरक्षा चाहते हैं वह सरकार मुहैया नहीं करा सकती। ज्यादातर लोग अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी बनाए जाने को स्थायी मानते हैं, लेकिन मनीष तिवारी को ऐसा नहीं लगता। उनके मुताबिक यह अब भी विचाराधीन है। कई बातें स्पष्ट होनी हैं। जैसे, संविधान में दो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक हाइकोर्ट का प्रावधान नहीं है। हालांकि जम्मू-कश्मीर को पुनः राज्य का दर्जा मिलने की संभावना काफी ज्यादा है। भाजपा महासचिव राम माधव ने भी आउटलुक से बातचीत में यह बात कही।



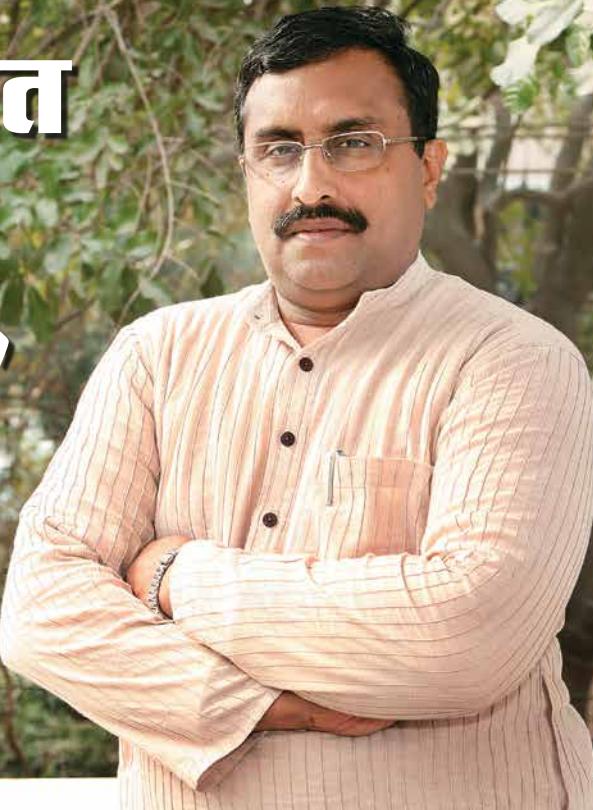
**बंदूक उठाने वाले स्थानीय युवकों को मारने से कुछ हासिल नहीं होगा, आप एक को मारेंगे तो गुस्से में चार और खड़े होंगे और फिर वे भी मारे जाएंगे।**

**ए.एस. दुल्लत**  
पूर्व रॉ प्रमुख

बात करने में भी कोई हर्ज नहीं है। सिन्हा भी मानते हैं कि बातचीत ही एकमात्र समाधान है। सरकार सभी पक्षकारों की पहचान करे और उनसे वार्ता के लिए किसी को साधिकार नियुक्त करे। हालांकि रैना के अनुसार जब तक कुछ बुनियादी मुद्दों पर खुले और लोकतांत्रिक तरीके से विचार नहीं होता, तब तक समाधान मुश्किल है।



# “अनुच्छेद 370 हटने से भारत की आवाज मजबूत हुई”



जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35ए के जरिए हासिल विशेष दर्जा को गंवाए लगभग साल भर हो गया। हालांकि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने भावना विज-अरोड़ा से बातचीत में कहा कि अनुच्छेद 370 निरस्त होने से सबसे नए केंद्र शासित प्रदेश में “भारत की आवाज मजबूत” हुई है। इससे स्थानीय नेताओं की असलियत भी सामने आ गई है, जो जनता और प्रशासन के बीच पुल बनने का काम करने के बजाय अपनी फेसबुक वॉल और टिकटर हैंडल में कुछ हुए हैं। बकौल उनके, “यही वजह है कि जब उन्हें नजरबंद किया गया तो आसु बहाने वाले कम ही थे।” प्रमुख अंश:

**अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जे की समाप्ति के साल भर बाद जम्मू-कश्मीर के हालात का वर्णन कैसे करेंगे?**

एक साल पहले, 5 अगस्त 2019 को जब हमारी सरकार ने अनुच्छेद 370 को बेमानी बनाया था तो विषय ने राज्य में खून-खराबा और सड़कों पर हिंसा

की आरंका जताई थी। लेकिन पिछले ग्यारह महीनों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आतंकी हिंसा जरूर हुई लेकिन इन घटनाओं के अलग पहलू हैं और उनके अलग तरह से विश्लेषण की जरूरत है। यूटी में प्रशासन के पास विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पर्याप्त शांति है।

आपको लगता है, हमने देश के बाकी हिस्सों के साथ जम्मू-कश्मीर को मुख्यधारा में लाने के घोषित लक्ष्य की दिशा में कुछ प्रगति की है?

हमें मुख्यधारा जैसे शब्दों के इस्तेमाल में थोड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत है क्योंकि इसका मतलब है कि वहां के लोग भारत के साथ नहीं थे। ऐसी ही धारणा के कारण दिल्ली के प्राइम टाइम टीवी कार्यक्रमों में आम कश्मीरी रोज अपनी देशभक्ति की परीक्षा देते हैं। कश्मीर घाटी में आबादी का एक वर्ग ऐसा है, जो अलगाववादियों के बयानों से प्रभावित है, लेकिन जम्मू के लोग और कश्मीर की आबादी का एक बड़ा हिस्सा दशकों से राष्ट्रीय मुख्यधारा के साथ है। विशेष दर्जे के मामले में घाटी में अनुच्छेद 370 के

प्रति लगाव था, लेकिन जम्मू में ऐसा नहीं था। सात दशक तक अनुच्छेद 370 के साथ रहने वाले सामान्य कश्मीरी, जिन्हें इससे कुछ नहीं मिला, अब शायद इसके बिना जीवन का अनुभव करना चाहते हैं। यही वजह है कि वे लोग सड़कों पर नहीं उतरे और उन्होंने पत्थर नहीं फेंके। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से केंद्र शासित प्रदेश में भारत की आवाज मजबूत हुई है।

केंद्र शासित प्रदेश में उद्योगों ने निवेश करने में रुचि दिखाई है? आप निजी निवेश के बारे में आश्वस्त हैं?

पिछले साल अगस्त के फैसले के बाद सर्दियां शुरू हो गई थीं। सर्दियां खत्म होते ही कोविड महामारी आ गई। इन प्राकृतिक चुनौतियों के अलावा, नए केंद्र शासित प्रदेश में नए डोमिसाइल कानून जैसे मुद्दे थे, जिनकी घोषणा होने में कुछ समय लगा। मॉल और मल्टीप्लेक्स में कुछ निवेश पहले ही आ चुके हैं। राज्य में एक इन्वेस्टर मीट की योजना बन रही है, जिससे निवेश का रास्ता खुलेगा।

**अनुच्छेद 370 बेमानी होने के बाद राज्य**

में अलगाववाद के मामले में कोई असर पड़ा है? हाल ही में आतंकवादी हमले में भाजपा के शीर्ष कार्यकर्ता और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या को आप कैसे देखते हैं?

अनुच्छेद 370 के बेमानी होने से सीमा पर के आतंकवादी और उनके आका बहुत हताश हैं। वे लगातार राज्य में अधिक से अधिक आतंकवादियों की घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे सुरक्षा बल सतर्क हैं। वे सीमा पर या उनके ठिकानों पर उन्हें बेअसर कर दे रहे हैं। एक भी सप्ताह ऐसा नहीं गुजरता कि बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सफाया न हुआ हो। दूसरी ओर आतंकवादी ऐंकों में स्थानीय भर्ती काफी कम हो गई है। हाई-प्रोफाइल वारदात में कामयाबी हासिल न हो पाने की हताशा में आतंकवादियों ने स्थानीय स्तर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया है। कुछ को तो हाल ही में निशाना बनाया गया है। हालांकि, राज्य में सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। हमने अपने काडर को बताया है कि घबराने की नहीं, सावधान रहने की जरूरत है।

इससे पहले एक कांग्रेस सरपंच अजय पंडिता की हत्या कर दी गई थी और एक अन्य महिला सरपंच का अपहरण कर लिया गया था। क्या आपको लगता है कि इसका मकसद कश्मीरी पंडितों को घाटी से दूर रखना है?

उन्हें घाटी में हमेशा ही भारत के साथ खड़े होने या राष्ट्रीय झंडे को उठाने की चुनौतियां झेलनी पड़ी हैं। पंडितों ने इसकी भारी कीमत चुकाई है। भाजपा नेता वसीम बारी के परिवार जैसे कई स्थानीय कश्मीरियों ने भी अपनी जान की बाजी लगा दी। बड़ी संख्या में पंडितों को घाटी छोड़नी पड़ी थी। घाटी उनका घर है और यहां लौटने का उन्हें अधिकार है। आतंकवादी उस अधिकार को नकारने के लिए हर तरकीब अपनाएं, लेकिन हम भी उन्हें सम्मान, सुरक्षा के साथ वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी तरह, हम उन सभी कश्मीरियों की सुरक्षा आश्वस्त करेंगे जो भारत के लिए खड़े हैं। घाटी में हम हर दिन आतंकवादियों को बेअसर कर रहे हैं। अब घाटी में किसी आतंकवादी का जीवन कुछ ही महीनों का है।

घाटी की अपनी हालिया यात्रा के दौरान, आपने कहा कि नेशनल कॉर्नेस और पीडीपी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं। आपकी राय में इस समय उनकी क्या भूमिका है?

केंद्र शासित प्रदेश में जब राज्यपाल का शासन होता है, तो लोगों को नेताओं की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि केवल वे ही लोगों और प्रशासन के बीच पुल का काम कर सकते हैं। सभी राजनीतिक दलों के लगभग सभी नेता नजरबंदी से बाहर हैं, लेकिन वे लोगों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। लोगों को सरकारी कार्यक्रमों का लाभ दिलाने के लिए वे वहां नहीं हैं। आतंकवादी राजनीतिक

कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, वे वहां भी गायब हैं। राज्य ने पिछले दो वर्षों में पंचायत स्तर के कई चुनाव देखे हैं। स्थानीय दलों ने उनका बहिष्कार किया और भाग गए। क्यों? ये लोग आम लोगों को पूरी तरह अस्वीकार्य हैं। ये लोग अपनी फेसबुक वाले और टिव्हिटर हैंडल के पीछे छुपे हुए हैं। जनता भी यह बात समझ रही है। यही वजह है कि जब ये लोग नजरबंद हुए तो किसी ने आंसू नहीं बहाए।

**चुनावों के संदर्भ में स्थिति कब सामान्य होगी? परिसीमन कब तक हो पाएगा?**

छिप्पुट पाकिस्तानी शह से आतंकी वारदातों को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेश में शांति है। जहां तक केंद्र शासित प्रदेश में विधायिका की सामान्य स्थिति बहाली की बात है, तो मुझे यकीन है कि यह प्राथमिकता पर होगा। नए यूटी अधिनियम के तहत, परिसीमन का काम केंद्र शासित विधानमंडल के चुनावों में जने से पहले पूरा होगा। न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने इसके लिए एक आयोग नियुक्त किया है। कांविड की वजह से प्रक्रिया में देरी हुई है। एक बार शुरू होने के बाद, मुझे लगता है कि यह कुछ

## “बहुसंख्यक कश्मीरियों को सात दशकों में अनुच्छेद 370 से कुछ हासिल नहीं हुआ, यही वजह है कि कोई हिस्क विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिला”

महीनों में पूरी हो जाएगी। उम्मीद है, प्रक्रिया जल्द पूरी होगी और चुनाव होंगे।

क्या यह सच है कि अधिकांश नेताओं को एक बॉन्ड भरने की शर्त पर रिहा किया गया है कि वे अनुच्छेद 370 पर नहीं बोलेंग? क्या यही वजह है कि पीड़ीपी नेता महबूबा मुफ्ती अब भी नजरबंद हैं?

जहां तक मैं जानता हूं, यह कोरी बकवास है। वास्तव में इससे हिरासत में लिए गए नेताओं की साख पर सवाल खड़े होते हैं। तमाम राजनीतिक मतभेदों के बावजूद मैं इन दलों के कई नेताओं की निष्ठा असंदिग्ध मानता हूं और इसलिए इस आरोप को खारिज करता हूं।

क्या जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा फिर बहाल करने की कोई संभावना है?

केंद्रीय गृह मंत्री की घोषणा के अनुसार, यह केंद्र शासित प्रदेश के लिए आगे का रास्ता होगा। उचित

समय पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

जम्मू-कश्मीर में कुछ हलाकों में जनसंख्यागत परिवर्तन की आशंका व्यक्त की जा रही है। यहां तक कि अल्लाफ बुखारी की ‘अपनी पार्टी’ भी डोमिसाइल कानून पर चिंता व्यक्त कर चुकी है। ऐसी चिंताएं जायज हैं?

ये सभी बातें भ्रामक हैं। नए डोमिसाइल कानून के तहत, राज्य सरकारों द्वारा क्रमिक रूप से की गई ऐतिहासिक गलती को सुधारा गया है और दशकों से घाटी में रहने वाले वास्तविक भारतीय नागरिकों को डोमिसाइल दर्जा दिया गया है।

जम्मू में एक बड़े तबके को लगता है कि अनुच्छेद 370 को बेमानी करने के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। जाहिर तौर पर जम्मू के लोग स्थिति से खुश नहीं हैं। जम्मू को अलग राज्य बनाने की कोई योजना?

जम्मू के लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि अनुच्छेद 370 निरस्त हो। वे इसे हासिल कर खुश हैं। जम्मू को पिछले कुछ वर्षों में विकास की कई परियोजनाएं परिलिपि। लेकिन यह भी सच है कि घाटी में जो कुछ होता है उसकी कीमत जम्मू के लोग चुकाते रहते हैं। दशकों से, प्रशासन को केवल घाटी के नजरिए से राज्य को देखने की आदत थी। यूटी एक ही इकाई है, इसलिए प्रशासन को ऐसा करने के नायाब तरीके विकसित करने होंगे।

कई विशेषज्ञ एलएसी पर चीन के आक्रामक तेवर को अनुच्छेद 370 के बेमानी होने और लदाख को अलग केंद्रशासित राज्य बनाने से जोड़ते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं?

एलएसी पर चीन की कार्रवाई की कई तरह की व्याख्याएं हैं। हम सभी विशेषज्ञों और उनकी राय का सम्मान करते हैं। लेकिन चीन ने अतीत में भी कई बार ऐसा ही किया है, विशेष रूप से 2013 में। उस समय यूटी का कोई प्रश्न नहीं था।

हुरियत कॉर्नेस के अपने धड़े से सैयद अली गिलानी के इस्तीके के बारे में सबसे पहले आपने ट्वीट किया। यह कितना बड़ा घटनाक्रम है?

गिलानी का इस्तीफा आंतरिक टकराव और पाकिस्तान की बदली प्राथमिकताओं का नीतीजा था। वे घाटी के हजारों युवाओं को आतंकवाद के रास्ते पर ले गए। उन्होंने हजारों निर्दोष कश्मीरियों के हजारों परिवारों को नष्ट कर दिया। हुरियत के कट्टरपंथी नेता के रूप में वे पाकिस्तान की सरपरस्ती का आनंद उठाते रहे। उनका इस्तीफा आज क्या उन सभी भयावह अपराधों को कम कर सकता है, जो उन्होंने इन दशकों में किए और जिसकी वजह से कश्मीरी लोग पीड़ित हुए?

क्या हुरियत अब भी प्रासंगिक है?

बहुत पहले हुरियत अपनी प्रासंगिकता खो चुका है। यह समय है कि कश्मीर के लोग उन्हें छोड़ कर आगे बढ़ जाएं।

**NURTURING  
FUTURE  
LEADERS**

**18  
FACULTIES**

**170+  
COURSES**

**360°  
HOLISTIC  
DEVELOPMENT**

[www.sgtuniversity.ac.in](http://www.sgtuniversity.ac.in)

**1800 102 5661**

## **SGT ADVANTAGES**

- Industry oriented multi-disciplinary research and Project Based Learning.
- Student fraternity from all regions of India ensuring cultural diversity for a vibrant campus life.
- Industry oriented and student centric teaching methodology to make students future ready.
- Student exchange programmes with Top International Universities.
- Multiple academic and extra-curricular clubs for holistic development of the students.
- Interpersonal skills enhancement sessions.
- Lush green, well equipped 70 acres campus.
- Full support and guidance to avail education loan.
- Industry oriented innovation curriculum.
- Regular Internship and Placement fairs.

- 70 ACRE POLLUTION FREE, SELF-SUSTAINED CAMPUS
- 17 YEARS OF LEGACY IN EDUCATION
- EXPRESSWAY CONNECTIVITY FROM AIRPORT

**Holistic Development through  
Experiential Learning**



Top Emerging B-School  
in India #3 - Times of India



Best Private University  
in Haryana by - Jagran Josh

UPTO  
**100%**  
SCHOLARSHIP



**SGT UNIVERSITY**  
SHREE GURU GOBIND SINGH TRICENTENARY UNIVERSITY  
(UGC & AICTE Approved) Gurugram, Delhi-NCR

**QS I-GRAUGE**  
INDIAN COLLEGE & UNIVERSITY RATING  
**GOLD**



# करिअर विकल्प के रूप में लॉ की प्रतिष्ठा बढ़ी है

वै

श्वीकरण ने शिक्षा प्रदान करने के पारम्परिक तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। सरहदें मिट्टने के कारण करियर विकल्प के क्षेत्रों में मैं भी आमूलचूल परिवर्तन आया है। लॉ, अर्थात् क्रानून की पढ़ाई, भी इससे अछूता नहीं रहा है। युवा अधिवक्ता क्रानून के पेशे के बदलते परिवृश्य और इसके द्वारा प्रदान किये जा रहे असीम संभावनाओं की एक झलक प्रदान करते हैं।

क्रानून के मूल सार और इसकी सामाजिक कर्तव्य को परिभाषित करते हुए डीन, लॉ संकाय, एसजीटी विश्वविद्यालय कहते हैं कि लॉ आमतौर पर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ी जा रही क्रानूनी लड़ाइयों के व्यापक परिणामों के कारण चर्चित रहकर सबों का ध्यान आकृष्ट करता है। बोर्डरलम से लेकर घर और आसपड़ोस तक मैं मुद्दों पर बहस और चर्चा की जाती है। समाज के हर तबके को इसका बेसब्री से इंतजार रहता है कि क्रानून कैसे अपना काम करते हुए किसी ऐसे निर्णय पर पहुंचेगा जो न्यायोचित हो।

निरंतर बदलते क्रानून की पढ़ाई और इससे बढ़ते अवसरों पर प्रकाश डालते सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड इष्टित सहारिया कहते हैं, "पिछले कुछ वर्षों में हमने लॉ स्कूलों का विकास देखा है। अब वह दौर गुजर गया जब क्रानून के विद्यार्थीयों के पास सिर्फ अधिवक्ता या न्यायाधीश बनने के विकल्प थे। आजकल, देश में लगभग हर लॉ कॉलेज समय की मांग के अनुसार विशेष पाठ्यक्रम पेश कर रहे हैं। विद्यार्थियों को विगत में ऐसे कोर्स पढ़ने के लिए विदेश जाना पड़ता था, लेकिन अब देशभर में अनेक नेशनल लॉ कॉलेज और यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज स्थापित हो गए हैं, जहाँ से न केवल भविष्य के अच्छे वकील और न्यायाधीश पढ़कर आ रहे हैं, बल्कि जहाँ ऐसा वातावरण है जो कॉर्पोरेट जगत में नेतृत्व प्रधान करने के भी उपयुक्त और आवश्यक है।

तकनीक की मदद से क्रानून की शिक्षा



प्रदान करने की कार्यप्रणाली में आये बदलाव के सम्बन्ध वह कहते हैं, "तकनीक की तरह क्रानून भी बदल रहा है। देश में सभी लॉ कॉलेज छात्रों को प्रशिक्षित करने और उन्हें मूट कोर्ट (वाद-विवाद कोर्ट) और इंटर्नशिप द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों से सम्बंधित सैद्धांतिक और व्यावहारिक (प्रैक्टिकल) ज्ञान प्रदान करने में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। इसमें शक नहीं कि लॉ एक चुनौतीपूर्ण और कठिन पेशा है। आज की प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में लॉ कॉलेजों के समक्ष शिक्षा की गुणवत्ता और उद्दीयमान अधिवक्ताओं को प्राप्त हो रहे अनुभवों को अद्यतन रखने की ओर भी बड़ी जिम्मेदारी है।

एडवोकेट श्रेया सिन्हा के अनुसार, क्रानून की शिक्षा और पेशे की खूबसूरती यह है कि ये अवसरों के कई द्वारा खोलते हैं। "आप या तो किसी लॉ संस्थान में आरामदायक नौकरी कर सकते हैं या स्वयं स्वतंत्र रूप से अधिवक्ता के रूप के में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावे आप समाज में उत्थान के लिए रिसर्च कर कर सकते हैं या प्रतिरक्षा सेवाओं में जज एडवोकेट-जनरल जैसे प्रतिष्ठित पद पा सकते हैं। इसका क्षेत्र अनंत है क्योंकि समाज और क्रानून के बीच अन्योनाशक्ति सम्बन्ध है।

सुकन्या बासु, वरीय अधिवक्ता (लिटिगेशन), फॉक्स मंडल एंड कंपनी, कहती हैं, "पिछले कुछ दशकों में भारत में क्रानूनी शिक्षा के स्वरूप में बड़ा बदलाव आया है। पहले, यह समाज की खास तबके के लोगों का विशेषाधिकार था लेकिन क्रानून के क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास आने और

बार कौसिल ऑफ इंडिया के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के बार कौसिलों की पहल से, भारत में क्रानूनी शिक्षा ने नई उचाईयों को छू लिया है और यह सबों के लिए उपलब्ध है। देशभर में बार कौसिल ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृत 1616 लॉ कॉलेज क्रानूनी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं जिनमें नेशनल लॉ स्कूलों के अतिरिक्त निजी संस्थान भी शामिल हैं। यहाँ तीन और पांच वर्षों के स्नातक और विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है। क्रानून की शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर की चुनौती के मद्देनजर, लॉ कमीशन ऑफ इंडियन ने अपनी 266वीं रिपोर्ट में अधिक से अधिक छात्रों को इस पेशे को चुनने के लिए प्रेरित करने लिए बेहतर शिक्षण और पुस्तकालय सुविधाएँ प्रदान कर लॉ कॉलेजों के उन्नयन पर बल दिया है।

भारत में लॉ के क्षेत्र में उपलब्ध करियर अवसरों में काफी वृद्धि हुई है और भारत के अधिवक्ताओं को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है और वे वहाँ कार्य करने के लिए आमंत्रित किये जाते हैं। यहाँ के बहुत वकील कई विदेशों कंपनियों के लिए वहाँ कार्यरत हैं। भारत में कुछ सबसे ज्यादा तेज क्रानूनी प्रतिभाओं का पोषण हो रहा है, जिसकी बदलत दुनियाभर में भारत की ख्याति क्रानूनी शिक्षा प्रदान करने वाले एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में कई गुना बढ़ी है।

आज के दौर में, करियर और पेशे के रूप में लॉ ने बहुत प्रगति की है और ऐसे अभ्यर्थियों जो न्याय के क्षेत्र में कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं, को नए अवसरों की प्रचुरता प्रदान की है।



# THE LEADER OF LAW EDUCATION

## FOR LAST 17 YEARS...

### ASSOCIATIONS/ COLLABORATIONS

Knowledge Exchange



Internships



Memberships

GOODMAN DERRICK LLP

CHANGARTH CHAMBERS LLC



International Association of Law Schools



Supporting Partners



Knowledge Institutes

Associations Over the Years



Singhania & Co.  
Solicitors and Advocates

SCC  
ONLINE

EBC

LexisNexis

manupatra®  
Power Your Legal Research

Live  
Law.in

Lawctopus

L.R.



Rank No. 1 Private Law College of MP, CG & RAJASTHAN



INDORE INSTITUTE OF LAW™

(Affiliated to DAVV & Bar Council of India, New Delhi)

Campus : "Gendal Bam Parisar", Opp. IIM, Rau-Pithampur Road, Indore (M.P.)  
City Office : 425-426 Orbit Mall, A.B. Road, Indore (M.P.) 452 010

CALL: 99770 19777, 99770 91777

### PATRON

Dr. Faizan Mustafa

Vice Chancellor,  
NALSAR Hyderabad



### ADVISORY BOARD



Dr. Balraj Singh  
Chouhan  
Vice Chancellor  
DNLU Jabalpur



Dr. Subir K  
Bhattacharya  
Vice Chancellor  
RMLNU Lucknow



Dr. S. Shantha Kumar  
Vice Chancellor  
GNLU Gandhinagar



Dr. V.C. Vivekandran  
Vice Chancellor  
HNLU Raipur



Dr. Yogesh Pratap  
Singh  
Registrar  
NLU Odisha

IILET

Indore Institute of  
Law Entrance Test on

20<sup>th</sup> May, 2020

### COURSES OFFERED

- **B.B.A.LL.B. (Hons.)**  
5 YDC With Global &  
Transnational Studies
- **B.A.LL.B. (Hons.)**  
5 YDC

WE CREATE  
Professionals  
NOT GRADUATES



# हिंदी पट्टी का रक्त-चरित्र

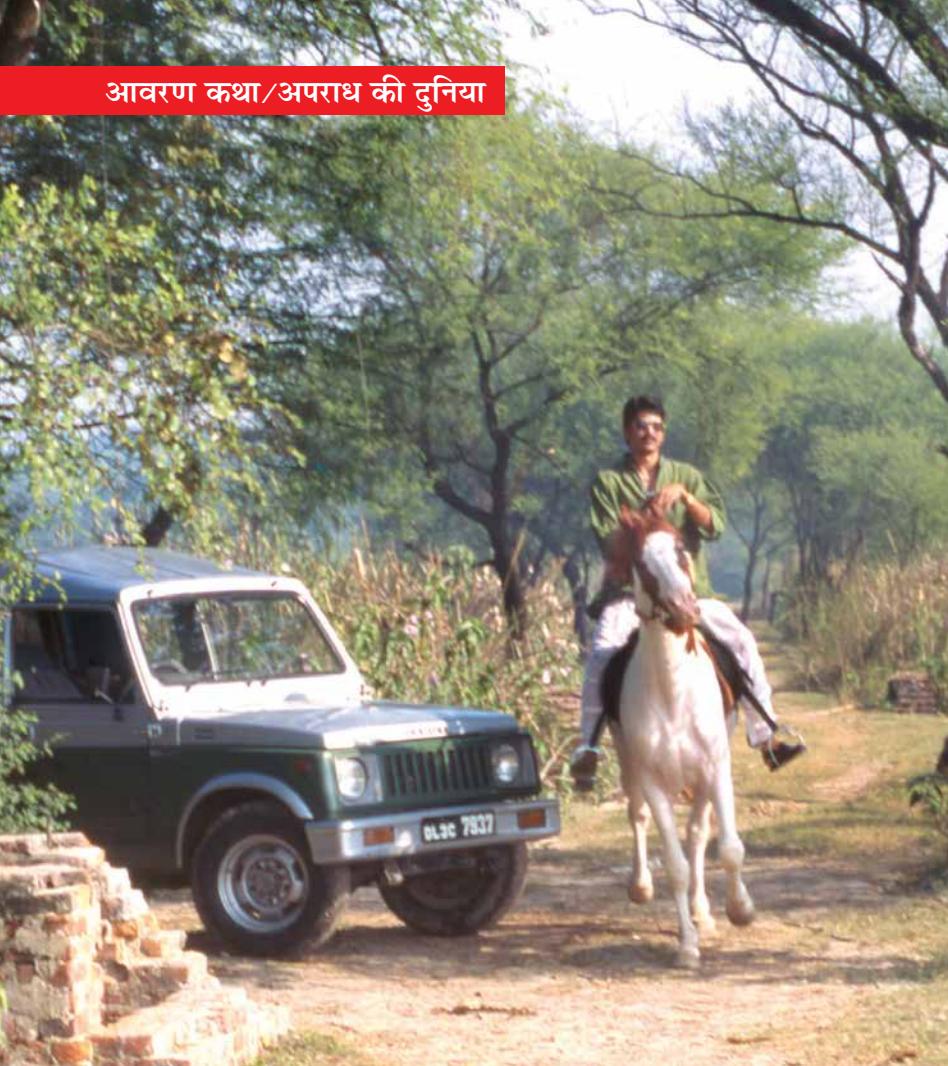
हिंदी प्रदेशों और खासकर सियासी तौर पर सबसे अहम उत्तर प्रदेश के सामाजिक-राजनैतिक तानेबाने में पिरोयी जैंगरटर और बाहुबली संस्कृति पिछले चार दशकों में राजनीति के तौर-तरीकों का नतीजा



**सवाल ही सवाल:** उज्जैन में पूरे नाटकीय अंदाज में विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में

### सलीक अहमद

**य**कीनन अपने रंग-ढंग और सामाजिक परिस्थितियों में पुराने दौर के बागी डॉकैतों और आज के गैंगस्टर या डॉन वगैरह का चाल, चरित्र सब कुछ एकदम अलग है। लेकिन दोनों की जुबान पर आज भी वही गर्व से फबता है, जो सबसे लोकप्रिय फिल्मी डॉकैत की बोली से गूंजा था: “कितना इनाम रखा है सरकार हम पर?” ठहाके गूंजते हैं, “पूरे 50 हजार, सरदार!” असल में खौफजदा करने वाला यही ठहाका हर डॉकैत या गैंगस्टर की पूँजी होती है, जो उसके बारे में किंवदंती की तरह चारों ओर छाई रहती है। लोगों के बीच छाए इसी खौफ की बनिस्बत वह अपनी आपराधिक दुनिया को फैलाता है और अपना दबदबा कायम करता है। सिनेमाई कहानियां भी एकदम मनगढ़ित नहीं होतीं। वे उसी के इर्दगिर्द बुनी होती हैं, जो निपट असली आपराधिक दुनिया और उसके बारे में प्रचलित किंवदंतियों के बीच पुल जैसी बिछी रहती हैं। असली दुनिया में आज के गैंगस्टरों का रंग-ढंग परदे के खूंखार से दिखने वाले पात्रों से एकदम अलग है लेकिन वे भी अपनी उसी पूँजी के सहारे होते हैं और खौफजदा करने की उसी शैली पर फख्त करते हैं, जो निपट पुरानी है। इसी से उनके अवैध कारोबार के दरवाजे खुलते हैं। उनका रहन-सहन, उनकी आकांक्षाएं, उनकी दुनियावी सोच-समझ, उनके तौर-तरीके चाहे



जितेंद्र गुप्ता

जितनी विरुद्धा पैदा करें, मगर उसकी बारिकियां दिलचस्प हैं और उनसे राजनीतिक-समाजिक हकीकत को जानने-समझने में मदद मिलती है।

पहले हाल ही में एक सवालिया पुलिस मुठभेड़ में मारा गया विकास दुबे का जिक्र जरूरी है, जिससे राजनीति, समाज और पुलिस तथा सरकारी तंत्र के स्थाह पक्ष का खुलासा होता है। विंडबना देखिए कि अपराध-मृत राज्य बनाने के बाद पर अपराधियों के सफाए के लिए “ठोक दो” कहकर पुलिस को हरी झंडी देने के बावजूद यह सिलसिला जारी है।

खैर, गैंगस्टर इतने दुर्दात कैसे बन जाते हैं, यह जानने के लिए कुछ पुरानी फाइलें पलटते हैं। उत्तर प्रदेश में 1990 के दशक में लखनऊ में गैंगस्टर श्रीप्रकाश शुक्ला की कहानी इस दुनिया की तसवीर दिखाती है। शुक्ला अपने आपको ‘बड़ा बाबू’ कहता था और अपने साथ हमेशा एक बैग रखता था। वह कहता था कि उसके बैग में ऑफिस का सामान है। असल में शुक्ला जिस सामान की बात करता था, वह एक-47 राइफल थी।

इसी तरह 70 और 80 के दशक में चंबल के बीहड़ों में छबीराम बांगी या डैकेत का खोफ था। इटावा, मैनपुरी और फिरोजाबाद में उसके नाम का

**दबदबा:** राजा भैया अपराधी और राजनीति के गठजोड़ वाले तंत्र की नई पीढ़ी हैं

आतंक हुआ करता था। उसकी एक पुलिस अफसर का अपहरण करने की कहानी काफी चर्चित है। उसने पुलिस अफसर को तब तक बंधक बनाकर रखा, जब तक अफसर की पत्नी सारे गहने लेकर उसके पास नहीं पहुंची। लेकिन कहानी यहीं पर दिलचस्प मोड़ लेती है। पुलिस अफसर की पत्नी ने डैकेत को गहने देते वक्त ‘भैया’ कहकर पुकारा। यह संबोधन सुनते ही डैकेत का दिल पसीज गया और उसने सारे गहने लौटा दिए। भले ही छबीराम की कहानी पूरी फिल्मी लगती हो, लेकिन प्रतापगढ़ के माफिया राजा भैया की कहानी कुछ कम नहीं है। उन पर आरोप लगता रहा है कि वह अपने दुश्मनों को तालाब में पाले गए घड़ियालों का भोजन बना देते थे।

भले ही मुंबई का अंडरवल्ड कमाई के मामले में ज्यादा ताकतवर है और उसे मीडिया में ज्यादा सुर्खियां मिलती हैं, लेकिन हिंदी पट्टी के ये देसी गैंगस्टर अपने क्षेत्र में रसूख और आतंक में किसी से कम नहीं। कानून के रखवालों और गैंगस्टरों के बीच कानून की दीवार इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि आए



**गोरखपुर के माफिया डॉन हरिशंकर तिवारी 23 साल तक विधायक रहे हैं। इस दौरान उन्हें भाजपा, सपा, बसपा सभी राजनीतिक दलों का साथ मिला**

दिन इनके आतंक की दास्तां सामने आती रहती है। ताजा मामला कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे का है। उसने अपने बिकरू गांव में 2-3 जुलाई की दरम्यानी रात को छापा मारने गई पुलिस टीम के आठ लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसमें शामिल विकास दुबे के एक साथी को बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसने बताया कि विकास दुबे को पुलिस के ही एक मुख्यबिर ने सूचना दी थी कि उसे पकड़ने के लिए पुलिस छापा मारने वाली है। वारदात स्थल पर कितनी राठंड गोलियां चली थीं, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि वारदात के बाद आठ दिनों तक गोलियों के खोखे मिलते रहे। हालांकि बाद में विकास दुबे और उसके चार साथियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया।

बिकरू गांव हत्याकांड के बाद से फरार विकास दुबे न केवल पुलिस के निशाने पर रहा, बल्कि मीडिया ने भी उसकी कवरेज का कोई मौका नहीं छोड़ा था। हालांकि उसके एनकाउंटर की कहानी जरूर भरोसेमंद नहीं लगती। पुलिस के अनुसार उसकी गिरफ्तारी सातवें दिन मध्य प्रदेश के उज्जैन से की गई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस उसे कानपुर लेकर आ रही थी। कानपुर से कुछ दूर पहले, तेज

बारिश में पुलिस की गाड़ी पलट गई और मौके का फायदा उठाते हुए दुबे ने पुलिस अधिकारी का हथियार छीनकर, भागना शुरू कर दिया। पुलिस ने जब दुबे को सरेंडर करने को कहा तो उसने पुलिस टीम पर गोलियां चलाई, जिसमें विकास मारा गया। इससे संदेह है कि उसके राजनीति और अपसरशाही के उस गठजोड़ का राज भी दफन हो गया जिसके सहारे उसे 60 संगीन मामलों के बावजूद जमानत मिली हुई थी और हत्या जैसी वारदात करने के बावजूद उसकी लाइसेंसी बंदूक उसके पास सलामत थी। यही सबाल अब सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है और मुठभेड़ की न्यायिक जांच के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से कह चुकी है। विकास दुबे का मामला सामने आने के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश की विनोनी आपाधिक दुनिया का खुलासा हुआ है। यह बताता है कि कैसे राज्य में अपराध की संस्कृति विकसित हो गई है जो दुबे जैसे डॉन या गैंगस्टर को पनपने का मौका देती है। अहम बात यह है कि राज्य में यह संस्कृति दशकों से चली आ रही है।

अब बात चबल के बीहड़ों के उन डकैतों की करते हैं, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर आतंक फैलाए हुए थे। उन्हें स्थानीय लोग बागी कहा करते थे। इन बागियों ने बॉलीवुड को भी अनेक कहानियां दी हैं। बीहड़ के इन डकैतों में कई ने बाद में सरेंडर भी कर दिया। उन्हीं में से एक डकैत मोहर सिंह था, जिसकी दो महीने पहले मौत हुई है। मोहर सिंह ने विनोबा भावे के आहान पर साठ के दशक में सरेंडर किया था। उसके बाद 1972 में जय प्रकाश नारायण, 1976 में मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी और 1982-83 में मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के आहान पर कुछ डकैतों ने सरेंडर किया। अगर इन चार दशकों को देखा जाए तो ये बागी, सामंतवादी समाज के खिलाफ खड़े हुए थे। लेकिन आज के दौर के गैंगस्टर की कहानी कुछ और है। पिछले चालीस वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है। वारदात करने के तरीके, अपराध में इस्तेमाल होने वाले हथियार, अपराध की दुनिया में आने वाले लोगों की सामाजिक हैसियत, सब कुछ बदल गई है। सबसे बड़ा बदलाव यह आया कि गैंगस्टर्स का सत्ता में दखल बहुत तेजी से बढ़ा है। विकास दुबे इसका सबसे ताजा उदाहरण है।

ज्यादातर बागी व्यवस्था के विरोध में हथियार उठाते थे, लेकिन उनके नए अवतार यानी गैंगस्टर सुपारी लेकर हत्या करने लगे हैं। यानी वे एक तरह से हत्या करने की मशीन बन गए हैं। अपराध में जिस तरह सत्ता का खेल शामिल हो गया है, वह उसकी मजबूत जड़ों को भी बताता है। साफ है कि भारत



में अपराधी और नेताओं के गठजोड़ का मजबूत तंत्र बनता जा रहा है।

अब राजनीति बदल गई है और दशकों से जमी सत्ता की जड़ें भी हिली हैं। सामाजिक संरचना में आए बदलाव से भी सत्ता को नए सिरे से चुनौती मिलने लगी है। पहले समाज के हाशिये पर बैठे बागियों ने इस बदलाव को हवा दी। उस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर भी सवाल उठाए, लेकिन पुलिस के काम-काज का तरीका बदस्तूर जारी रहा। तत्कालीन मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के

**समर्पण राजनीति:** 1983 में दस्यु सुंदरी फूलन देवी मप्र के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने सरेंडर करते हुए

कार्यकाल में डकैतों के खिलाफ चलाए गए अभियान में 1981-1983 के दौरान 1,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। उस अभियान पर यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी आनंद लाल बनर्जी का कहना है, “मार्च 1982 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और विश्वनाथ प्रताप सिंह के भाई की हत्या के बाद राज्य में पुलिस को डकैतों के खात्मे के निर्देश दिए गए थे। इस अभियान में कई ऐसे लोगों को मार दिया गया जिन्होंने छोटे-मोटे अपराध किए थे। कुछ तो बेगुनाह थे, लेकिन डकैतों का सफाया करने के इस पागलपन में इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। पुलिस ने यह भी नहीं देखा कि मारे गए लोगों में कितने वास्तव में डकैत थे।” बनर्जी की उस वक्त पुलिस में नई-नई भर्ती हुई थी।

ऐसा माना जाता है कि डकैतों को मारने के लिए जूनियर पुलिस वालों की जान को जोखिम में डाला जाता था। जब डकैत मार दिए जाते थे, तब सीनियर अधिकारी आकर उसका श्रेय लेते थे। कई बार डकैतों को पेड़ से बांध दिया जाता था। डाकुओं के साथ इस तरह के व्यवहार से साफ है कि प्रतिशोध की भावना उस समय भी थी। जब फूलन देवी मध्य प्रदेश में सरेंडर के लिए जा रही थीं, तो उस वक्त एक पुलिस अधिकारी के शब्दों ‘फूलन हमारा शिकार है’ की आज भी चर्चा होती है। यह बयान बताता है कि ज्यादा नंबर बनाने के चक्कर में उस वक्त भी पुलिस इस तरह के काम करती थी।

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के अब तक के तीन साल के कार्यकाल में 100 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं। आज भी उसी तरह के आरोप पुलिस पर लग रहे हैं कि उसने प्रतिशोध के नाम पर बहुत से छोटे-मोटे अपराधियों के साथ बेकसूरों को भी मार दिया। इन उदाहरणों से साफ है कि आज के दौर में अपराधियों से निपटने के लिए किस तरह का पुलिस तंत्र तैयार हो रहा है। जिस तरह कई डकैत अच्छे दिल वाला हो सकता है, उसी तरह पुलिस वाला भी युग्मे सामाजिक सोच से प्रभावित होकर पुरानी कार्यशैली में काम कर सकता है।

इस माहौल में कैसे सभी चीजें बदल गई? यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह कहते हैं, “राज्य में संगठित अपराध 1980 के दशक में पनपना शुरू हुआ जो धीरे-धीरे 90 के दशक में चरम पर पहुंच गया। उस वक्त सुपारी लेकर हत्या करना, चुनाव के दौरान बूथ लूटना, अवैध शराब की बिक्री, जबरन सरकारी टेके हासिल करना, अपहरण, मानव

## यूपी पुलिस की ‘ठोक दो’ नीति का ही नतीजा है कि योगी आदित्यनाथ के तीन साल के कार्यकाल में 100 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं

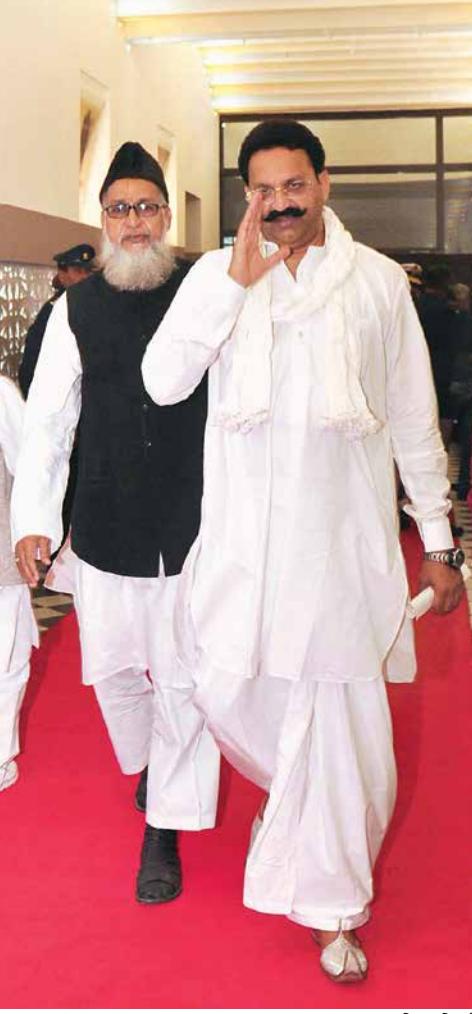


तस्करी, जाली नोट जैसे अपराध बहुत तेजी से बढ़े। छोटे-माटे अपराधी कुछ करोड़ खर्च कर ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख बनने लगे। अगर कोई 10 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च कर देता तो वह विधायक का चुनाव लड़ने लगता था। अगर किसी के अंदर अपराध करने का कोई भी गुण है तो उसके लिए राजनीति में प्रवेश कर सफल होना बहुत आसान हो गया था। उसे प्रष्ठा राजनेताओं, पुलिस और कमज़ोर न्याय व्यवस्था का भी सहारा मिल जाता था। धीरे-धीरे भ्रष्टाचार का एक मजबूत और बड़ा तंत्र तैयार हो गया।”

समय के साथ अपराध का दायरा भी बढ़ता गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 70-80 के दशक में अपहरण और उगाही प्रमुख अपराध हुआ करते थे। उदाहरण के तौर पर मुजफ्फरनगर में कोई संपन्न गन्ना किसान रहता था, तो गन्ने की कटाई के समय उसके बेटे का अपहरण जरूर होता था। इसी तरह गाजियाबाद, मेरठ के संपन्न व्यापारी हमेशा डर के साथ में रहते थे। अपहरण जैसे अपराध तो अब भी चल ही रहे हैं। एक समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लठौतों का बोलबाला हुआ करता था। भूमि सुधार के बाद ये लठौत टेक्स वसूली में माफियाओं की मदद करने लगे। अब इनका इस्तेमाल सरकार के ठेके लेने और स्थानीय स्तर पर वोट जुटाने में किया जाता है।

इसी तरह, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एक अहम जिला है जो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय भी है। वहां रेलवे के स्कैप का ठेका हासिल करने के लिए कई तरह के अपराध और माफिया खड़े हो गए। सबसे मशहूर लडाई माफिया डॉन हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के बीच उभरकर सामने आई। माना जाता है कि हरिशंकर तिवारी को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलापति त्रिपाठी का वरदहस्त हासिल था, वहां वीरेंद्र शाही पर कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता वीर बहादुर सिंह का हाथ था। इस लडाई में हरिशंकर तिवारी नए डॉन बन कर उभरे। वे 23 साल तक विधायक रहे। यही नहीं, वे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सबके सासनकाल में मंत्री भी बने। उनके विरोधी वीरेंद्र शाही की एक और माफिया श्रीप्रकाश शुक्ला ने 1997 में हत्या कर दी थी। उस वक्त तक शाही भी दो बार विधानसभा चुनाव जीत चुके थे। शुक्ला ने जब शाही की हत्या की थी, तो वह मात्र 24 साल का था। शुक्ला उस समय अपनी चमक-दमक वाली जीवन शैली के लिए भी जाना जाता था। वह हमेशा यही कहा करता था कि उसे भारत का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनना है। वह एक तरह से आज के दौर के विकास दुबे जैसा था।

श्रीप्रकाश शुक्ला पर कैसे गिरफ्त में आया, वह उस वक्त भाजपा के एक नेता के दावे से पता



निराला त्रिपाठी

**सबसे बड़ा डॉन:** चंदौली के राजनेता मुख्तार अंसारी

पड़ी थी।

शुक्ला के मारे जाने के बाद एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट में जो खुलासे किए, वे काफी चौंकाने वाले थे। रिपोर्ट में यह बताया गया था कि कैसे अपराधियों और राजनेताओं का गठजोड़ पूरे राज्य में तैयार हो गया था और यही गठजोड़ राज्य को चला रहा था। रिपोर्ट के अनुसार कम से कम भाजपा के आठ मंत्रियों ने कभी न कभी अपने सरकारी आवास पर शुक्ला को छुपाया था। यही नहीं, दूसरे राजनीतिक दलों के नेता, नौकरशाह और पुलिस अधिकारी भी शुक्ला को गिरफ्तारी से बचा रहे थे। यह गठजोड़ कितना खतरनाक था, इसे ऐसे समझा सकता है कि शुक्ला ने एक बार अपहरण के लिए जिस कार का इस्तेमाल किया था, उसकी बुकिंग अमरमणि त्रिपाठी ने कराई थी। चार बार के विधायक अमरमणि भी डॉन रह चुके हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने टिकट दिया है। इस समय वे मधुमिता शुक्ला की हत्या के मामले में जेल में हैं।

उत्तर प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में बसा मुगलसराय भी अपराध का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यहां रेलवे का बड़ा जंक्शन होने के कारण बिहार और झारखण्ड की कोयला की खदानों से निकलने वाले कोयले की लोडिंग-अनलोडिंग होती रही है। इस बजह से यहां कोयले का अवैध व्यापार तंत्र खड़ा हो गया है। इसके पड़ोस में चंदौली कोयला मंडी है। इस क्षेत्र पर दबदबे के लिए मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय में प्रतिदंदिता रही है। इसी लडाई में कृष्णानंद राय सहित छह लोगों की हत्या अंसारी के गुर्गे मुना बजरंगी ने 2005 में की थी। इस हत्याकांड में सात लोगों के शरीर से 67 गोलियां मिली थीं। बाद में जुलाई 2018 में बागपत जेल में बजरंगी की हत्या कर दी गई थी। यह हत्या एक अन्य गैंगस्टर ने की थी, उसने बजरंगी के सिर में 10 गोलियां मारी थीं। इसी कड़ी में दून स्कूल में पढ़ाई कर चुके रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, अंतीक अहमद और डी.पी. यादव का भी नाम सामने आता है। इन तीनों के नाम दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। हत्या, गैंगवार, आदि में शामिल होने के बावजूद उनका राजनीतिक करियर फलता-फलता रहा है। सबसे अहम बात यह है कि इन्होंने कभी अपने पाप को छुपाने या उसे धोने की कोशिश नहीं की। अंतीक अहमद और डी.पी. यादव अभी जेल में हैं। इन लोगों ने राजनीतिक रसूख का फायदा उठाते हुए कई पार्टियां बदली हैं। हालांकि उनका ज्यादातर समय समाजवादी पार्टी में गुजरा है।

कानून बनाने वालों और कानून तोड़ने वालों के



## संजीव माहेश्वरी

### उर्फ़ जीवा

दबदबे का इलाका

मुजफ्फरनगर, सहारनपुर (प.यूपी)

**मौजूदा स्थिति**  
लखनऊ जेल में

**गैंग के साथी**  
प्रवीण कुमार भित्ति उर्फ़ पीटर,  
फिरोज पठान, अनुज शर्मा और  
अनुज त्यागी

**राजनीति**  
राष्ट्रीय लोक दल के समर्थक के  
रूप में पहचान

माहेश्वरी भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी  
की हत्या के आरोप में जेल में है। उसके  
ऊपर गैंगस्टर मुख्तार अंसारी और  
मुन्ना बजरंगी का भी हाथ रहा है। जीवी  
के ऊपर 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं।



## सुंदर भाटी

### उर्फ़ नेताजी

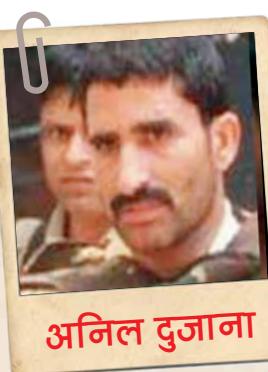
दबदबे का इलाका

गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर

**मौजूदा स्थिति**  
हमीरपुर जेल में

**गैंग के साथी**  
सतवीर बंसल, राहुल, ब्रजेश

**राजनीति**  
ज्ञात नहीं



## अनिल दुजाना

### उर्फ़ अनिल नागर

दबदबे का इलाका  
गौतमबुद्ध नगर

**मौजूदा स्थिति**  
महाराजगंज जेल में

**गैंग के साथी**  
अमित पंडित, आशीष चौहान और  
योगेश

**राजनीति**  
ज्ञात नहीं

दुजाना पुलिस की गिरफ्त में आने से  
पहले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मोस्ट वांटेड  
अपराधियों की सूची में था। उसके ऊपर  
हत्या, वसूली, फिरोती, हत्या का प्रयास  
करने के 50 से अधिक मामले दर्ज हैं।

1993 में पहली बार अपराध के क्षेत्र में  
भाटी सुर्खियों में आया। उसके बाद से  
उसका अपराध का ग्राफ बढ़ता गया।  
भाटी गैंग पर हत्या, आगजनी, फिरोती,  
बहुराष्ट्रीय कंपनियों, ट्रेडर्स, पानी और स्कैप  
के कारोबारियों, प्रॉपर्टी डीलर्स आदि से  
जबरन वसूली का भी आरोप है। गैंग के  
ऊपर लूट-पाट, हत्या, हत्या की कोशिश,  
फिरोती, गैर कानूनी रूप से हथियार रखने  
के करीब 40 मामले दर्ज हैं।



शॉर्प शूटर के रूप में इसकी पश्चिमी  
यूपी के गैंग्स में पहचान है। इसके ऊपर  
30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वह दो बार  
जेल से फरार भी हो चुका है। पकड़े जाने  
से पहले पुलिस ने उस पर 50 हजार  
रुपये का ईनाम रखा था।



## अंकित गुर्जर

दबदबे का इलाका  
नोएडा, गाजियाबाद

**मौजूदा स्थिति**  
महाराजगंज जेल में

**गैंग के साथी**  
अमित कसाना

**राजनीति**  
ज्ञात नहीं

**डाकुओं की दुनिया:** मलखान सिंह जैसे पहले के दौर के बागी बेहद साधारण जीवन जीते थे

इस गठबंधन को मजबूत करने में शहरी वर्ग की अहम भूमिका रही है। इसके अलावा उस दौर में ही रहे सामाजिक और राजनीतिक बदलाव ने भी इस गठजोड़ को मजबूत करने में अहम भूमिका निर्भाइ है। ये चीजें कैसे लोकतंत्र का हिस्सा बन गईं, इसके जबाब में 'वेन क्राइम पेज़: मनी एंड मसल्स इन इंडियन पॉलिटिक्स' पुस्तक की लेखक और वाशिंगटन स्थित कार्नेगी एनडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के डायरेक्टर और संनियंत्र फेलो (साउथ एशिया प्रोग्राम) मिलान वैष्णव का कहना है, "यूपी सहित दूसरे राज्यों में आपातकाल के दौरान अहम मोड़ आया। आपातकाल से पहले चुनावों में राजनेता इनका इस्तेमाल जबरन वोट डलवाने और वृथत लूटने जैसे आपराधिक कामों में किया करते थे, लेकिन आपातकाल के बाद सीधे तौर पर अपराधियों और राजनेताओं का गठजोड़ दिखने लगा। अस्सी और नब्बे के दशक में यह संख्या काफी तेजी से बढ़ी। इसकी एक बड़ी वजह उस दौर के मंडल, मस्जिद और बाजार जैसे मुद्दे थे, जो राजनीति में बदलाव की अहम वजह बने।"

सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसायटी एंड पॉलिटिक्स के डायरेक्टर अनिल कुमार वर्मा ने हाल ही में आउटलुक के लिए कानपुर की घटना पर लिखे लेख में बताया है, "70 और 80 का दशक उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव का दौर था। उस समय स्थापित पार्टियों में अभिजात्य वर्ग के एकाधिकार को चुनावी मिल रही थी। यह वह समय था जब राज्य में दलित और पिछड़ा वर्ग एक मजबूत राजनीतिक ताकत बनकर उभरा था।" इस बदलाव के प्रतीक के रूप में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सामने आई थी। इन राजनीतिक दलों ने अपना आधार बनाने के लिए अपराधियों को संरक्षण दिया। इन्होंने अपराधियों को जाति के सम्मान से जोड़ दिया और उन्हें वोट भी मिलने लगे।" वैष्णव कहते हैं, लोग यह भूल गए थे कि राज्य का काम निष्पक्ष होकर उन्हें सेवाएं प्रदान करना है। इस कारण भी इन दलों को समर्थन मिला। बदले माहौल में राजनेताओं ने अपने संसदीय क्षेत्र में काम कराने के लिए अपराधियों का सहारा लेना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में यह गठजोड़, दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा मजबूत होकर सामने आया। वैष्णव एक बात और कहते हैं। उनके अनुसार, "कई बार ऐसा लगता है कि केवल यूपी में ही अपराध हो रहे हैं, लेकिन बिहार, महाराष्ट्र और झारखण्ड भी ऐसे राज्य हैं जहां अपराध की दर बहुत ज्यादा है। गुजरात और केरल जैसे राज्यों में जारी राजनीतिक प्रतिदंदिता की खबरों को बहुत कम तरजीह मिलती है। मेरा मानना है कि उत्तर भारत में अपराध को बढ़ावा देने की जो छवि



बनी है, उसकी एक बड़ी वजह सिनेमा संस्कृति भी है। यहां पर दबंग का विचार ही बिकता है।" इसे राज्य की विधानसभाओं में आपराधिक रिकॉर्ड वाले सदस्यों की मौजूदगी भी साबित करती है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपराधिक रिकॉर्ड वाले सदस्यों की संख्या 35 फीसदी, राजस्थान में 23

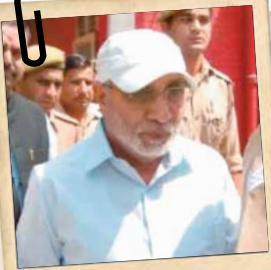


**राजनीतिक रसूख:** गैंगस्टर अतीक अहमद इस समय जेल में, एक समय सपा के सांसद थे

फीसदी, पंजाब में 23 फीसदी, मध्य प्रदेश में 40 फीसदी, कर्नाटक में 35 फीसदी और महाराष्ट्र में 60 फीसदी है।

### डाकुओं का जीवन

आपराधिक राजनीति को लेकर इन्हीं आसानी से किसी तथ्य पर पहुंचने से पहले हमें सफेदपोश अपराधियों का भी विश्लेषण करना चाहिए। इनकी संख्या जिस तरह उत्तर प्रदेश में बढ़ी है, वह विश्व स्तर पर कभी नहीं देखी गई है। इसकी एक बड़ी वजह राज्य में हुआ सामाजिक बदलाव है। राज्य के सबसे दुर्दांत डैकॉंटों में रघुवीर सिंह यादव उर्फ छबीराम को पुलिस ने उसके 11 साथियों के साथ मार्च 1982 में ढेर कर दिया था। छबीराम और उसके गैंग को मारने के लिए पुलिस को करीब नौ हजार राठड़ गोलियां चलानी पड़ी थीं। मारे जाने से पहले छबीराम ने 24 पुलिस वालों की हत्या की थी। उसके गैंग में करीब 100 डैकॉंट शामिल थे। इनमें ज्यादातर ऐसे थे जो साहूकारों और जर्मीदारों के सताए थे। उसी दौरान डैकॉंट पोथी, महावीरा और अनार सिंह भी पुलिस के हाथों मारे गए। मुठभेड़ के बाद मैनपुरी पहुंचने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कपूर उस वक्त का जिक्र करते हुए कहते हैं, "थाने के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ जमा थी। मैंने सामान्य लहजे में बोला, अब लोगों को इसके आतंक से राहत मिलेगी। लेकिन यह बोलते ही भीड़ ने तुरंत गुस्से में मुझसे कहा कि तुम लखनऊ से जींस और शर्ट पहनकर पहुंच गए, तुम क्या जानते हो। नेता जी चले गए, अब हमें पुलिस

**सुशील****उर्फ़ मूँछ****दबदबे का इलाका**

मुजफ्फरनगर, झेरठ,  
सहारनपुर, बागपत

**मौजूदा स्थिति**  
कानपुर जेल में

गँग के साथी  
उसके बेटे अक्षयजीत उर्फ़ मोनी,  
मनजीत उर्फ़ टोनी सहित 29 लोग  
शामिल होने की खबर

**राजनीति**  
ज्ञात नहीं

सुशील मूँछ उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड में अपराध का जाना-पहचान नाम है। इन राज्यों में उसने हत्या, अपहरण की गहरी जड़ें, संगठित गँग के जरिए जमा दी हैं। 65 साल के सुशील के नाम पर 52 आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2012 में एक बार गिरफ्तार हो हुआ था लेकिन बाद में जमानत मिल गई। 2018 में सबको चौंकाते हुए उसने अचानक पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था।

**गौरी यादव****दबदबे का इलाका**

चित्रकूट और यूपी-मध्य प्रदेश की सीमा से सटे इलाके

**मौजूदा स्थिति**

फरार, एक लाख रुपये का ईनाम

**गँग के साथी**  
भोला यादव, विनय कुमार**राजनीति**  
ज्ञात नहीं**अजय सिंह****उर्फ़ अजय सिपाही**

दबदबे का इलाका  
आंबेडकरनगर, लखनऊ,  
सुलतानपुर, अयोध्या

**मौजूदा स्थिति**  
मदोही जेल में**विजय प्रताप और अभिषेक सिंह****राजनीति**  
ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीता

गौरी यादव पर कम से कम 29 मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, लूटपाट, फिरौती के मामले शामिल हैं। चित्रकूट क्षेत्र में इसके खौफ का आलम यह है कि, सरकारी काम भी नहीं हो पाते हैं। मार्व के महीने में वन विभाग की टीम पर हमला कर उसने काम लूकवाकर फिरौती मांगी थी।

साल 2005 में जेल गया था। उस वक्त जेल में कैदियों के साथ हुई लड़ाई से चर्चा में आया। कुछ दिन बाद जमानत मिल गई। लेकिन फिर उसे दोहरे हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। सङ्क सहित दूसरे निर्माण कार्मों की जबरन ठेकेदारी लेने में भी इसका हाथ रहा है।





**रवान मुबारक**

**दबदबे का इलाका**

आंबेडकर नगर, मऊ, भद्रोई,  
प्रयागराज

**मौजूदा स्थिति**  
हरदोई जेल में

**गैंग के साथी**

जफर सुपारी, शकील अहमद,  
रोहित, नीरज सिंह

**राजनीति**  
ज्ञात नहीं



**अताउर रहमान**

**उर्फ बाबू सिंकंदर**

दबदबे का इलाका  
गाजीपुर, मऊ, वाराणसी

**मौजूदा स्थिति**

फरार, 2 लाख का ईनाम

**गैंग के साथी**  
शहाबुद्दीन

**राजनीति**  
मुख्तार अंसारी  
का कारीबी



**बच्चा पासी**

**दबदबे का इलाका**

प्रयागराज

**गैंग के साथी**

दिलीप मिश्रा, राजेश यादव

**राजनीति**

2017 में बसपा नेता के रूप में  
पार्षद का चुनाव जीता

इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई करने वाले खान ने क्रिकेट मैच के दौरान अंपायर पर गोली चला दी थी। उसका भाई अपराध जगत में पहले से था। दोनों भाई इलाहाबाद से मुंबई आए। खान छोटा राजन का प्रमुख शार्पशूटर बना। कुछ समय बाद गृहनगर अंबेडकर नगर में अपराध का जाल बिछाना शुरू किया। 20 से ज्यादा मामले दर्ज, 2017 में लखनऊ से गिरफ्तार। जेल से गैंग को चलाने का भी आरोप।

विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल के एक रिश्तेदार पर हमले करने के बाद इसका नाम चर्चा में आया। इसके अलावा 2005 में भाजपा नेता कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल होने का भी आरोप है। इतने जघन्य अपराधों के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है।

राम संजीवन का समर्थन था, जो बाद में बसपा में शामिल हो गए थे। 2007 में जब दुआ को एसटीएफ ने मारा, तो वापस लौटी एसटीएफ की टीम पर अंबिका पटेल (ठोकिया) ने हमला कर दिया था। इस हमले में एसटीएफ के छह लोग मारे गए थे। हालांकि कुछ घंटे बाद ठोकिया को भी मार गिराया गया। उन वर्षों में दस्यु निर्भय गुर्जर और घनश्याम केवट भी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। इन सभी अपराधियों में एक बात की समानता भी रही है कि ये पिछड़ी जाति या दलित वर्ग के थे। एक अन्य डकैत मलखान सिंह ने 1982 में सरेंडर किया था। सिंह और उसके समकालीन के बारे में लखनऊ के पत्रकार दिलीप अवस्थी कहते हैं कि ये लोग सीधे-साधे लोग थे, मैंने मलखान सिंह की डायरी पढ़ी है, उसमें ज्यादातर खर्चे राशन, साबुन, आम जरूरतों के दिखाए गए थे, जो किसी गरीब परिवार के होते हैं। मलखान कभी अपने आपको डकैत नहीं,

छोटा राजन का कारीबी और 2006 में मुंबई के कालाघोड़ा शूटआउट में शामिल था। हिस्ट्री शीटर पप्पू गढ़वा की मौत के बाद बच्चा ने उसके गैंग की कमान संभाल ली थी। उस पर हत्या, हत्या की कोशिश, लूट-पाट, अवैध हथियारों की सप्लाई और अपराधियों को पनाह देने के भी आरोप लगते रहे हैं। बाद में पार्शी बसपा में शामिल हो गया और उसके टिकट पर पार्षद का चुनाव भी जीता। फिलहाल प्रयागराज में है।

बल्कि बागी कहलाना पसंद करता था। बागी होने के बावजूद इन लोगों के साथ जीवन जीने का संघर्ष हमेशा बना रहा। फिर भी वे कुछ उम्रों के साथ अपराध किया करते थे। मसलन उसने कभी किसी गरीब या महिला को नहीं सताया। कई बागियों की अपने इलाके में रोबिन हुड जैसी छवि थी जो गरीबों की मदद करता है।

अगर आज विकास दुबे के दौर से उस समय की तुलना की जाय तो वह पूरी तरह से बदल चुका है। अब अपराध की कमान पिछड़ी जातियों से निकलकर ब्राह्मण गैंगस्टर्स जैसे शुक्ला, तिवारी, त्रिपाठी के पास चली गई हैं। इस बदलाव को उत्तर प्रदेश ने 90 के उथल-पुथल भेर दशक में पार कर लिया है।

### लल्लू यादव

दबदबे का क्षेत्र: लखनऊ  
मौजूदा स्थिति: जमानत पर  
यादव पर हत्या का मामला और अवैध रूप से हथियार रखने का भी आरोप है।



### रमेश सिंह उर्फ़ काका

दबदबे का क्षेत्र: मऊ  
मौजूदा स्थिति: वाराणसी जेल में 60 से अधिक मामले दर्ज हैं। जिसमें हत्या, लूट-पाठ आदि शामिल हैं।



### संजीव द्विवेदी उर्फ़ रामू

दबदबे का क्षेत्र: देवरिया  
मौजूदा स्थिति: जमानत पर  
बीएसपी से एमएलसी रह चुके हैं और पार्टी के सांसद धनंजय सिंह के करीबी हैं।



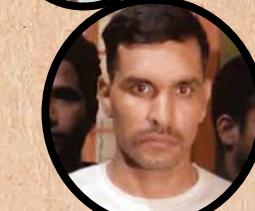
### योगेश भटोहा

दबदबे का क्षेत्र: मेरठ  
मौजूदा स्थिति: सिद्धार्थ नगर जेल में उधम सिंह गैंग का मुख्य प्रतिद्वंदी है। फिरोती का रैकेट चलाने का आरोप है।



### राजेश यादव

दबदबे का क्षेत्र: प्रयागराज  
मौजूदा स्थिति: जमानत पर  
हत्या का आरोपी, साथ ही अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के साथ काम करने का आरोप।



### दिलीप मिश्रा

दबदबे का क्षेत्र: प्रयागराज  
भाजपा नेता और कैबिनेट मंत्री गोपाल गुप्ता का राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। गुप्ता पर साल 2010 में हमले का आरोप।



### अनिल भाटी

दबदबे का क्षेत्र: गौतम बुद्ध नगर  
मौजूदा स्थिति: कौशांबी जेल में भाजपा नेता शिवकुमार और उनके ड्राइवर की हत्या करने के आरोप में 2017 में गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा नोएडा में बहुराषीय कंपनियों से उगाही का भी आरोप।



### सिंहराज भाटी

दबदबे का क्षेत्र: गौतम बुद्ध नगर  
मौजूदा स्थिति: फैजाबाद जेल में फिरोती लेने का आरोपी और दूसरे अपराधिक मामलों में लिप्त



### अमित कसाना

दबदबे का क्षेत्र: गौतम बुद्ध नगर  
मौजूदा स्थिति: गौतम बुद्ध नगर जेल में जैगस्टर सुंदर भाटी का शॉर्पशूटर और फिरोती लेने का आरोपी।

### आकाश जाट

दबदबे का क्षेत्र: शामली  
मौजूदा स्थिति: गाजियाबाद जेल में जैगस्टर सुंदर भाटी का शॉर्पशूटर और फिरोती लेने का आरोपी।



### उधम सिंह

दबदबे का क्षेत्र: मेरठ  
मौजूदा स्थिति: बैनी जेल में जैगस्टर मुन्ना बजरंगी की हत्या में अपने जैग का नाम शामिल होने की बात स्वीकारी।

### मुलायम यादव

दबदबे का क्षेत्र: प्रतापगढ़  
मौजूदा स्थिति: बरेली जेल में फिरोती लेने का आरोपी।



### अजीत उर्फ़ पप्पू

दबदबे का क्षेत्र: बागपत  
मौजूदा स्थिति: बस्ती जेल में

### हरीश

दबदबे का क्षेत्र: मुजफ्फरपुर  
मौजूदा स्थिति: भगोड़ा, 2 लाख का ईनाम 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज, इसमें हत्या और लूट प्रमुख रूप से शामिल हैं।

### शिवा बिंद

दबदबे का क्षेत्र: गाजीपुर  
मौजूदा स्थिति: फरार,  
50 हजार का ईनाम

### आफताब आलम

दबदबे का क्षेत्र: इलाहाबाद  
मौजूदा स्थिति: फरार  
50 हजार का ईनाम



### पिंटू

दबदबे का क्षेत्र: भदोही  
मौजूदा स्थिति: फरार, 50 हजार का ईनाम

# The Global Epicentre of Knowledge

**J**aipur, the Pinkcity has been at the helm of world tourism since ages. But now, this magnificent city has also become a major hub for world-class higher education, with a good number of universities offering quality education. Among these universities, a name that has created waves all across the globe is Nims University, which has grown leaps and bounds in terms of enrolments, courses offered and amenities extended to the students who flock in great numbers from all corners of the world for a lifetime experience and learning par excellence.

The brainchild of Prof.(Dr) Balvir S. Tomar, an authority in medical sciences and a name of highest repute in healthcare education, Nims University came into being in decade before, by the enactment of the Nims University Rajasthan, Jaipur Act, 2008 by the Government of Rajasthan. Today, this gigantic epicentre of higher education, spread over 60.9 acres amidst green Aravali Ranges has not only become a leading University in India within a short span of nine years, it also boasts of being the Largest Self-financed University in Rajasthan. The state-of-the-art campus of Nims University - a splendid composite of 45 buildings that house constituent colleges and institutes, lecture theatres, laboratories, hospital, hostels, administrative offices, residential blocks, bank and post office, etc., stands tall along Jaipur-Delhi Highway, with its commitment to promote quality education in a variety of courses and action-oriented research in diverse fields of human welfare. The University is recognized by UGC, MCI, DCI, PCI, INC, BCI, COA, RPC and other regulatory bodies. It is also a member of Association of Indian Universities (AIU).

Offering more than 350 programmes that include courses in medical, dental, pharmacy, paramedical, engineering and technology, management, architecture, humanities, fashion designing, law, etc., Nims University is a temple of knowledge for more than 25000 Indian and foreign students from more than 25 countries. Nims University has a highly dedicated, well-qualified and thoroughly professional faculty of over 1000 Faculties. The university has drawn its teaching talent from IITs, NITs, and various prestigious nationally and internationally acclaimed universities and institutes in its endeavour to groom young minds to become future leaders, experts and great citizens. The Medical faculty has been drawn from AIIMS, PGIs, KGMC, SMS and many other renowned medical institutes. The University has a number of national and international collaborations, granting opportunities to the students to study in world's best institutions.

Nims University provides technical and professional education in modern disciplines such as aircraft and aerospace engineering, oil & natural gas engineering, mines engineering, food technology, Biomedical engineering and energy & power. Various other specific management disciplines are forestry for futuristic sustainable development for green energy, health and nutrition management etc . In order to give a fillip to the scarcity in aeronautical engineering, pilot & other allied services the university has purchased two aircrafts of 5 & 55 seater to provide hands on experience to the students. Nims University offers training & certificate courses in various streams like stone crafting, leather and textile engineering, nanotechnology, agriculture engineering

In addition to inculcating essential skills in practicing physicians and technologists, Nims University attunes them towards achieving the highest professional and human goals. Nims Hospital a super specialty tertiary care hospital is a constituent unit of Nims University provides most modern treatment for all diseases and disorders and has modern sophisticated diagnostic and therapeutic facilities. This exquisite hospital is a "Healthcare for All" centre, catering to the needs of lower income groups. The hospital specializes in providing low cost treatment of all ailments. Approved by the Government of Rajasthan for Bhamashah Yojna, BPL Chief Minister Scheme, Janani Suraksha Yojna and other such welfare schemes, Nims Super Speciality Hospital provides all ultra-modern facilities like Angioplasty, Bypass Surgery, Valve Replacement Surgery, Laparoscopic Stone Removal & Prostate Surgery, Dialysis, Kidney & Liver Transplant, Knee/Hip Replacement, Spinal and Neuro Surgery, Infertility Treatment along with IVF, to name a few.

## THE MENTOR AND THE DRIVING FORCE



### Prof. (Dr.) Balvir S. Tomar

**M.B.B.S., M.D., M.C.H.(USA), M.I.A.P., M.A.H.T.(ENGLAND), F.I.A.P(USA), F.A.A.P(USA), F.I.C.A.(USA), F.A.C.U.(LONDON).**

*Pediatric—Gastroenterologist: Kings College Hospital School of Medicine University of London (England), Ped. Nutrition: Harvard University (USA)*

*WHO Fellow in Child Health in USA,*

*Common wealth Fellow in London (England)*

**Formerly Professor & Head : Department Pediatric Gastroenterology, SMS Medical College, Jaipur**

#### PRESIDENT:

Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology, Transplant & Nutrition

#### DIRECTOR:

Institute of Pediatric Gastroenterology and Hepatology Institute of Organ Transplant

#### CHAIR:

Institute of Stem Cells and Regenerative Medicine

Institute of Nutrition and Public Health

#### CHANCELLOR:

Nims University, Jaipur

#### CHAIRMAN:

**Nims Global Group**

National Council on Chemicals and Petrochemical -ASSOCHAM

National Council of Skill Development – ASSOCHAM

National Accreditation Board for Education and Training (NABET)

**H**ighly decorated with a slew of medical adornments, the Chairman & Chancellor of Nims University, Prof. (Dr.) Balvir S. Tomar, is the actual impetus and *raison d'être* of this magnificent institution of learning. Dr. Tomar is famous in the medical circles, for his dynamism, versatility, charisma and multi-dimensional personality. Dr. Tomar was destined to acclaim a tall stature for himself in the medical and healthcare field. He is widely admired as a strategist, innovator, dynamic leader motivator and a humane educationist who values holistic development of individuals at personal and professional levels. He is known as a deft planner and facilitator who has brought about countless growth opportunities for students, faculty members, associates and people at large. He is applauded by one and all for his observance of highest principles of integrity in professional and personal life. The University has Office of Academic Integrity to uphold fare practices and promote faculty diversity. He has regularly undertaken numerous philanthropic endeavours, establishing research centres in many areas, dedicated to the service of nation and society at large. He has invented treatment therapy by the D-penicillamine for the deadly disease called "Indian Childhood Cirrhosis", a significant research work that was published in "Advances in paediatrics".

Prof. (Dr.) Balvir S. Tomar sees students, faculty members, doctors, patients and associates as integral elements of a large, close-knit community, working towards the common goals of human welfare and service of the nation through academics and healthcare. He has been a strong pillar, amidst tough times and challenges that holds high the morals and ethics of this grand institution called Nims University, to which he is dedicated just like the priest to a temple.



# NIMS UNIVERSITY

RAJASTHAN , JAIPUR



A  
“NAAC”  
ACCREDITED  
UNIVERSITY



## Make the move to Better Future

Undergraduate, Post Graduate and Doctoral Programmes in

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> MEDICAL       | <input type="checkbox"/> AVIATION           | <input type="checkbox"/> DENTAL                   |
| <input type="checkbox"/> ENGINEERING   | <input type="checkbox"/> ARCHITECTURE       | <input type="checkbox"/> BASIC & ADVANCE SCIENCE  |
| <input type="checkbox"/> PHARMACY      | <input type="checkbox"/> HOTEL & TOURISM    | <input type="checkbox"/> MANAGEMENT               |
| <input type="checkbox"/> NURSING       | <input type="checkbox"/> HUMANITIES         | <input type="checkbox"/> LIBRARY SCIENCE          |
| <input type="checkbox"/> PARAMEDICAL   | <input type="checkbox"/> LAW                | <input type="checkbox"/> THEATER & FILM           |
| <input type="checkbox"/> PHYSIOTHERAPY | <input type="checkbox"/> MEDIA & MASS COMM. | <input type="checkbox"/> TEXTILE & FASHION DESIGN |

**N**ims Superspeciality Hospital : State of art Super Speciality Hospital having Department of  
 • Cardiology • Cardio Thoracic Surgery • Gastroenterology • Hepatology • Oncology • Nephrology • Urology • IVF  
 • Neuro Surgery • Plastic Surgery • Critical Care • Multi Organ Transplant (Kidney & Liver Transplant) • Arthroplasty

**Call Today**

Toll Free: 1800 120 1020

Website: [www.nimsuniversity.org](http://www.nimsuniversity.org)

**Nims University Rajasthan, Jaipur-Delhi Highway NH-11C, Jaipur - 303121**

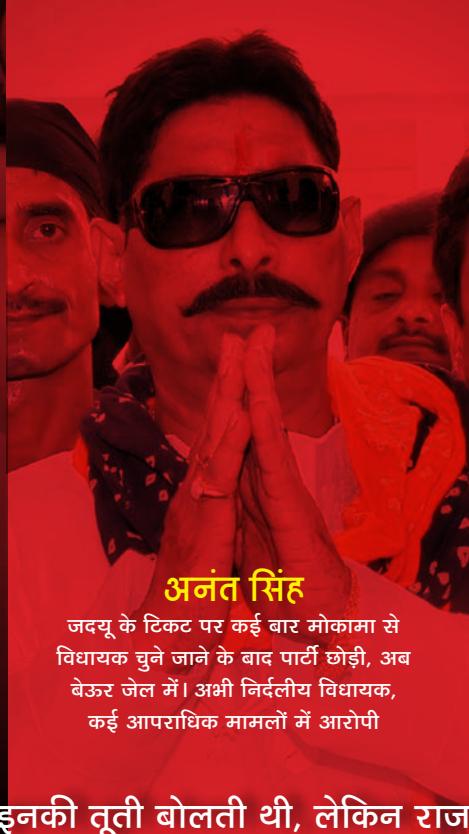
Contact: +91- 7412077145, 7412077166, 7412077141, 9116010477 Email: [admissions@nimsuniversity.org](mailto:admissions@nimsuniversity.org)

# सियासी दम से दबंगई बेपनाह



## आनंद मोहन

बिहार पीपुल्स पार्टी के संस्थापक, 15 वर्षों से जेल में। 1994 में गोपालगंज के जिलाधिकारी जी. कृष्णच्छा की हत्या के मामले में उम्रकैद



## अनंत सिंह

जदयू के टिकट पर कई बार मोकामा से विधायक चुने जाने के बाद पार्टी छोड़ी, अब बेतर जेल में। अभी निर्दलीय विधायक, कई आपराधिक मामलों में आरोपी



## पप्पू यादव

माकपा विधायक अजित सरकार की हत्या के मामले में निचली अदालत ने दोषी ठहराया था, लेकिन हाइकोर्ट ने बरी कर दिया। पांच बार के सांसद, पिछले लोकसभा चुनाव में पराजित

कभी प्रदेश में इनकी तूती बोलती थी, लेकिन राजनैतिक संरक्षण कम होने से बदले हालात

## गिरिधर झा

**ज**ब बात अपराध और राजनीति के गलबहियां डालने की हो तो बिहार अक्सर अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का प्रतिबिंब नजर आता है। कानपुर में 10 जुलाई को पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारे जाने से पहले कुछ्यात डॉन विकास दुबे और उसके साथियों ने 3 जुलाई की रात मुठभेड़ में उत्तर प्रदेश के आठ पुलिसवालों की हत्या की, तो कुछ वर्षों पहले बिहार में हुई ऐसी ही घटना की याद ताजा हो आई। मार्च 2001 में बिहार के सीवान में जिला पुलिस प्रमुख बचू सिंह मीणा के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने मोहम्मद शहाबुद्दीन को पकड़ने के लिए प्रतापपुर गांव में ऐसा ही ऑपरेशन चलाया था। डॉन से राजद सांसद बने शहाबुद्दीन के नाम अपराध के अनेक रिकॉर्ड दर्ज हैं। फिलहाल वह 2005 से जेल में सजा काट रहा है।

प्रतापपुर गांव में हुई मुठभेड़ में 10 लोगों की जान गई थी, जिनमें दो पुलिसवाले भी थे। शहाबुद्दीन ने एक पुलिस अधिकारी को कथित रूप से चांटा मारा था, जिसके बाद पुलिस उसे पकड़ने गई थी। हालांकि माना जाता है कि स्थानीय पुलिसवालों के साथ वह जिस तरह अपमानजनक तरीके से पेंश आता था, उससे पुलिसवालों में शहाबुद्दीन के प्रति गुस्सा भरा हुआ था और यह ऑपरेशन उसी का परिणाम था। लेकिन शहाबुद्दीन के दबदबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि छापे के अगले ही दिन राबड़ी देवी सरकार ने मीणा समेत जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया। उस वक्त शहाबुद्दीन गिरफ्त में तो नहीं आया लेकिन पुलिस ने छापे में उसके घर से एक-47 राइफलों समेत हथियारों का जखीरा बरामद किया। इसके बाद शहाबुद्दीन ने यह कहते हुए एसपी को मारने की कसम खाई कि भले ही इसके लिए राजस्थान (एसपी के गृह प्रदेश) तक पीछा करना पड़े।

इस घटना से पांच साल पहले जीरादेह से जनता दल का विधायक रहते शहाबुद्दीन ने सीवान के तत्कालीन एसपी संजीव कुमार सिंघल पर कातिलाना हमला किया था। सिंघल उसके खिलाफ 1996 के संसदीय चुनाव से संबंधित एक शिकायत की जांच कर रहे थे। 1980 के दशक में कई अपराधों में नाम आने के बाद शहाबुद्दीन ने 1990 में निर्दलीय विधायक के तौर पर राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। जल्दी ही वह तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की नजरों में आ गया और 1995 का विधानसभा चुनाव सत्तारूढ़ पार्टी के टिकट पर लड़ा। 1996 से 2004 तक उसने चार संसदीय चुनाव जीते और इस दौरान सीवान उसकी निजी जागीर की तरह बना रहा। वसूली, अपहरण और हत्या के कई हाई-प्रोफाइल मामलों में उसका नाम आया, इसके बावजूद वह अपने अपराध का सिंडिकेट बेरोकाटोक चलाता रहा। उसका नेटवर्क कई राज्यों तक फैल गया था। जब शहाबुद्दीन जैसे शक्तिशाली डॉन की सत्ता के गलियारों में अबाध पहुंच थी, तब यह सुनकर आश्चर्य नहीं होता था कि बिहार बाहुबलियों की असली राजधानी है।

लेकिन अब बिहार का वह स्थान नहीं रहा। विकास दुबे जैसे अपराधियों के उत्थान (और पतन) से उत्तर प्रदेश सुर्खियों में रहने लगा है। बिहार में बीते 15 वर्षों के दौरान कानून के लंबे हाथों ने धीरे-धीरे शहाबुद्दीन और उसके जैसे दूसरे डॉन को खामोश करने में सफलता पाई है। राजनीतिक संरक्षण का ही नतीजा था कि शहाबुद्दीन, आनंद मोहन, सूरजभान सिंह, मुनील पांडे, पप्पू यादव, मुना शुक्रला, सतीश पांडे, मनोरंजन सिंह धूमल, रामा सिंह, राजन तिवारी, अनंत सिंह, रणवीर यादव, बूटन यादव, अवधेश मंडल और



## मोहम्मद शहाबुद्दीन

सिवान से चार बार राजद सांसद, 2005 से जेल में। हत्या, हत्या की कोशिश और अपहरण के कई मामलों में दोषी



## रीतलाल यादव

कभी 'दानापुर का आतंक' नाम से कुख्यात इस विधान परिषद सदस्य का नाम कई आपराधिक मामलों में शामिल। अभी पटना के बेऊर जेल में

का गठन किया, जिससे इन बाहुबलियों पर लगाम लगाने में काफी सफलता मिली। इन अदालतों ने अनेक बाहुबलियों को अपराधी ठहराया जिससे डॉन से नेता बने ये लोग चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए। धनबल और बाहुबल से इन्होंने जो राजनीतिक दबदबा बनाया था, वह कम होने लगा। फिलहाल ये लोग या तो जेलों में सजा काट रहे हैं या फिर ये राजनीतिक दलों के लिए 'अच्छूत' बन गए हैं।

शहाबुद्दीन 2005 से जेल में है, हालांकि 2016 में वह कुछ दिनों के लिए जमानत पर बाहर आया था। उसे एक के बाद एक कई मामलों में सजा सुनाई गई और फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद है। सीपीआई-माले कार्यकर्ता छोटेलाल गुसा के अपहरण और हत्या के मामले में 2007 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद दो भाइयों की नृशंस हत्या के मामले में 2015 में उसे उम्रकैद की सजा मिली। इन दोनों भाइयों को गोली मारने से पहले एसिड से नहला दिया गया था। घटना का प्रत्यक्षदर्शी तीसरा भाई घटनास्थल से तो बचकर भागने में कामयाब रहा, लेकिन इस मामले में गवाही देने से तीन दिन पहले 2014 में उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस बीच, 1996 में एसपी सिंघल पर कातिलाना हमले के मामले में 2007 में उसे 10 साल सत्रम कारावास की सजा सुनाई गई। इसके एक साल बाद अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा मिलने के मामले में भी उसे 10 साल की सजा मिली। उसके घर से पाकिस्तान में बनी ऐसी स्वचालित राइफलें

मिली थीं जिनका इस्तेमाल सिर्फ सेना करती थी। शहाबुद्दीन के अपराधों की सूची इतनी लंबी है कि कुछ मामलों पर सुनवाई अभी तक जारी है।

अब शहाबुद्दीन को देखकर यह विश्वास करना मुश्किल होता है कि यह वही डॉन है जिसने कभी पूरे राज्य की पुलिस को अकेले चुनौती दी थी। पुलिस महानिदेशक डी.पी. ओझा के कार्यकाल में उसके खिलाफ लंबा-चौड़ा डोजियर तैयार किया गया था। इसके बावजूद पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकी थी। इस डोजियर के मुताबिक शहाबुद्दीन के संबंध न सिर्फ कश्मीर के आतंकवादी संगठनों, बल्कि आईएसआई और दाऊद इब्राहिम के साथ भी थे।

1973 बैच के आईपीएस मनोज नाथ, जो बिहार के होमगार्ड महानिदेशक पद से रिटायर हुए, के अनुसार बिहार में डर का राजनीतिक इस्तेमाल किसी न किसी रूप में हमेशा होता रहा है, लेकिन 1990 के दशक में मंडल-मस्जिद राजनीति के दौरान यह राजनीतिक रसूख का मौलिक हिस्सा बन गया। वे कहते हैं, “इस डर ने राजनीति में पहले भी अहम भूमिका निर्भाई और अब भी इसकी भूमिका अहम है, इसलिए अपराध और राजनीति का गठोड़ एक तरह से प्राकृतिक मेल बन गया। वोट दिलाने में मददगार अपराधियों को खुलेआम पुरस्कृत किया जाने लगा। वे सत्ता के गलियरे में पिछले दरवाजे से नहीं, बल्कि सामने से आने लगे। अपने दबदबे और संरक्षण मिलने की वजह से उनके लिए छिपकर रहना जरूरी नहीं रह गया, बल्कि अब वे अकड़ के साथ चलने लगे।”

अपने समय में दबदबा और राजनीतिक संरक्षण हासिल करने वाला शहाबुद्दीन अकेला बाहुबली नहीं था। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अन्य लोग भी थे जो बाहुबल के दम पर राजनीति में आए। कोसी क्षेत्र में रोंबिन हुड नाम से जाना जाने वाला आनंद मोहन भी ऐसा ही एक प्रभावशाली बाहुबली था, जिसने बिहार पीपुल्स पार्टी नाम से अपना राजनीतिक दब बनाया। लेकिन गोपालगंज के जिलाधिकारी जी. कृष्णौर्या की हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उसकी राजनीतिक यात्रा आगे नहीं बढ़ सकी। मुजफ्फरपुर जिले में 1994 में उसने जिलाधिकारी पर हमला करने वाली भीड़ की अगुआई की थी। निचली अदालत ने 2005 में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखा। जेल में बंद वह कई किताबें लिख चुका है।

कोसी क्षेत्र से एक और बाहुबली है पप्पू यादव, जो पांच बार सांसद रह चुका है। माकपा विधायक अजित सरकार की 1998 में हत्या के मामले में जिला अदालत ने उसे दोषी ठहराया था, हालांकि बाद में हाइकोर्ट ने उसे इस मामले में बरी कर दिया। कई साल तक सलाखों के पीछे रहने के



## सूरजभान सिंह

मोकामा का डॉन, एलजेपी के टिकट पर सांसद बना। हत्या के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद चुनाव के लिए अयोग्य घोषित, अभी जमानत पर

नीतीश ने कानून को अपने तरीके से काम करने की अनुमति दी और पार्टी के विधायकों से जुड़े किसी भी मामले की जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। नीतीश यह हुआ कि सुनील पांडे और अनंत सिंह जैसे कई हाई-प्रोफाइल बाहुबली उनकी पार्टी से अलग हो गए।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) का कहना है कि नीतीश सरकार को लालू राबड़ी के 15 वर्षों के तथाकथित ‘जंगल राज’ के बारे में कुछ भी कहने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि यह सरकार भी बाहुबलियों के दम पर ही सत्ता में आई थी। राजद प्रवक्ता मुन्तुंजय तिवारी कहते हैं, “एक धारणा बनाई गई कि राजद के शासनकाल में जंगल राज था, लेकिन एनडीए के शासन में क्या हो रहा है? इसके 15 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में अपराध का ग्राफ देश में सबसे ऊपर है। प्रदेश में खुलेआम एके-47 राइफलें लहराई जा रही हैं। अगर राजद का शासनकाल जंगल राज था तो नीतीश के शासन काल को क्या कहेंगे, महा-जंगल राज?”

तिवारी कहते हैं, “राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहारवासियों से पार्टी के शासनकाल के दौरान हुई गलतियों और खामियों के लिए माफी मांग ली है। बिहार के लोगों ने हमारी पार्टी को 15 साल तक सत्ता से बाहर रखकर सजा दे दी है, लेकिन अब नीतीश सरकार को यह बताना पड़ेगा कि इसने अपने शासनकाल में सिवाय 55 घोटालों के और क्या किया? उन्हें हमारे शासनकाल की गलतियां गिनाने के बजाय अपनी उपलब्धियों का हिसाब देना पड़ेगा।”

जबाब में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता निखिल आनंद कहते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नीतीश ने बिहार को माफिया डॉन के आतंक से मुक्ति दिलाई है। आपराधिक तत्व छिप गए हैं, लेकिन अब वे मुख्यमंत्री के विरोधी राजनीतिक दलों के साथ आ रहे हैं। आनंद के अनुसार, “हमारी सरकार गुड गवर्नेंस को बढ़ावा दे रही है, इसलिए बाहुबली खामोश हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आरजेडों शारब माफिया, रेत माफिया, भू-माफिया और खनन माफिया जैसी ताकतों के साथ सांठगांठ कर रही है।” वे सवाल करते हैं कि क्या राजद इन ताकतों के दम पर सत्ता में लौटना चाहती है?

आनंद कहते हैं, “आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को इन बाहुबलियों और विपक्ष के साथ उनकी सांठगांठ पर नजर रखनी चाहिए। बिहार एक बार फिर बाहुबलियों के युग में जाने का खतरा नहीं उठा सकता। भविष्य में भी इन ताकतों को दरकिनार रखने का सबसे अच्छा विकल्प नीतीश जी ही हैं।”

# कोयलांचल के बाहुबली

धनबाद इलाके में पांच दशकों से चल रहे गैंगवार में 350 से अधिक की मौत,  
राजनीतिक सांठगांठ के चलते अब भी दबंगई जारी



एक समय कोयला क्षेत्र का असली शासन सूर्यदेव सिंह (इनसेट) के 'सिंह मैशन' से ही चलता था

## ► रांची से नवीन कुमार मिश्र

**अ**पराध के राजनीतिक रिश्तों की बात हो तो झारखंड से दिलचस्प जगह नहीं। सभी पार्टियों का यहां से सीधा वास्ता रहा। दबंगई और राजनीति का ऐसा मेल शायद ही कहीं और देखने को मिले। कोयले की राजधानी नाम से मशहूर धनबाद में कोयले की काली कमाई और वर्चस्व को लेकर पांच दशक से जारी लड़ाई में काला सोना की जमीन लाल होती रही। नीचे कोयला, तो सतह पर गैंगवार की आग धधक रही है, जिसमें अब तक कई बड़े नेता और दबंग

सहित 350 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। अवैध खनन और ढुलाई आदि में रंगदारी को लेकर सालाना पांच-छह सौ करोड़ रुपये से अधिक का खेल होता है। घुसपैठ के लिए दूसरे माफिया उत्तर प्रदेश के ब्रजेश सिंह, मुख्तार अंसारी और श्रीप्रकाश शुक्ल जैसे दबंगों की भी मदद लेते रहे। यहां होने वाली हत्याओं में उनके नाम आते रहे।

कोयलांचल के डॉन की चर्चा हो तो सूर्यदेव सिंह का नाम सबसे पहले आता है। कोयले की काली कमाई में लंबे समय तक इनकी बादशाहत रही। कोयला क्षेत्र का असली शासन तो इनके धनबाद

के सरायदेला-गोविंदपुर रोड स्थित 'सिंह मैशन' से ही चलता था। एक बार को छोड़ 1977 से झारिया विधानसभा सीट पर इन्हें के परिवार का कब्जा है। वे खुद चार बार जीते। बलिया का होन के कारण पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से सूर्योदेव सिंह की मित्रता थी। चंद्रशेखर 'सिंह मैशन' भी आते थे, 1990 में प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आए थे। एक बार तो जेल में सूर्योदेव सिंह से मिलने गए। सवाल उठा तो साफ कहा- किसी से मेरी दोस्ती रही है तो पढ़ पर पहुंच जाने के बाद उसे कैसे नकार सकता हूं।

कहा जाता है कि बलिया से लाया और लाठी लेकर धनबाद आने वाले सूर्योदेव सिंह कोल माफिया बिंदेशवरी प्रसाद सिन्हा (बीपी सिन्हा) के लैंटैट बन गए। कोयलांचल में एकछत्र राज चलाने वाले सिन्हा की 1978 में हत्या के बाद सूर्योदेव सिंह को बादशाहत हासिल हुई। आरोप सूर्योदेव सिंह पर भी लगा मगर अदालत से बरी हो गए। कहा जाता है कि कांग्रेस के मजदूर संघ इंटक में सिन्हा की तृती बोलती थी। एसके राय, राजदेव राय, सत्यदेव सिंह, नैरंगदेव सिंह, सूर्योदेव सिंह के साथ गैंग्स ॲफ वासेपुर के शफी खान भी उनके दरबार में हजिरी लगाते थे।

श्रमिक नेता पंडित बिंदेशवरी दुबे अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री बने तो माफिया और तमाम दबंग डॉ. जगन्नाथ मिश्र के पाले में चले गए। बाद में भागवत झा आजाद बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने माफिया और दबंगों के खिलाफ कड़े तेवर दिखाए। धनबाद में तब मदन मोहन झा उपायुक्त थे। उन्होंने माफिया और दबंगों का आर्थिक स्रोत खत्म करने का जोरदार अभियान चलाया। सूर्योदेव सिंह सहित कई माफिया के कब्जे की सरकारी संपत्ति जब्त की गई। कहते हैं, आजाद के जाते ही माफिया ने मिटाइयां बांट कर मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह का स्वागत किया। सूर्योदेव सिंह को पार्टी में भारी विरोध के बाद भी जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने टिकट दिला दिया था और वह झारिया से विधायक बन गए थे।

वर्तमान समय में कोयलांचल में हर दल में दबंगों का बोलबाला है। भाजपा और कांग्रेस में तो दबंग ही प्रभावशाली बन गए। कतरास कोयलांचल में सत्यदेव सिंह का प्रभाव खत्म होने के बाद सकलदेव सिंह और बिनोद सिंह का साप्राज्य स्थापित हुआ, मगर ये विरोधियों के हाथों मारे गए। फिलहाल, कतरास-बाघमारा क्षेत्र में भाजपा के दबंग विधायक दुल्लू महतो का सिक्का चलता है। रघुवर दास के मुख्यमंत्री रहते दुल्लू की दबंगई से सब त्रस्त थे। प्रशासन उनके खिलाफ किसी शिकायत को तबज्जो नहीं देता था। कोलियरी में कोयला लोडिंग के लिए दुल्लू को प्रतिटन के हिसाब से रंगदारी टैक्स देना पड़ता था। हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद से दुल्लू जेल में है। रामगढ़ और करीबी कोयला पट्टी में भोला पांडेय, सुशील श्रीवास्तव और अमन साव का गिरोह कोयला और रेलवे साइडिंग से वसूली पर वर्चस्व

के लिए टकराता रहता है। कथित नक्सली संगठन टीपीसी-टीएसपीसी (तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति समिति) ने भी वसूली में अपनी जगह बना ली है। अनिल शर्मा, अखिलेश सिंह, सुजीत सिन्हा जैसे हत्या-रंगदारी के दर्जनों मामलों के आरोपी अपनी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उनका कारोबार वर्ही से चल रहा है।

### गासेपुर की कहानी

धनबाद के इलाके वासेपुर पर ही गैंग्स ॲफ वासेपुर फिल्म बनी है। यह फहीम खान और साबिर खान के बीच गैंगवार की कहानी पर आधारित है। वासेपुर के ही जीशान कादरी की कहानी पर यह फिल्म बनी है। वासेपुर का किस्सा भी सूर्योदेव सिंह से शुरू होता है। 1980 के दशक में जेल के भीतर शफी खान और



### कतरास-बाघमारा क्षेत्र में भाजपा के दबंग विधायक दुल्लू महतो का दबदबा, कोयला दुलाई में रंगदारी वसूलता था, हेमंत सरकार आने के बाद जेल में

झारिया के तत्कालीन विधायक सूर्योदेव सिंह के बीच विवाद हुआ। बाद में 1983 में बरवा अड्डा पेट्रोल पंप पर फहीम खान के पिता शफी खान की हत्या कर दी गई। इल्जाम सूर्योदेव सिंह के सिर आया। उसके बाद जो गैंगवार का सिलसिला चला तो बीसियों लालों गिरें। शफी के बड़े बेटे शमीम को 1986 में धनबाद सिविल कोर्ट में और छोटे बेटे छोटा खान को रांगा टांड ग्वालापट्टी में विरोधी गुट ने ढेर कर दिया। 2010 में साबिर के भाई वाहिद की भी रांची में हत्या हो गई। भिड़ंत में फहीम और साबिर दोनों के परिवार और

गिरोह के कई सदस्य मारे गए। इसी क्रम में कांग्रेस नेता फजलू हक भी फहीम गिरोह की भेंट चढ़ गया। फहीम अभी हजारीबाग जेल में है।

कहते हैं, बिहार के एक समाजसेवी जर्मींदार ने वासेपुर के जंगल को कटवाकर मोहल्ला बसाया था, तब यहां की आबादी कोई डेढ़ सौ रही होगी। वहां सुल्तान, सूर्योदेव सिंह का हथियार बना। सुल्तान की हत्या के बाद उसका गिरोह कमज़ोर पड़ा। मगर छोटे-मोटे गिरोह अब भी जोर-आजमाइश करते रहते हैं। हां, पहले वाला खौफ का माहौल अब नहीं है।

### लैंटैट से डॉन का सफर

बिंदेशवरी प्रसाद सिन्हा बेगूसराय से 1950 में धनबाद आए थे। कोलियरी मालिकों में पैठ बनाने के बाद इंटक से जुड़कर अपनी दखल बढ़ाई। इनके पास कई कोयला खदानों का काम था। मजरूरों पर नियन्त्रण के लिए लैंटैटों की टीम बनाई, जिनमें बलिया से नौकरी की तलाश में आए सूर्योदेव सिंह और वासेपुर के शफी खान भी थे। बाद में सूर्योदेव सिंह ने अपने भाइयों को भी बुला लिया और कोयला कारोबारियों के बीच पैठ गढ़ी कर ली। 1970 के करीब ही विरोधियों को पछाड़ते हुए धनबाद में वर्चस्व कायम कर लिया था। यही दौर था कि शफी खान से उनकी अदावत शुरू हो गई थी।

1991 में सूर्योदेव सिंह आगा संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे थे, उसी दौरान हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनकी सलतनत पर कब्जे को लेकर आपस में ही टकराव शुरू हो गया। अनुज बच्चा सिंह ने उनकी राजनीतिक और जनता मजदूर संघ की विरासत पर कब्जा जामाया तो सूर्योदेव सिंह की पत्नी कुंती सिंह और बड़े बेटे राजीव रंजन विरोध में खड़े हुए। सबसे छोटे भाई राजन सिंह का परिवार बच्चा सिंह के साथ चला गया। राजन के पुत्र नीरज सिंह, सूर्योदेव के झारिया से विधायक पुत्र संजीव के खिलाफ एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धी बन गए। संजीव सिंह के खास रंजय सिंह की हत्या नीरज सिंह के निवास 'रघुकुल' के पास हुई तो कुछ दिनों बाद संजीव के आवास 'कुंती निवास' के सामने चार लोगों के साथ नीरज सिंह की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। नीरज की हत्या के हत्याकाल में संजीव जेल में है।

धनबाद में दो दशक से अधिक समय से पत्रकारिता कर रहे संजीव झा कहते हैं कि बीते विधानसभा चुनाव में संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह और नीरज सिंह की पत्नी पूर्णिमा सिंह झारिया विधानसभा सीट पर आमने-सामने थीं। जेठानी-देवरानी या कहें 'सिंह मैशन' और 'रघुकुल' की लड़ाई में पूर्णिमा सिंह विजयी हुई। अभी रघुकुल का पलड़ा भारी लग रहा है और शांति भी है। वैसे, कोयलांचल में कई और गिरोह हैं। जब तक सालाना अरबों रुपये का अवैध खेल चलता रहेगा, वर्चस्व को लेकर माफिया गिरोह टकराते रहेंगे, कभी कम-कभी ज्यादा।

# जय हो बॉलीवुड डॉन की!

हर दौर में फिल्मी परदे पर डॉन दर्शकों को लुभाते रहे हैं, फिल्मकार भी हमेशा ऐसी कहानियों की खोज में रहते हैं, जिन्हें बॉलीवुड के परदे पर उतारा जा सके



के.एन.सिंह और  
अजीत



गिरिधर झा

ल ही में निहायत भद्रेस नाटकीय अंदाज में एक सवालिया पुलिसिया ‘मुठभेड़’ में मारा गया उत्तर प्रदेश का अपराध सरगना विकास दुबे मुंबईया फिल्मों का दीवाना था। कहते हैं, उसने अर्जुन पंडित (1999) सौ से अधिक बार देखी थी, जिसमें सनी देओल खूंखार गैंगस्टर के किरदार में अपने कथित अन्याय का बदला लेने के लिए हथियार उठा लेता है। हैरतअंगोज वारदातों से भरी डॉन दुबे की जिंदगी भी किसी फिल्मकार के लिए भरपूर मसाला मुहैया करा सकती है। दरअसल कुछ तो नाम दर्ज कराने और पटकथा तैयार करने में जुट भी गए हैं। इसमें कोई हैरानी भी नहीं। आखिर बरसों से बॉलीवुड परदे पर अपराध जगत के सरगनाओं का महिमामंडन करता ही रहा है।



(ऊपर बाएं) डॉन में अमिताभ बच्चन, और धर्मात्मा में प्रेमनाथ, (नीचे बाएं) अग्निपथ में डैनी, और कंपनी में विवेक ओबेरॉय के साथ अजय देवगन

सच तो यह भी है कि हर रंग-तेवर के सरगनाओं के किस्से फिल्मकारों और दर्शकों को दीवाना बनाते रहे हैं। कैसे बरसों से बॉलीवुड के परदे पर कुछ खांटी डॉन आकार लेते रहे हैं, उसकी एक फेहरिस्तः

### सीटी बजाता डॉन

के.एन. सिंह बॉलीवुड परदे के शुरुआती डॉन थे, जैसे कोई निपट जाना-पहचाना दबंग, जिसे दर्शकों को खौफजदा करने के लिए बाहुबल नहीं दिखाना पड़ता, बल्कि थोड़ी बाहर-सी निकलीं आंखें तररते ही सिनेमा हॉल में खौफ उत्तर आता था। बागवां (1938) से लेकर कालिया (1981) तक के लंबे दौर में 'बॉस' का गजब अंदाज और खास अदा बाजी (1951) और हावड़ा ब्रिज (1956) जैसी यादगार फिल्मों में बुलंदी पर थी। न कोई छुटभैया हरकत, न कोई उल-जलूल पहनावा न भदा डायलॉग, वे इन चीजों से कुछ ज्यादा ही ऊपर थे। बस रात में एक हैट, गर्मी में ओवरकोट, भिंडी बाजार की संकरी गलियों में सिगार का कश उड़ाते अपनी खास शैली में सीटी बजाते वे काम तमाम कर देते थे।

### सफेदपोश डॉन

अजीत मुगल-आजम (1960) जैसी फिल्म में बेहतरीन अदाकारी का गुर दिखा चुके थे लेकिन

शायद यह बदा था कि उन्हें ऐसे स्टाइलिश खलनायक की तरह याद किया जाए, जो बंदूक वी शेरा और राका जैसे गुर्गों के बदले मनीष मल्होत्रा जैसों को साथ रखना पसंद करता था। दिलफेंक शोख अदा वाली 'मोना डालिंग' के संग खुश वह झक सफेद कपड़ों में ऐसे नमूदार होता, माने सीधे लॉन्ड्री से चला आ रहा हो। सबकी जुबान पर चढ़ गए 'सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है' जैसे डायलॉग की बेमिसाल अदायगी ने अजीत को डॉन के किरदार में हॉलीवुड के खलनायकों की बराबरी में ला खड़ा किया था। आखिर कौन दूसरा डॉन खदबदते एसिड का इनडोर पुल रखता रहा है, ताकि कोई उसके ठिकाने पर हीरोगीरी दिखाए तो निपटाया जा सके! वह ऐसा बेमिसाल डॉन था, जिसको लेकर न जाने कितने चुटकले हर जुबां और इंटरनेट पर बरसों छाए रहे हैं, खासकर तब जब, मीम का चलन नहीं शुरू हुआ था।

### गॉडफादर डॉन

द गॉडफादर (1972) की डुगडुगी बजने के पहले तक हिंदी सिनेमा के खलनायक पचासों रंग-रूप और तेवर से दर्शकों की नफरत और आकर्षण का केंद्र हुआ करते थे। मार्लन ब्रांडो की अदाकारी में कृपालु डॉन हर जरूरतमंद को बंदूक और वरदान

समान भाव से मुहैया करता है। उससे 'प्रेरणा' पाकर मुंबईया मायानगरी में फिरोज खान ने धर्मात्मा (1975) बना डाली। इस देसी संस्करण में प्रेमनाथ शीर्षक भूमिका वाले डॉन बने मगर उन्हें किसी 'नामधारी' पात्र या कहिए तब के किसी हकीकी डॉन जैसे हाजी मस्तान और करीम लाला के खांचे में नहीं ढाला गया था। इसके बदले, प्रेमनाथ के पात्र के लिए तब बंबई का 'मटका किंग' रतन खत्री जैसा किरदार लिया गया, जिसकी हाल ही में मौत हुई। फिरोज खान खुद अल पचोने वाली भूमिका में तालिबान के पहले के दौर में अफगानिस्तान में बायियान बुद्ध मूर्ति के ईर्द-गिर्द की सुहानी फिजा में 'एपोलोनिया' हेमा मालिनी के चक्कर काटते रहे।

### भगोड़ा डॉन

यूं तो बॉलीवुड के चोटी के कलाकार अशोक कुमार से लेकर देवानंद तक कई बार एंटी-हीरो की भूमिका में उतरे, मगर अमिताभ बच्चन ने ही चंद्रा बारोट की फिल्म डॉन (1978) में उसे फैशनेबल बनाया। अलबत्ता वे एक बौद्धम बनारसी के डबल रोल में भी थे, मगर स्टाइलिश डॉन के उनके किरदार ने ऐसी दिलचस्पी जगाई कि लाभग्न तीन दशक बाद सुपरस्टार शाहरुख खान डॉन: द चेज बिगिन्स (2006) में उत्तरने का लोभ संवरण नहीं कर पाए।

जगा सोचिए, इस भूमिका को कई शीर्ष कलाकारों ने नकार दिया था और फिल्म वितरक फिल्म के नाम को लेकर ही शक-शुबहे में थे, मगर दर्शक बिग बी के मुंह से निकले उस डायलॉग के मुरीद हो गए कि “‘डॉन’ को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।”

## परदे पर असली डॉन

1970 के दशक में बेहिसाब तस्करी पर बनी यश चौपड़ा की अमिताभ बच्चन की अदाकारी वाली दीवार (1975) के बारे में कहा जाता है कि वह हाजी मस्तान पर आधारित थी, मगर असली डॉन जैसे पात्रों पर तो फिल्में बनाने की शुरुआत काफी बाद में मणि रत्नप की नायकन (1987) से होती है, जिसमें कमल हासन 1980 के दशक के तुरीकोरिन के बाहुबली वरदराजन मुदलियार जैसे पात्र की भूमिका में थे। फिरोज खान ने उसकी रिमेक दयावान (1988) बनाई तो इस भूमिका में विनोद खना थे। यह डॉन भी नरम दिल का था, जो अपने अपराध से हासिल धन घर और बाहर दान में लुटाया करता था। यह डॉन अजब-गजब टिकानों से मूँछ ऐंठते बंदूक लहराते गुर्गों के बदले बड़े शहरों की झूगी-बस्तियों से अपना कारोबार आराम से चलाता है।

## खास मकसद के डॉन

द गॉफ़फ़ादर की देखा-देखी गैंगस्टर ड्रामा का शुरू हुआ खासा लोकप्रिय सिलसिला 1990 के दशक में परिदा (1989) जैसी फिल्मों तक जारी रहा। मुकुल आनंद की फिल्म अग्निपथ (1990) में खास मकसद वाले डॉन की भूमिका अमिताभ बच्चन ने बखूबी निर्भाई। बिग बी ने विजय दीनानाथ चौहान की भूमिका में ब्रांडो वाली शैली और सुर बदल दिए और अपने पुराने दिनों के एंग्री यंगमैन के तेवर में अदाकारी से राशीय पुरस्कार हासिल कर लिया। हालांकि, उसी फिल्म में कांचा चीना की भूमिका में चालाक, लकड़क लिबास में डैनी ऐसा लगा, मानो ‘लॉयन’ अजीत का टू-कॉर्पो हो, फर्क बस यह था कि उसका ठिकाना मड आइलैंड से नीले समुद्र वाले मॉरीशस में पहुंच गया था। उसका हितिक रोशन अभिनित नया संस्करण (2012) भले ही ज्यादा हिट रहा हो मगर पुरानी फिल्म की तो कोई सानी नहीं है।

## भद्रेस डॉन

अनुराग कश्यप जैसे निर्देशकों के आगमन के साथ अपराध जगत के डॉन से परदा खिसककर देहात और कस्बों के डॉन की ओर चला गया। अर्धसत्य

(1984) और परिदा (1989) में मेट्रो शहरों में अपराध-सियासी गठजोड़ से नए डॉन उभरे, मगर शूल (1999) जैसी फिल्मों में ये छोटे कस्बों से झुंड के झुंड नमूदार होने लगे। गले में गमछा लपेटे ये डॉन अपने शहरी बिरादरों के नाज-नखरों से दूर हैं और खांटी रंग-रूप दिखाने के लिए भद्रेस बोली भी जुबान पर जमकर लाते हैं। कश्यप की दो खंडों में गैंग्स ऑफ वासेपुर में अविभाजित बिहार के कोयलांचल में खूनी गैंगवार से देहाती डॉन का

जमा। रामगोपाल वर्मा की सत्या (1998) ने ट्रेंड सेट कर दिया। उसमें भीखू महात्रे की भूमिका में मनोज बाजपेयी ने “मुंबई का किंग कौन” जैसे डायलॉग से अपनी धाक जमा ली। संजय दत्त की वास्तव (1999) और वर्मा की कंपनी (2002) भी खूब चली। कंपनी दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच खूनी जंग पर आधारित बताई गई। अगला दशक भी हर तरह के मुंबईया डॉन का ही दौर था, बस उनकी कपीनगीरी थोड़ी कम थी। उसके बाद यह डॉन कथा धीरे-धीरे बॉक्स ऑफिस पर फीकी पड़ती गई।

## फैमिलीगाला डॉन

नई सहस्राब्दी में भी डॉन फैशन बदस्तूर बना रहा। फिल्मकारों को गैंगस्टर संस्कृति ऐसी भायी कि वे असली दुनिया के डॉन और उसके परिवारों तथा उससे जुड़े लोगों की बारीक छवि परदे पर उतारने को बेताब हो गए। विवेक आओबेरॉय शूटआउट एट लोखंडवाला (2007) में गैंगस्टर माया डोलास और रक्त-चरित्र (2010) में परीताला रवींद्रा की भूमिका में, जॉन अब्राहम शूटआउट एट वडला (2013) में गैंगस्टर मान्या सुर्वे, श्रद्धा कपूर हसीना पार्कर (2017) में दाऊद की बहन के टाइटिल रोल में थीं, जबकि अर्जुन रामपाल ने डैडी (2017) में अरुण गवली की भूमिका निर्भाई। हालांकि गैंगस्टर वाली कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिट गई, मगर फिल्मी डॉन से फिल्मकारों का नशा नहीं उतरा।

## दाऊद जैसे डॉन

दाऊद इब्राहिम बॉलीवुड का दीवान रहा है और 1980 के दशक में शारजाह क्रिकेट मैच के दौरान मुंबईया सितारों के साथ फोटो खिंचाने का उस पर नशा-सा सवार था। कई बरसों के अंतराल में बॉलीवुड परदे पर उसके कई क्लोन नमूदार हुए, मगर सबसे करीब दिवंगत ऋषि कपूर ही पहुंच पाए। डी डे (2013) में पाकिस्तान में रह रहे मराठी बोलने वाले इकबाल सेठ के किरदार में वे भगोड़े गैंगस्टर से काफी मिलते-जुलते हैं। इमरान हाशमी ने भी वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई (2010) में उसका किरदार किया। उसके पहले रिस्क (2007) में विनोद खना ने ऐसे डॉन का किरदार किया, जिसका सिक्का मुंबई में चलता है। हालांकि बॉलीवुड में बॉयोपिक का जुनून भी चढ़ा हुआ है, मगर अभी तक भगोड़े माफिया डॉन की जिंदगी और दौर को फिल्माने की कोई कोशिश नहीं हुई है। घबराइए नहीं असली या फिल्मी डॉन का सिलसिला जारी रहेगा। जय हो, परदे वाले डॉन की!



सत्या में भीखू महात्रे की भूमिका में मनोज बाजपेयी (ऊपर) श्रद्धा बनी हसीना पार्कर

ट्रेंड चल पड़ता है। इनकी पैठ डिजिटल दौर में भी बदस्तूर कायम है और अब एकदम ताजा वेब सीरिज के नए मैदान में उन्हें खुलकर निपट भद्रेस हिंदी में अश्लील विशेषणों के इस्तेमाल की खुली आजादी है, गूगल ड्रांस्लेशन की भी दरकार नहीं।

## अंडरवर्ल्ड डॉन

बॉलीवुड की अंडरवर्ल्ड से ऐसी करीबी है कि उसे परदे पर ज्यों का त्यों उतारना संभव है। मुंबई दंगों के बाद के दौर में परदे पर झुंड के झुंड अंडरवर्ल्ड डॉन किरदार उत्तर आए, मगर कुछ ही का सिक्का



राजेश कुमार

# कांवड़ बैठी, आर्थिकी ढप

**महामारी से सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा थमी, तो आस्था के साथ हजारों करोड़ के कारोबार पर ग्रहण**

रंची से नवीन कुमार मिश्र

**सा**वन बीता जा रहा है मगर उत्तर और पूर्वी भारत के कई हिस्से में भगवान शिव पर गंगा जल चढ़ाने के लिए हर वर्ष होने वाली कांवड़ यात्राओं पर भी कोविड महामारी का कहर बरपा। उत्तर में उत्तराखण्ड के हरिद्वार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के सुदूर इलाकों के अलावा पश्चिम बंगाल में कोलकाता से ताड़केश्वर और बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश से झारखण्ड के देवघर में बाबाधाम तक कांवड़ यात्राओं के कुछ जाने-पहचाने मुकाम हैं। हजारों के हुजूम में कांवड़ यात्रियों के इस सफर की करोड़ों रुपय की अनोखी अर्थव्यवस्था भी है और दूसरी आर्थिक गतिविधियों की तरह यह कारोबार भी जैसे कोरोना शाप का शिकार हो गया। कांवड़ यात्रा का सामाजिक असर भी लगातार बढ़ता गया है और पिछले कुछ साल से खास तरह के राष्ट्रवादी रुझान के लिए तिरंगे झंडे का इस्तेमाल भी कांवड़ियों के हाथों में देखे जाने लगे थे। सो, लोगों की आस्था को

ध्यान में रखकर उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों ने गंगाजल के कलश स्थानीय स्तर पर मुहैया कराने के बादे भी किए। यकीन, इस मामले में देवघर के बाबाधाम की महत्ता अनोखी है। लेकिन बिहार के सुल्तानगंज से झारखण्ड के देवघर जाने वाली सड़क इस बार सूरी है। हर साल इस मौसम में 105 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर कदम रखने तक की जगह नहीं होती

थी। हर तरफ बोलबम का नारा और गीत गूंजते थे। सावन के महीने में 45 से 50 लाख श्रद्धालु देवघर में शिवलिंग पर जलार्पण के लिए आते थे, लेकिन इस बार कांवड़ियों का सैलाब कहीं नजर नहीं आ रहा। कोरोना महामारी के कारण प्रशासन ने यहां पूरे सावन, यानी 4 अगस्त तक श्रद्धालुओं के आने और कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। सुल्तानगंज के गंगा घाट, जहां से जल लेकर कांवड़िये देवघर जाते हैं, वहां पुलिस का पहरा है। देवघर में भी पुलिस की सख्त घेराबंदी है। देवघर में कुछ पंडे कोरोना पॉजिटिव हो गए, इसलिए प्रशासन ने बाबाधाम मंदिर में पूजन के लिए सीमित संख्या में ही पंडों-पुजारियों को जाने की अनुमति दी है। आम लोगों के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई है।

बाबाधाम मंदिर के पंडा तथा धर्म रक्षिणी सभा के महामंत्री कार्तिक ठाकुर दर्शन और कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध के पक्ष में हैं। वे कहते हैं, “जान है तो जहान है। मेरे जैसा आदमी परहेज के बाद भी चपेट

में आ गया।” देवघर में करीब पांच हजार पंडों का परिवार है। पहले लॉकडाउन और अब श्रावणी मेले पर प्रतिबंध ने उन पर बड़ा अधिक प्रहार किया है।

आम तौर पर सावन में सुल्तानगंज-देवघर कांवड़िया पथ पर झारखंड के प्रवेश द्वार दुम्मा मोड़ से बाबाधाम, नौ किलोमीटर तक मेला लगा रहता है। सड़क की दोनों तरफ दुकानें और ठहरने की व्यवस्था होती है। रोजाना करीब एक लाख लोग बाबाधाम में शिवलिंग पर जलार्पण करते हैं। सोमवार को यह संख्या चार-पांच लाख तक पहुंच जाती है। करीब 60 फीसदी कांवड़िये यहां से 42 किलोमीटर दूर दुम्मा जिले में बासुकीनाथ के भी दर्शन करते हैं। भगवान्निवास में श्रद्धालु दिन-रात चलते दिखते हैं। किसी को जरा-सी तकलीफ हुई नहीं कि दूसरा अपरिचित साथी मदर को हाजिर हो जाता है।

प्रशासन और समाजसेवियों की व्यवस्था तो रहती ही है। चाय, भोजन, विश्राम, दवा-चिकित्सा, हर तरह की व्यवस्था।

यह कांवड़ यात्रा सिर्फ आस्था में डुबकी लगाने का धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस-पास के जिलों की अर्थव्यवस्था को भी यह गहरे प्रभावित करती है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्रीज के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आलोक मल्लिक के अनुसार प्रति यात्री औसतन दो हजार रुपये का खर्च आता है।

वस्त्र और प्रसाद से लेकर पूजन सामग्री, रेस्तरां आदि का सावन में एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार होता है, जो पूरी तरह ठप है। सालाना कारोबार का 80 फीसदी सावन में ही होता है। सुल्तानगंज से बासुकीनाथ तक 25 हजार से अधिक परिवारों के जीवनयापन का खर्च इसी श्रावणी मेले से निकलता है। इनकी चिंता है कि आगे इनका घर कैसे चलेगा।

बाबाधाम के प्रसाद की भी एक खासियत है। जलार्पण के बाद जब लोग लौटते हैं तो प्रसाद में पेड़ा, चूड़ा, बद्धी (धागा) जरूर होता है, हालांकि मंदिर में ये प्रसाद नहीं चढ़ाए जाते। स्थानीय पत्रकार मनोज केशरी बताते हैं कि देवघर में स्थायी रूप से सौ दुकानें होंगी मगर सावन में इनकी संख्या पांच हजार तक हो जाती है। देवघर से बासुकीनाथ के रास्ते घोरमारा का पेड़ा सबसे ज्यादा मशहूर है। यहां पेड़े की अनेक स्थायी दुकानें हैं, लेकिन इस बार ये भी सूनी हैं।

वर्षों से कांवड़ियों का मेला देख रहे भागलपुर (सुल्तानगंज इसी जिले में पड़ता है) के गिरधारी लाल जोशी ने बताया कि पहले सुल्तानगंज से 20-25 कांवड़ियों का जथा निकला था, मगर प्रशासन ने उन्हें वहां रोक दिया। पुलिस चारों तरफ तैनात है मगर

यात्रियों को रोकने के लिए। देवघर के सामाजिक कार्यकर्ता संजय भारद्वाज कहते हैं, “भागलपुर, देवघर, मुंगेर, बांका और दुमका के हजारों परिवारों के लिए यह श्रावणी मेला रोजी-रोटी का इंतजाम कर देता था। कोरोना के चलते लॉकडाउन और कांवड़ यात्रा पर पाबंदी ने लोगों की कमर तोड़ दी है।”

केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में ढील देते हुए जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की, तब भी झारखंड सरकार ने मंदिरों को खोलने की इजाजत नहीं दी। गोड्डा से भाजपा सांसद निश्चित दुबे चाहते थे कि

**कोरोना का असर: कांवड़ यात्रा (फाइल फोटो) पर रोक से सूना बाबा धाम (बाएं)**



फोटो: आइ

**सुल्तानगंज से बासुकीनाथ तक 25 हजार से अधिक परिवारों का जीवन इसी श्रावणी मेले पर निर्भर, इनकी चिंता है कि आगे घर कैसे चलेगा**

सावन में बाबाधाम मंदिर खोला जाए और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कांवड़ यात्रा को अनुमति दी जाए। उनकी चिंता उन हजारों परिवारों को लेकर भी थी जिनकी इसी मेले पर रोजी-रोटी निर्भर करती है। इसके लिए उन्होंने जनहित याचिका दायर की थी। लेकिन झारखंड उच्च न्यायालय ने इस पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के आदेश को बहाल रखा और सरकार को अनलाइन दर्शन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। उधर, बिहार सरकार ने भी धार्मिक न्यास बोर्ड की बैठक कर किसी भी मंदिर में जलाभिषेक, मेला या कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी

थी। जिस तरह देश में रोजाना हजारों लोग कोरोना महामारी की चपेट में आ रहे हैं और सैकड़ों की जान जा रही है, उसे देखते हुए यह पाबंदी सर्वथा उचित है। वर्ना जैसा कि धर्म रक्षणी सभा के कार्तिक ठाकुर कहते हैं, “कांवड़ यात्रा की इजाजत मिलता तो लाखों लोग आते और तब तो तबाही मचती।”

## फौजदारी बाबा के यहां हाजिरी जरूरी

देवघर से 42 किलोमीटर है बासुकीनाथ का शिव मंदिर। इन्हें फौजदारी बाबा भी कहा जाता है। स्थानीय निवासी प्रमोद कुमार बताते हैं कि मान्यता के अनुसार देवघर में जलार्पण के बाद यहां जलाभिषेक करने पर ही यात्रा पूरी होती है। इसलिए बाबाधाम की यात्रा करने वाले 60 फीसदी से अधिक लोग यहां आते हैं।

## किंवदंतियां और हकीकत

कांवड़ यात्रा कब शुरू हुई, इसे लेकर अलग-अलग किंवदंतियां हैं। एक मान्यता है कि समुद्र मंथन से निकले विष को पीने से शिवजी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसे दूर करने के लिए रावण ने तप के बाद कांवड़ में जल लाकर शिवजी का जलाभिषेक किया। इससे विष के प्रकोप से शिवजी को मुक्ति मिली, तब से यह परंपरा चली आ रही है। दूसरी मान्यता यह है कि भगवान राम ने सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगाजल लाकर बाबाधाम में जलाभिषेक किया

था। एक मान्यता यह भी है कि श्रवण कुमार ने अपने नेतृत्व माता-पिता को कांवड़ में बैठा कर हरिद्वार में गंगा स्नान कराया और गंगा जल लेकर आया था, तब से इसकी शुरुआत हुई।

वैसे, देवघर में भगवान शिव के जलाभिषेक की परंपरा के कम से कम दो सौ साल पुरानी होने के लिखित सबूत हैं। वरिष्ठ पत्रकार डॉ. ब्रजेश वर्मा ने अपनी पुस्तक राजमहल में इसका जिक्र किया है। डॉ. वर्मा के अनुसार 1794 से 1815 तक बंगाल चिकित्सा सेवा में रहे स्कॉर्टिश डॉक्टर फ्रांसिस बुकानन ने सुल्तानगंज के बारे में लिखा है कि वे 21 फरवरी 1811 को सुल्तानगंज पहुंचे थे। वहां उन्होंने अनेक कांवड़ियों को कंधे पर जल उठाए देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर की यात्रा करते देखा था।

ऐतिहासिक-पुरातात्त्विक महत्व के विषयों पर काम करने वाले लेखक संजय कृष्ण के अनुसार आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी नरेश के साथ बाबाधाम की यात्रा की थी, जिसका विस्तृत वर्णन 1880 में हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका में छपा था। स्वामी विवेकानंद भी यहां 1887 से 1890 के बीच सात बार आए। इस दौरान अखंडानंद जी के साथ बाबाधाम के दर्शन भी किए।

# बिजनेस लाओ, चाहे जान गंवाओ

निजी और सरकारी बैंक कर्मचारियों पर बिजनेस लाने का बढ़ा दबाव तो कोरोना से 2,000 से ज्यादा संक्रमित और 57 की मौत

◀ प्रशांत श्रीवास्तव

**आ**पका फोन घनघनाता है और दूसरी तरफ से आवाज आती है, “सर आपको कोई लोन की जरूरत है, प्लीज ले लीजिए, बहुत प्रेशर है। हम जानते हैं कि कोरोना में सब कुछ ठप है लेकिन फिर भी कुछ लोन ले लीजिए।” कोविड-19 के दौर की यह बैंकिंग दुनिया है, जिसमें ठप पड़ी अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस लाने का कर्मचारियों पर दबाव भारी है। यह दबाव निजी ही नहीं, सरकारी क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों पर भी ऐसा भारी है कि वे इस चक्कर में कोरोना संकट की चपेट में आ रहे हैं और कुछ जान भी गंवा रहे हैं। इन पक्षियों के लिखे जाने तक नेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स के मुताबिक देश भर में 2,000 से ज्यादा बैंक कर्मचारी कोरोना संक्रमण लगा चैटे हैं और 57 मौत के शिकार हो चुके हैं। बढ़ते खतरे और दबाव का असर है कि कर्मचारियों में डर और गुस्से का माहौल है।

दरअसल, गिरता बिजनेस संभालने के लिए बैंक कर्मचारियों पर ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट लाने और ज्यादा कर्ज देने का दबाव बना रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, “इस समय कोविड की वजह से न केवल बैंक में लोगों का आना कम है, बल्कि सारी गतिविधियां ठप हैं। फिर भी कर्मचारियों को सामान्य दिनों जैसे ही टारगेट दिए जा रहे हैं। ऐसे महीने में कैसे कोई टारगेट पूरा कर सकता है। इस दौर में बिजनेस में 20-25 फीसदी की ग्रोथ बहुत मुश्किल है। इसके अलावा क्रॉस सेलिंग का भी दबाव है। यानी आपको केवल अपने ग्राहकों से डिपॉजिट लेने और उन्हें कर्ज देने का काम नहीं करना है, बल्कि बीमा और एन्सुअरेंस फंड सहित दूसरे उत्पादों की भी बिक्री कराने का दबाव है।” शिकायत यह भी है कि कोरोना पॉजिटिव होने पर केवल 20 हजार रुपये का इलाज खर्च मिल रहा है और मौत होने पर 20 लाख रुपये का बीमा कवर है। हालांकि कोरोना योद्धा के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 50 लाख रुपये का बीमा कवर दिया जा रहा है। वे पूछते हैं, “सबाल है कि कोविड-19 के दौर में लगातार काम कर रहे बैंक कर्मचारी क्या कोरोना योद्धा नहीं हैं? यह सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है?”



## सर्वाधिक मौतें महाराष्ट्र में

राज्य	मृतक कर्मचारियों की संख्या
असम	1
बिहार	3
दिल्ली	6
गुजरात	8
जम्मू-कश्मीर	1
केरल	1
महाराष्ट्र	21
तमில்நாடு	3
तेलंगाना	3
उत्तर प्रदेश	6
पश्चिम बंगाल	3
अन्य	1

स्रोत: वॉर्कस ऑफ बैंकिंग

## सरकारी बैंककर्मी ज्यादा शिकार

बैंक	कोरोना से मृत कर्मचारियों की संख्या
बैंक ऑफ बड़ौदा	3
बैंक ऑफ इंडिया	3
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1
कैबरा बैंक	4
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	5
आईडीवीआई बैंक	3
इंडियन बैंक	3
पंजाब नेशनल बैंक	6
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	1
भारतीय स्टेट बैंक	18
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2
यूको बैंक	2
कोऑपरेटिव बैंक	1
निजी बैंक	2
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	3
<b>कुल</b>	<b>57</b>

**सवाल:** स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी कोरोना योद्धा हैं तो बैंककर्मी क्यों नहीं

स्रोत: व्यापक ऑफ बैंकिंग

रहा है कि उससे एफडी करवाओ, या कुछ नहीं तो पर्सलन लोन ही दिलवाओ।

बैंक कर्मचारियों का कहना है कि लोगों की सेवा करते हुए वे कोरोना वायरस के प्रकोप से गंभीर चुनौतियों और जोखिम का समना कर रहे हैं। इस दौरान, 57 बैंक कर्मचारियों को कोविड-19 के कारण जान से हाथ धोना पड़ा है। इन कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को आर्थिक मदद के साथ मुआवजा दिया जाना चाहिए और उनके आश्रितों को नौकरी दी जानी चाहिए। इसके अलावा बैंक, कर्मचारियों से जुड़े कई नियमों की अनदेखी भी कर रहे हैं।

मसलन, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने सलाह दी थी कि सार्वजनिक बैंकों के गर्भवती, विकलांग, होम क्वारंटीन और अधिक जोखिम वाले कर्मचारियों के लिए लॉकडाउन अवधि के दौरान विशेष छूट दी जाए। उनको विशेष अवकाश बिना बेतन कटौती के दिए जाएं। लेकिन उस सलाह को दरकिनार कर कई बैंकों ने ऐसे कर्मचारियों को भी शाखाओं में ड्यूटी पर आने को मजबूर किया। लॉकडाउन अवधि के दौरान कई

बैंकों ने बड़ी संख्या में अंतरराज्यीय स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं, जिन्हें रद्द किया जाना चाहिए। यही नहीं, एक प्रमुख निजी बैंक के अधिकारी के अनुसार कई ऐसे निर्देश दिए जा रहे हैं, जो जमीनी हकीकत से एकदम अलग हैं। लखनऊ में काम करने वाले एक अधिकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण की वजह से कई बड़ी शाखाएं बंद कर दी गई हैं, ऐसे में उन शाखाओं में कर्मचारी नहीं पहुंच रहे हैं। इसके बावजूद शीर्ष प्रबंधन

से ऐसे आदेश दिए जा रहे हैं, जो बिना शाखा गए संभव नहीं हैं। ऐसे में कर्मचारियों पर ही दबाव पड़ेगा।

पंजाब नेशनल बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि असल में कोविड-19 का दौर काफी संकट भरा है। ऐसे दौर का कभी किसी ने सामना नहीं किया था। अर्थव्यवस्था में सुस्ती का असर बैंकों के बिजनेस पर पड़ना लाजिमी है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार कोविड-19 की वजह से चालू वित वर्ष में बैंकों के कर्ज की दर तेजी से गिरने वाली है। पिछले वर्ष क्रेडिट ग्रोथ 6.14 फीसदी थी, जो इस साल केवल एक फीसदी रहने का अनुमान है, जबकि कोविड के पहले इसके 8-9 फीसदी रहने का अनुमान था। इसी तरह ढूबत खाते के कर्ज (एनपीए) 1.9 फीसदी बढ़ने की आशंका है।

जाहिर है, न केवल बैंक कर्मचारी बल्कि बैंकिंग बिजनेस भी संकट से गुजर रहा है। ऐसे में जरूरत तालमेल बैठाने की है क्योंकि अर्थव्यवस्था का बड़ा दारोगदार बैंकिंग व्यवस्था पर टिका हुआ और वह डगमगायी तो असर पूरी अर्थव्यवस्था पर होगा।

**बैंकरों पर डिपॉजिट को लेकर भी दबाव है, वे कर्स्टमर ये ज्यादा डिपॉजिट के लिए कहते हैं तो जवाब होता है- कोरोना में पैसे की बात मत करिए**



# आत्मनिर्भरता अभी दूर

फिलहाल चीन पर निर्भरता कम करने के लिए उद्योगों का रुख ताइवान, वियतनाम और यूरोपीय देशों की ओर

## चंडीगढ़ से हरीश मानव

### सी

मा पर भारतीय और चीनी सेना में हुई खूनी झड़प के बाद तनाती में जिस तरह से देश में आत्मनिर्भरता के सुर तेज हुए हैं, उतनी तेजी से

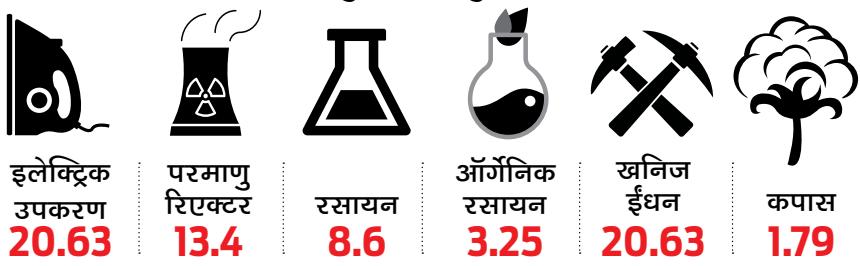
आत्मनिर्भरता पर अमल करना आसान नहीं है। 21 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा और 'वोकल फॉर लोकल' के प्रचार के बीच रातों-रात चीन पर निर्भरता खत्म करना न तो सरकार के बस में है, न ही कारोबारी जगत के। कारण यह है कि भारत और चीन के आपसी कारोबार का संतुलन चीन के पक्ष में बहुत ज्यादा छुका हुआ है। भारत चीन से जितना आयात करता है, उसकी तुलना में उसे करीब 25 फीसदी निर्यात करता है। अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 के बीच भारत ने चीन को 14.42 अरब डॉलर का निर्यात किया था, जबकि इस दौरान चीन से आयात 57.93 अरब डॉलर का हुआ है। कोविड-19 महामारी के चलते घटे कारोबार से चातू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में चीन की जीडीपी में 6.8 फीसदी गिरावट आई है, जबकि 2020 में, भारतीय अर्थव्यवस्था में आईएमएफ का अनुमान 4.5 फीसदी गिरावट का है।

अभी भारत की चीन पर निर्भरता कापी है। चीन की कंपनियों ने 225 भारतीय कंपनियों में निवेश कर रखा है। फार्मस्यूटिकल जैसे अहम औद्योगिक कलस्टर की 70 फीसदी निर्भरता चीन से आयातित एपीआइ (एक्टिव फार्मस्यूटिकल्स इन्फ्राइंटर्स) पर है। आत्मनिर्भरता पर स्वर्देशी रंग चढ़ाना भी इतना आसान नहीं। अभी तक चीन से आयात पर निर्भर हिमाचल प्रदेश के बड़ी स्थित फार्मा कलस्टर, पंजाब के लुधियाना स्थित यॉर्न और साइकिल कलस्टर और जालंधर के खेल सामान कलस्टर ने अब ताइवान, वियतनाम और यूरोपियन यूनियन के देशों का रुख

सालाना 8,000 करोड़ रुपये के साइकिल उद्योग में 90 फीसदी हिस्सेदारी वाले लुधियाना के कारोबारियों का कहना है कि चरणबद्ध तरीके से आयात पर निर्भरता खत्म की जा सकती है। ऑल इंडिया साइकिल मेन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के महासचिव के.बी. ठाकुर का कहना है कि साल दर साल चीन से बढ़ता आयात पहली बार इतनी तेजी से गिरा है। पहले तो कोरोना के चलते नवंबर 2019 से ही चीन से साइकिल का आयात लगभग ठप था, अब सीमा पर तनाती के बीच चीन के साथ कारोबार के खिलाफ महालै बना है। फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेन शाह का कहना है, कि एकदम से भारत में चीनी वस्तुओं का बहिष्कार लगभग असंभव है। चीन से आयातित कई वस्तुओं पर डंपिंग ड्यूटी बढ़ाकर वियतनाम, थाइलैंड, बांगलादेश, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर से आयातित वस्तुओं पर ड्यूटी घटाने से चीन पर निर्भरता कम की जा सकती है।

70 फीसदी पुर्जे चीन से आयात कर साइकिल असेंबल करने वाले लुधियाना के छोटे-मझोले कारोबारियों की आयात पर निर्भरता कम करने के

## चीन से आयातित प्रमुख वस्तुएं



लिए यहां की बड़ी कंपनियां भी तकनीकी मदद के लिए आगे आई हैं। हीरो साइकिल्स के एमडी एस.के. राय ने आउटलुक को बताया, "यहां के तमाम छोटे और मझोले उद्यमियों को तकनीकी मदद के लिए हम तैयार हैं। इसके लिए यूनाइटेड साइकिल पार्ट्स एंड मेन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (यूसीपीएमए) के सदस्यों के साथ बैठक में चीन पर निर्भरता चरणबद्ध तरीके से कम करने की रणनीति बनाई गई है।" राय का कहना है कि छोटे और मझोले कारोबारियों को चीन से आयातित पुर्जे से तैयार हुए परंपरागत काले रोडस्टर साइकिल की बजाय हाइएंड साइकिल तैयार करनी चाहिए, इसके लिए हम मदद करने को तैयार हैं।

चीन पर निर्भरता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अनेक वस्तुएं भारत में अभी तैयार नहीं की जा रही हैं। यूसीपीएमए के पूर्व अध्यक्ष चरणजीत सिंह विश्वकर्मा

**जिम का विकल्प:** लॉकडाउन की वजह से जिम बंद हैं, ऐसे में बड़ी साइकिल की मांग



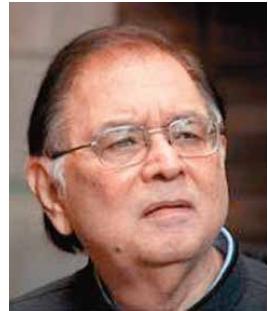
ने बताया कि प्रति माह एक लाख से अधिक हाइएंड साइकिल का चीन से आयात इसलिए हो रहा था, क्योंकि यहां इनके एलॉय, फाइबर और कार्बन फ्रेम का अभी तक उत्पादन नहीं हो रहा है। साइकिल फ्रेम और इनके गियर शिफ्टर, ब्रेक और विलपर का धरेलू उत्पादन जरूरी है। भारत में सालाना 2.20 करोड़ साइकिलें बनती हैं, इनमें से मात्र पांच फीसदी का नियांत होता है, जबकि चीन हर साल नौ करोड़ साइकिल उत्पादन कर उसमें से छह करोड़ का नियांत करता है।

भारत के कई उद्योग चीन से आयात पर निर्भर हैं। इसे कम करने से पहले स्टील, ऑयल एंड गैस, फार्मा, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और केमिकल उद्योगों के लिए विकल्प तलाशना होगा। भारत मोबाइल हैंडसेट, टीवी सेट और कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के मामले में भी चीन पर निर्भर है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के सालाना 76,300 करोड़ रुपये के कारोबार में 45 फीसदी चीन से आयात होता है। भारत के 5.30 लाख करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में चीन का सिर्फ छह फीसदी नियांत होता है, जबकि आयात में 67 फीसदी निर्भरता चीन पर है। भारत के ऑटोमोबाइल पुर्जों की जरूरत का 30 फीसदी चीन से आता है। दवा बनाने के लिए 53 तरह के 70 फीसदी एपीआई के लिए भारतीय दवा कंपनियां चीन पर निर्भर हैं। इसी तरह, मेडिकल उपकरणों के आयात में भी चीन की अहम

**यूनाइटेड साइकिल पार्ट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की बैठक में चीन पर निर्भरता चरणबद्ध तरीके से कम करने की रणनीति बनाई गई है। छोटे और मझोले उद्यमियों को तकनीकी मदद के लिए हम तैयार हैं**

**एस.के. राय**

एमडी, हीरो साइकिल्स



की बचत हो सकती है। चीन के सरकारी ऑकड़ों के मुताबिक 2019 में भारत और चीन का आपसी कारोबार 92.68 अरब डॉलर का रहा, जो 2018 में 95.7 अरब डॉलर का था। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें करीब 70 फीसदी गिरावट की संभावना है। हालांकि इसमें कोविड महामारी का बड़ा योगदान है।

### चीनी साइकिल पर ब्रेक, स्टॉक का संकट

लॉकडाउन के बाद कारोबार पटरी पर लाने की सरकार और कारोबारियों की कोशिशों के बीच लुधियाना के साइकिल उद्योग ने रफ्तार पकड़ी है। एक मई से 15 जुलाई तक ढाई महीने में साइकिल की मांग में 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। लॉकडाउन खत्म होने के बावजूद जिम नहीं खुले हैं, इसलिए शहरों में साइकिलिंग का रुझान तेजी से बढ़ा है।

बिक्री बढ़ने और चीन से हाइएंड साइकिल का आयात लगभग ठप होने से यहां की साइकिल कंपनियों के पास इन साइकिलों के कई मॉडल्स के स्टॉक खत्म हो गए हैं। एवन साइकिल के चेयरमैन ऑंकार पाहवा ने बताया, “लॉकडाउन के बाद कई वजहों से साइकिल की मांग में तेजी देखी गई है। कोरोना के डर से लोग जिम से दूर हैं। पहली बार जिम के विकल्प के रूप में साइकिल को देखा जा रहा है, जिससे मांग में भारी इजाफा हुआ है।” ऑल इंडिया साइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक, मांग में अप्रत्याशित तेजी के बीच सीमित प्रोडक्शन के चलते साइकिल निर्माता मांग पूरी करने में असमर्थ हैं। एसोसिएशन के महासचिव केबी ठाकुर ने बताया कि मई में साइकिल निर्माताओं ने 35 फीसदी श्रमिकों के साथ करीब 4.5 लाख साइकिल का उत्पादन किया, जबकि जून में 65 फीसदी उत्पादन क्षमता का उपयोग कर करीब 8.5 लाख साइकिल का उत्पादन हुआ है।



## चीन पर उद्योग की निर्भरता

**75% सोलर पैनल**

**70% फॉर्मा एपीआई**

**50% कीटनाशक**

**45% कंज्यूमर ड्यूरेबल**

**44% प्लास्टिक**

**38% चमड़ा**

**34% पेट्रोकेमिकल**

**30% टायर**

**27% यॉर्न**

**17% स्टील**

# ओली की ऐसी क्यों बोली

नेपाली प्रधानमंत्री के भारत विरोधी तेवर का राज उनकी घरेलू परेशानियां या भारत की नेपाल नीति की नाकामी

हरिमोहन मिश्र

**स**हसा विश्वास नहीं होता कि नेपाल या कहें कि वहां के प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली (के.पी. ओली) की बोली ऐसे बदल जाएगी। आखिर नेपाल हमारा पड़ोसी देश भर नहीं, उससे हमारे “रोटी-बेटी” के संबंध रहे हैं, जैसा कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में कह चुके हैं। लेकिन विडंबना देखिए, नेपाल के इस नए तेवर में राजनाथ सिंह की भी एक भूमिका है। उन्होंने इस साल 8 मई को उत्तराखण्ड से कालापानी-लिपुलेख के जरिए कैलाश मानसरोवर के एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया तो नेपाल के मौजूदा गरम तेवरों की शुरुआत हुई। उसने न सिर्फ कालापानी-लिपुलेख पर अपना दावा किया, बल्कि अपनी संसद में एकमत से उसे अपने नए नक्शे में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया। ओली की बोली लगातार तीखी होती गई। मार्क्सवाद में यकीन करने वाले ओली को हिंदू अस्मिता की भी याद आ गई। उन्होंने दावा कर दिया कि राम की अयोध्या भी नेपाल में है। यह सब तब हो रहा था जब लद्धाख की गलवन नदी घाटी में चीनी सेना और हमारे जवान आमने-सामने थे। इससे कई सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो उठे। क्या यह हमारी नेपाल नीति की नाकामी है? क्या नेपाल चीन के उक्साके में ऐसा कर रहा है? क्या ओली अपनी पार्टी में मिल रही चुनौती और घरेलू नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए भारत-विरोधी रुख अपना रहे हैं?

नेपाल हमारे लिए इतना अहम है कि किसी भी



सवाल को खारिज नहीं किया जा सकता। इसमें दो राय नहीं कि पिछले कुछ साल से नेपाल की नागरिकी बढ़ती गई है। हालांकि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काठमांडू यात्रा के दौरान ऐसी फिजा तैयार हुई थी कि वहां भारत की जय-जय होने लगी थी। उसके बाद नेपाल के नए गणतांत्रिक संविधान से तराइ में बसने वाले मधेसी लोगों में असंतोष भड़का, जिनके साथ सीमाई इलाकों में भारत के लोगों के साथ सामाजिक और शादी-ब्याह के रिश्ते हैं। मधेसी आंदोलन शुरू हुआ तो भारत ने सीमा पर नाकेबंदी कर दी, जिससे वहां जरूरी सामान की आपूर्ति रुक गई। ऐसे दौर में चीन ने नेपाल की ओर हाथ बढ़ाया और वहां से सभी जरूरी सामान की आपूर्ति होने लगी। तब ओली प्रधानमंत्री थे। चौतरफा विरोध से ओली को इस्तीफा देना पड़ा। संविधान लागू होने के बाद हुए चुनाव-प्रचार के दौरान ओली ने भारत की नाकेबंदी को मुद्दा बनाया और कहा कि वे सामान आपूर्ति के लिए एक पक्ष पर निर्भर नहीं रहेंगे। उसके बाद हुए चुनावों में ओली अपनी पार्टी को भारी बहुमत से जिताने में कामयाब हुए। उधर, नेपाल में चीन की पैठ लगातार बढ़ती गई और ओली उसकी ओर झुकते गए। उसके बाद भी भारत की नेपाल नीति में कोई फेरबदल नहीं

**नेपाल में चीन की पैठ बढ़ने और ओली के चीन की ओर झुकने के बावजूद भारत ने नेपाल नीति नहीं बदली, इससे नेपाल की शिकायत बरकरार**

**दोस्ती का हाथ:** नेपाल में चीन की राजदूत हुया यांकी के साथ प्रधानमंत्री के.पी. ओली

हुआ और नेपाल की शिकायत बनी रही कि भारत बड़े भाई जैसा बर्ताव कर रहा है।

लेकिन ओली का संकट इधर कुछ समय से घरेलू भी है, खासकर उनके भारत विरोधी तीखे रुख के बाद उन्हें अपनी ही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में सहयोगी पुष्य कमल दहल प्रचंड से चुनौती मिल रही है। प्रचंड का रुख पहले भले चीन की ओर नरम था, लेकिन अब वे भारत से संबंध बुरी तरह खराब कर लेने के लिए ओली को दोषी ठहरा रहे हैं और उनके इस्तीफे पर अड़े हैं। ऐसे ही हालात में चीन की अहम पहल शुरू हुई। नेपाल में चीन की राजदूत हुया यांकी ने बीच-बचाव किया। यांकी के हस्तक्षेप से ओली को जरूर कुछ मोहलत मिल गई, लेकिन अभी कोई पुख्ता रास्ता नहीं निकल पाया है।

इस बीच ओली ने एक नया राग छेड़ दिया। उन्होंने कहा, “अयोध्या को लेकर तीखी बहस जारी है। दरअसल अयोध्या ठारी में है, जो पश्चिम में नेपाल के बीरगंज के पास है। दशरथ के लिए पुत्रेष्ठि यज्ञ कराने वाले ऋषि भी रीदी (नेपाल) के थे। इसलिए राम भारतीय नहीं थे, न जन्मस्थान (अयोध्या) भारत में था। हमें सांस्कृतिक रूप से दबाया गया, तथ्य बदले गए। हम आज भी यही मानते हैं कि सीता का विवाह एक भारतीय राजकुमार के साथ हुआ था लेकिन ऐसा नहीं है। अयोध्या बीरगंज के पास एक गांव है।” उनका यह दावा भारत के खिलाफ है या अपनी पार्टी में मिल रही चुनौतियों के खिलाफ, यह तो समय ही बताएगा लेकिन भारत के लिए जरूरी है कि नेपाल चीन की गोद में पूरी तरह न जाए।

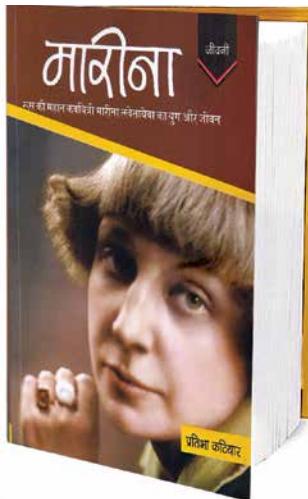
# सत्ता गई, कवयित्री बची रही

## प्रियदर्शन

**बी** सर्वों सदी के शुरुआत में उभरी रूसी कवयित्री मारीना त्वेतायेवा का जीवन बहुत त्रासद रहा। वह एक कुलीन परिवार में जन्मी, भावावेग से भरी कवयित्री थी। उसके पांते सेर्गेई अपने प्रारंभिक वर्षों में वाइट आर्मी में थे, यानी जार के साथ। बेशक, बरसों बाद उनके सेवियत सीक्रेट एजेंट होने की बात निकली, लेकिन जेल और यातनाएं तब भी उसकी जिंदगी में बने रहे। बहुत सारे निजी पारिवारिक कष्टों के बीच रूस की उथल-पुथल में मारीना का सब-कुछ नष्ट होता चला गया। वह करीब ढेढ़ दशक रूस के बाहर रहने को मजबूर हुई। बरसों वह खाने को मोहताज रही। ऐसी भी नौबत आई कि किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उसे कपड़े मांगने पड़े। एक बार जूते फट जाने की वजह से वह एक कार्यक्रम में नहीं जा पाई। उसकी एक बेटी अनाथालय में भूख से मर गई।

यह हिला देने वाली कहानी किसी ऐसी कवयित्री की नहीं है, जिसे कोई न जानता हो। मारीना को मायाकोव्स्की जानते थे, पास्तरनाक और रिल्के उससे प्रेम करते थे, अन्ना अखमातोवा उसकी दोस्त थी, ब्लॉक और गोर्की उसके काम से परिचित थे। रूस और रूस के बाहर बहुत सारे लेखक उसके लेखन से खूब वाकिफ थे।

लेकिन रूसी क्रांति के बाद, खासकर स्टालिन के लंबे दौर में जिन लोगों ने रूस में साहित्य-संस्कृति के संरक्षण का बीड़ा उठाया था, वे अपने विचारधारात्मक आग्रहों के दबाव या फिर स्टालिन



## मारीना

प्रतिभा कटियार

प्रकाशक | संवाद प्रकाशन

पृष्ठ: 272 | मूल्य: 300 रुपये

के आतंक की वजह से मारीना की मदद करने को तैयार नहीं हुए। बरसों बाद जब मारीना रूस लौटी तब उसके हालात बुरे होते चले गए और एक इतवार अवसाद और तनाव के बीच उसने खुदकुशी कर ली। मारीना को सेवियत सत्ता प्रतिष्ठान ने भुला देने की बरसों कोशिश की, लेकिन स्टालिन की मौत के बाद जब वहां व्यवस्था में

कुछ लचीलापन लौटा तो सत्तर के दशक में मारीना का काम नए सिरे से प्रकाश में आया।

यह सारी कहानी हिंदी की एक कवयित्री प्रतिभा कटियार ने लिखी है। हिंदी में इसके पहले मारीना त्वेतायेवा का काम वरयाम सिंह के अनुवाद में कुछ चिट्ठियां कुछ कविताएं नाम से पहले आ चुका है। दरअसल प्रतिभा का मारीना से पहला परिचय इसी किताब के जरिए हुआ। लेकिन मारीना की कोई संपूर्ण जीवनी हिंदी में पहली बार लिखी गई है। खास बात यह है कि इस जीवनी में जितनी वस्तुनिष्ठा है उतनी ही आत्मनिष्ठा भी। प्रतिभा कटियार जैसे बीच-बीच में अपनी प्रिय कवयित्री से बतियाती चलती है। अलग-अलग अध्यायों के अंत में छोटी-छोटी 'बुक मार्क' जैसी टीपें पूरी किताब को आसीय स्पर्श ही नहीं देतीं, यह भी बताती हैं कि कैसे किसी दूसरे देश और दूसरी सदी की कवयित्री के साथ कोई लेखिका ऐसा सच्य भाव विकसित कर सकती है जिसमें वह बिलकुल उससे संवादरत हो, बारिश में उसके साथ चाय पीने की कल्पना करे और उसके दुख से दुखी हो। दरअसल किताब इसी संलग्नता से निकलती है, इसलिए छूती है।

हालांकि किताब के कुछ अध्याय और बड़े होते तो अच्छा होता। खासकर रूसी क्रांति के समय की उथल-पुथल के बीच होने वाले सांस्कृतिक विस्थापन की विडंबना को और पकड़ने की जरूरत थी। किताब में पूफ और संपादन की असावधानियां भी खलती हैं। लेकिन ऐसे खलल के बावजूद यह हिंदी के समकालीन संसार की एक महत्वपूर्ण किताब है। हिंदी में ऐसी जीवनियां कम हैं। इसकी मार्फत एक विलक्षण कवयित्री के त्रासद जीवन पर और इस जीवन की मार्फत साहित्य और सत्ता के अंतर्संबंधों से बनने वाली विडंबना पर भी रोशनी पड़ती है।



## बिहार की लोककथाएं

संपादक: रणविजय राव  
प्रकाशक | राष्ट्रीय पुस्तक न्याय  
पृष्ठ: 150 | मूल्य: 175 रुपये

वन्य जीवों से जुड़ी कहानियां हैं, तो कहीं राजा, राजकुमार, राजकुमारी की कहानियां।

नैतिकता का संदेश देने वाली कहानियां भी संग्रह में मौजूद हैं।

संपादक ने लोककितियों-मुहावरों का प्रयोग ज्यों का त्यों रखा है। 'जांता' शब्द का प्रयोग ग्रामीण जनजीवन और कृषि सभ्यता से परिचय कराता है। 'जांता' में गेहूं पीसते समय जो हंसी-मजाक भरा वातावरण ग्रामीण जनजीवन की पहचान है, संपादक ने इसे याद दिलाया है।

# लोकोक्तियों का लौटना

## डॉ. रमेश तिवारी

**क** हानी कहने-सुनने की परंपरा सभ्यता के अरंभ से ही समाज में रही है। इसी कड़ी में बिहार की सामाजिक जनश्रुतियों और मिथकों से लोक कथाओं के रूप में हमारा साक्षात्कार कराने वाली कृति बिहार की लोककथाएं उल्लेखनीय है। इसमें बिहार के जनजीवन और वहां की मान्यताओं, भाषा-शैली की मिठास, ग्रामीण जनजीवन की सोंधी खुशबू है। सहजता और जीवंतता ही लोक कथाओं का प्राणतत्व है। किसी भी लोक और उसकी

कहानियों या साहित्य को समझने के लिए हमें उस लोकभाषा को, उसके तेवर को जानना जरूरी होता है। भाषा के मिजाज को समझे बगैर आप उसकी खूबसूरती को नहीं समझ पाएंगे और इसके अभाव में कहानी का आनंद प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे।

इस कृति में कुल 42 कहानियां संकलित हैं। इन कहानियों में ग्रामीणजनों की समझदारी, कहीं



# “न सितारे

स्ट्री-केंद्रित सिनेमा में विद्या बालन ने अपनी खास पहचान बनाई है। 2011 में उनकी हिट फिल्म द डर्टी पिक्चर के बाद उनके खाते में कई व्यावसायिक सफलताएं हैं। नो बन किल्ड जेसिका (2011), कहानी (2012) से लेकर तुम्हारी सुलु (2017) और मिशन मंगल (2019) तक उन्होंने कई चर्चित फिल्में की हैं। 41 वर्षीय बालन अब दुनिया भर में मानव कंप्यूटर नाम से चर्चित शकुंतला देवी (1929-2013) की बॉयोपिक में मुख्य किरदार निभा रही हैं। यह फिल्म 31 जुलाई को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता इस अभिनेत्री ने पिरिधर झा से अपनी नई फिल्म, करिअर, बॉलीवुड में मेहनताने में महिला अभिनेत्रियों के साथ भेदभाव जैसे तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की। कुछ अंशः

आप शकुंतला देवी की इसी नाम से आ रही बॉयोपिक में किरदार निभा रही हैं, अपने स्कूल के दिनों में आप गणित की कैसी छात्रा रही हैं?

स्कूल के दिनों में मुझे गणित हल करने में मजा आता था। दसवीं के बाद मैंने गणित नहीं लिया, मैं आटर्स की छात्रा थी। उसके बाद गणित की आदत छूट गई। मुझे खुशी है कि शकुंतला देवी के बहाने मैंने नंबर्स (संख्याओं) से नाता फिर खोज लिया है।

आप जिस इंडस्ट्री में हैं, उसमें नंबर वैसे भी महत्वपूर्ण हैं...

(हसते हुए) जिंदगी में भी। आपको नहीं लगता कि जिंदगी में भी संख्याएं महत्वपूर्ण होती हैं, हर चीज में गणित है।

ऐसी महिला का किरदार निभाना कैसा रहा, जिसे अपने जीवनकाल में ही ‘मानव कंप्यूटर’ की उपाधि पिल गई थी?

यह बहुत ही रोमांचक पर चुनौतीपूर्ण था। दुनिया बेशक शकुंतला देवी को मानव कंप्यूटर के रूप में जानती है, लेकिन फिल्म में उन्हें न केवल गणितीय प्रतिभा के रूप में, बल्कि एक महिला, मां और एक व्यक्ति के रूप में उनके जीवन को दिखाने की कोशिश की गई है। यही सबसे रोमांचकारी था। गणित वाला हिस्सा कठिन था पर मैंने इसका भी आनंद उठाया।

स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त आपको शकुंतला देवी के व्यक्तित्व के कई अज्ञात पहलुओं के बारे में पता चला होगा। सबसे खास बात क्या थी, जिसने आपको इस बायोपिक के लिए प्रेरित किया?

वे जीवन का हर पल पूरी तरह से जीती थीं। खुद को कभी महिला के रूप में परिभाषित नहीं किया। इसके बजाय, उन्होंने खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करना चुना, जिसे नंबर्स का दुर्लभ

सुनील खंडारे

# गर्दिश में होंगे, न कंटेंट ”

उपहार मिला था। उन्होंने लड़की या महिला होने की सामाजिक सीमाओं को कभी, किसी तरह से बाधा नहीं बनने दिया। उन्होंने जीवन को ऐसे जिया जैसे हर पल आखिरी पल था। उन्होंने वह सब किया जो करना चाहती थीं। वे गणितीय प्रतिभा या मानव कंप्यूटर थीं, जिसकी वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। उन्होंने दुनिया भर में यात्राएं की और 1970 के दशक में समलैंगिकता पर तब किताब लिखी, जब लोग समलैंगिकता शब्द तक बोलने से डरते थे। उन्होंने पहेलियों और पाक कला पर भी किताब लिखी। वह राजनीतिज्ञ और ज्योतिषी भी थीं। उन्हें खाना बनाना और खाना, दोनों बेहद पसंद था। वे ड्रिंक का आनंद लेती थीं और कपड़ों की शौकीन थीं। जब मैंने यह सब सुना, तो कहा वाह! आम तौर पर जब हम गणित के बारे में बात करते हैं, तो दिमाग में ऐसे व्यक्ति की छवि आती है जो शायद थोड़े बोरिंग होते होंगे। ज्यादातर लोगों का गणित से ऐसा ही नाता रहा है लेकिन उन्होंने इसे बदल दिया। यही मेरे लिए सबसे रोमांचक था। उनकी कहानी दर्शक उनकी बेटी के नजरिए से देखेंगे, जिसके साथ उनका रिश्ता आसान नहीं था।

कामकाजी महिलाओं को वास्तविक जीवन में दोहरी भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। एक महिला और अभिनेत्री के रूप में क्या आप शकुंतला देवी के जीवन से खुद को जोड़ पाती हैं?

बिलकुल। अपना जीवन में अपनी शर्तों पर जीने की कोशिश करती हूं, मेरा पालन-पोषण इसी ढंग से हुआ। इसलिए मैं शकुंतला देवी के साथ खुद को जोड़ सकती हूं और उनसे प्रेरणा पाती हूं। मुझे लगता है कि यदि वह पचास, साठ और सत्तर के दशक में ऐसा जीवन जीती थीं, जैसा वह चाहती थीं तो आज जब स्थितियां इतनी बदल गई हैं, हमारे पास कोई कारण नहीं है कि हम अपने अधिकारों के लिए न लड़ें या अपने सपनों को हासिल न करें। इसलिए निश्चित रूप से मैं खुद को उनसे जोड़ पाती हूं। मुझे लगता है, अधिकांश महिलाएं उनसे काफी हृद तक खुद को जोड़ पाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण है, उनसे प्रेरित होंगी।

क्या आप काल्पनिक चरित्रों की तुलना में वास्तविक जीवन वाले व्यक्ति पर आधारित बायोपिक के लिए अलग तैयारी करती हैं?

निश्चित रूप से। काल्पनिक चरित्र के साथ आप अपनी कल्पना का उपयोग करते हैं। बायोपिक के लिए आपके पास संदर्भ के लिए वास्तविक जीवन है। आप उस व्यक्ति की नकल भी नहीं कर सकते क्योंकि आप कभी वह व्यक्ति नहीं हो सकते। मैं शकुंतला देवी की कुछ भूमिकाओं को अपनाने का प्रयास किया,

लेकिन सिर्फ भाव पकड़ने के लिए। उम्मीद है ऐसा करने में सक्षम हुई हूं।

आपको द डर्टी पिक्चर जैसी फिल्मों के साथ व्यावसायिक रूप से सफल महिला-केंद्रित सिनेमा युग की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। आप इसका आकलन कैसे करती हैं?

इस श्रेय के लिए मैं बहुत आभारी हूं, लेकिन मुझे लगता है, हम इस बदलाव के लिए तैयार थे। हम महिलाओं की कहानियां कहने और स्क्रीन पर महिलाओं की कहानियां देखने के लिए भी तैयार थे। सबसे अच्छी बात यह है कि हम व्यक्ति के तौर पर देखे गए, सिर्फ महिला के तौर पर नहीं। हम सिर्फ अपने लिंग से परिभाषित नहीं हैं। शकुंतला देवी के मामले में भी यही है। उन्होंने खुद को पहले एक व्यक्ति के रूप में देखा, महिला के रूप में नहीं। इसलिए फिल्मों में यह बदलाव वाकई दिल से है।

मैं शकुंतला देवी से प्रेरणा पाती हूं। जब वह इतने दशक पहले मनचाहा जीवन जीती थीं, तो आज हमारे पास कोई कारण नहीं कि हम अपने अधिकारों के लिए न लड़ें

बॉलीबूड वर्षों से पुरुष प्रधान रहा है। अतीत में कई महान अभिनेत्रियों को हीरो जैसा मेहनताना पाने का हक नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि अब फिल्म उद्योग बदल गया है?

मेरा अनुभव अलग रहा है, क्योंकि लगभग 12 बरस से मैं महिला केंद्रित फिल्में कर रही हूं। मैं अपनी फिल्मों में केंद्रीय भूमिका निभाती हूं, इसलिए मुझे नहीं पता कि टिप्पिकल हीरो वाली फिल्मों में समान भुगतान के बारे में दूसरे अभिनेताओं को कैसा लगता है। हालांकि मुझे पता है कि जहां तक हमारी फीस का संबंध है, अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है। यहां तक कि मेरी तरह की फिल्मों में, यदि आप उस बजट के अनुपात की तुलना करें, जो एक पुरुष अभिनेता को मिलता है, तो इसका अंतर पता चलेगा। इसके बावजूद, मैं यह ध्यान देना पसंद करती हूं कि हमने लंबा सफर तय किया है।

फिल्म उद्योग में महिलाओं की संख्या में भी बदलाव दिखता है। अब हम कई बार 50 फीसदी से ज्यादा महिला कर्मी को किसी फिल्म के सेट पर काम करते हुए देखते हैं...

बिलकुल। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि शकुंतला देवी की, निर्देशक-लेखक एक महिला (अनु मेनन) हैं। निर्माताओं में से एक, छायाकार, कला निर्देशक, कॉस्ट्यूम डिजाइनर और फिल्म एडिटर सभी महिलाएं हैं। हम महिलाओं की भारी उपस्थिति वाली टीम में थे और हमने एक-दूसरे का संवर्धित लाने में मदद की।

टीवी धारावाहिक हम पांच (1995) से लेकर पहली फिल्म यरिणीता (2005) के बीच आपके अनुभव क्या रहे?

जब मैंने हम पांच किया था तो मैं सेंट जेवियर कॉलेज में फर्स्ट इयर में थी। जेवियर में ही पढ़ते मैंने विज्ञापन फिल्में कीं। उस वक्त मेरा फोकस इस पर नहीं था। मैंने अभिनय पर फोकस करना शुरू किया तो मुझे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुझे दक्षिण में भी कई बार अस्वीकृत किया गया। लेकिन मुझे लगता है, यह ठीक है। शायद यही कारण है कि आज मैं चीजों की इतनी अहमियत समझती हूं।

आपने हाल ही में एक लघु फिल्म नटरखट के साथ निर्माता के रूप में शुरुआत की। फिल्म उद्योग में आपके कद को देखते हुए, आप बड़े बजट वाली फिल्म आसानी से बना सकती थीं।

दरअसल मैं निर्माता बनने के बारे में नहीं सोच रही थी। नटरखट (2020) को प्रोड्यूसर क्रेडिट में डाल सकते हैं। उन्होंने कहा, “हम आपकी फीस नहीं दे सकते लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल फिल्म बनाने में कर सकते हैं। निर्माता के रूप में नाम होने से फायदा मिलेगा।” मैंने भी कह दिया, ठीक है।

फिल्मों को सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग करने से क्या स्टार सिस्टम खत्म हो जाएगा और असली स्टार के रूप में एक बार फिर हमेशा के लिए कंटेंट स्थापित हो जाएगा?

हम ऐसे समय में हैं जब कंटेंट ही किंग है। लेकिन मुझे विश्वास है कि सितारे चमकते रहेंगे। दर्शक जिनकी शिखियत और काम को पसंद करेंगे, वे सितारे बन ही जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि यह दोनों में से किसी एक को चुनने का मामला है। संभव है, दोनों एक-दूसरे से जुड़े रहेंगे।



## जलपरी के जलवे

सुरक्षित रहने के लिए सनी लियोनी ने भारत छोड़ दिया है। मुंबई में सख्ती के साथ 'सामाजिक दूरी' का पालन करने वाली सनी लॉस एंजिलिस में इसका पालन नहीं कर रही हैं। उनकी इस्टाग्राम पोस्ट तो यही बता रही है। समुद्र तट पर मस्ती करते हुए उनका फोटो आया, तो कोविड महामारी के दौर में जैसे, उनके प्रशंसकों के लिए मौसम बदल गया। रिमझिम फुहरों वाली मुंबई, चिंता न करो, जल्द ही यहां फिर 'सनी' डे होगा।



## दूरी का बाजीगर

फिल्मों में अक्सर किरदार का नाम राज रखने वाले शाहरुख खान के लिए भी शायद यह राज ही होगा कि उनका बाहें फैला देने वाला अंदाज इतना लोकप्रिय क्यों है। अब असम पुलिस ने इस आइकॉनिक पोज को सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश देने के लिए इस्तेमाल किया है। पुलिस के ट्वीट के अनुसार शाहरुख खान कहते हैं, "कभी-कभी पास आने के लिए कुछ दूर जाना पड़ता है और दूर जाकर पास आने वालों को बाजीगर कहते हैं।" इसलिए एक-दूसरे से छह फुट की दूरी रखें और बाजीगर बनें।



## अक्षरा कॉल

बॉलीवुड वाले क्षेत्रीय सिनेमा के सितारों को कमतर आंकने की गलती न करें। टिकटॉक पर बैन लग चुका है, लेकिन फरवरी में रिलीज हुई भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह का टिकटॉक स्पेशल गाना 'कॉल करें क्या' 10 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। सात फरवरी को रिलीज हुए इस गाने को यूट्यूब पर अब तक 10,07,07,565 व्यूज मिल चुके हैं। "कभी इजहार भी नहीं करते और चुपके-चुपके इतना प्यार दे जाते हो आप लोग," फैंस का शुक्रिया करते अक्षरा की खुशी छिपाए नहीं छिपती। लेकिन उनके हर मुरीद की जुबां पर अब एक ही सवाल है, "कॉल करें क्या?"

## बॉलीवुड की नई अप्सरा

राम गोपाल वर्मा फिर लौट आए हैं। न सिर्फ लौट आए हैं बल्कि बॉलीवुड के लिए नई सौगत भी लाए हैं। (अच्छी) फिल्में बनाना उन्होंने भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन बॉलीवुड के लिए नए चेहरे खोजना नहीं छोड़ा है। उनकी नई पेशकश है, अप्सरा रानी। यूं तो अप्सरा रानी ओडिशा की हैं, लेकिन देहरादून में पली-बढ़ी हैं और आजकल हैदराबाद में रहती हैं। आरजीवी ने सबसे पहला काम तो यह किया कि उन्होंने अंकिता महाराणा को अप्सरा रानी बना दिया।



## दृष्टि बाधा नहीं

झारखण्ड के बोकारो में दृष्टिबाधित आइएस राजेश सिंह को डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है। इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। पटना के राजेश ने 2007 में यूपीएससी की दिव्यांग श्रेणी में तीसरी वरीयता हासिल की थी। तब कोर्ट ने सरकार को राजेश सिंह की नियुक्ति के निर्देश देने के साथ कहा था, “आइएस के लिए दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण की जरूरत होती है।”



## वीरप्पन की बेटी

हाल ही में 29 साल की विद्या वीरप्पन को भाजपा ने तमिलनाडु युवा मोर्चे का उपाध्यक्ष बना दिया। उनकी पहचान बच्चों के लिए एक स्कूल की संचालिका से ज्यादा वीरप्पन की बेटी की है।

# शहरनामा

## पटना



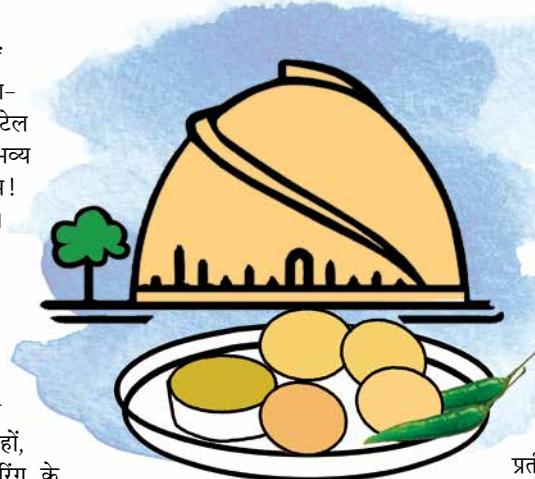
**गिरिधर झा**  
(लेखक आउटलुक के कार्यकारी संपादक हैं)

### गुम गुलमोहर गलियां

आप पिछले कुछ वर्षों से पटना नहीं आए हैं, तो यकीनन यह शहर बदला-बदला-सा दिखेगा। ज्ञान भवन, पटेल भवन, अधिवेशन भवन, बापू की भव्य मूर्ति और एक विश्वस्तरीय म्यूजियम! यहां तक कि एक सभ्यता द्वारा भी। गंगा किनारे एक मरीन ड्राइव बनाने की कवायद भी जारी है। चारों तरह पुल-पुलियों का जाल, चमचमाती सड़कें आपको हैरत में डाल सकती हैं। एक बारगी लगेगा मानो किसी वास्तुविद को सत्ता साँपं दी गई है। हैरान न हों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंजीनियरिंग के छात्र रहे हैं। जाहिर है, राजधानी को चमकाने में आधुनिक स्थापत्य कला की महत्ता से अनभिज्ञ न रहे होंगे। इसके बावजूद, आपको कुछ खालीपन का एहसास तो जरूर होगा। बेली रोड के किनारे रंग-बिंगे गुलमोहर और अमलतास की कमी निश्चित खलेगी, जिसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाते थे। पाटली के वृक्ष, जिसके काणण पाटलिपुत्र का नामकरण हुआ, अब गुलर के फूल हो गए हैं। आप पूछ सकते हैं, इसमें नया क्या है? हमारे आधुनिक बनने की कीमत प्रकृति से ज्यादा किसने चुकाई है?

### सजदा यक्षीकार का

पटना में नई अट्टालिकाएं कुकुरमुते की तरह उग आई हैं। छोटे शहरों से पलायन कर यहां बसने वालों की तादाद उतनी ही होगी, जितनी पटना से नोएडा और गुरुग्राम जाने वालों की। पुरखों की गांव की जमीन बेचकर शहर में एक 2-बीएचके के कई सपने यहां साकार होते मिलेंगे। हालांकि इस बदलाव के दौर में भी शहर के प्रमुख आकर्षण दशकों पुराने ही हैं। वही 1786 में बना ऐतिहासिक गोलघर, जिसके शिखर से आपको गंगा तट पर बसे पूरे शहर का विहंगम दृश्य दिखेगा। वही दीदारगंज यक्षी की मूर्ति जिसे देखकर आपको गुजरे जमाने के गुमनाम शिल्पकारों के सजदे में सर झुकाने का मन करेगा। वही पुराने सचिवालय में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों का बनाया भव्य कर्लोक टॉवर। वही दरभंगा हाउस स्थित काली मंदिर, वही अशोक राजपथ की खुदाक्ष क्षेत्री। जब आप



1917 में बने पटना म्यूजियम को निहारेंगे तो आपके मन में अनायास यह ख्याल आ सकता है कि क्यों न इस खूबसूरत भवन को नींव समेत उखाड़कर 500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बने नए बिहार म्यूजियम में स्थापित कर दिया जाए। कुछ तो देखने लायक हो वहां!

### हम लिट्टीवाले

पटना के बाशिंदे आदिकाल से ही खाने-पीने के शौकीन रहे हैं। नीतीश कुमार की बजह से पिछले चार वर्षों में उन्हें 'पीने' के शौक को ताक पर रखना पड़ा है। अब सारा ध्यान खाने पर ही केंद्रित है। हर चौक-चौराहे पर लिट्टी-चोखा के स्टाल खुल गए हैं। लिट्टी बिहार की अस्मिता और स्वाभिमान का प्रतीक बन गई है। पहले यह मेहनतकश और गरीब-गुरबों का पसंदीदा व्यंजन था, अब इसकी पैठ पांच सिटारा होटलों तक हो गई है। यह बात और है कि अधिकतर लिट्टी अब मैदा से बनी मिलेगी। आप कितना भी शुद्ध धी में डुबोएं, उसमें पारंपरिक आटे की बनी लिट्टी की शान में कोई गुस्ताखी करें। ऐसा करके आप खुद को ही खतरे में डालेंगे। अपनी पिछली यात्रा के दौरान आमिर खान अपने लाव-लश्कर के साथ पटना के जैविक उद्यान के निकट एक स्टाल पर पहुंचे और लिट्टी का ऑर्डर किया। पलक झपकते ही धी (या रिफाइंड तेल?) में सराबोर गरमागरम लिट्टी चट्कदार चोखा के साथ उनके हाथों में थी। आमिर ने खांटी बिहारी व्यंजन जैसे ही चखा, लिट्टीवाले को 500 रुपये दिए और स्टील की प्लेट समेत जाने की इजाजत मांगी। शायद वे रास्ते में इसका जायका इत्मीनान से अपनी एसयूवी में लेना चाहते होंगे!

### चंपारण मीट गाला

शहर के किसी सीनियर सिटीजन के मुंह में महंग का नाम सुनकर अगर पानी आ जाए, तो आपको हैरत में नहीं पड़ना चाहिए। वर्षों तक मछुआ टोली स्थित छोटा-सा रेस्तरां निरामिष-पसंद शौकीनों का अड़ा हुआ करता था। इसके मुगलई व्यंजनों की ख्याति गंगा के दोनों ओर बसे सुरूर नगरों तक थी। ऐसी ही लोकप्रियता बिस्कोमान भवन स्थित चायनीज रेस्तरां, शिन लॉना की थी, जिसके रसोईघर से निकली खालिस चीनी मसालों की खुशबू पास के आलीशान मौर्या होटल के शफ को बेचन करने के लिए काफी थी। अब जमाना बदल चुका है। हर दूसरी गली में 'चंपारण मीट' की दुकानें खुल गई हैं। खास बात यह है कि ऐसे हर रेस्तरां चलाने वालों का दावा है कि उसकी दूसरी शाखा नहीं है। दरअसल चंपारण के स्थानीय ढाबों के सुस्वादु तास और अहुना मीट वर्षों से वहां की संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि चंपारण, जो सौ वर्षों से ज्यादा तक गांधी के सत्याग्रह का पर्याय और प्रतीक रहा है, अब अपने मटन के व्यंजनों के कारण जाना जा रहा है।

### नेहरू रोड

पटना की जीवनरेखा कहे जाने वाले बेली रोड का आधिकारिक नाम वैसे तो जवाहरलाल नेहरू पथ है, लेकिन इसे कोई इस नाम से नहीं पुकारता। ऐसा वर्षों से हो रहा है। ध्यान रहे, इसमें स्थानीय भाजपा-जदयू सरकार का कोई हाथ नहीं।

# 'न्याय' की शुरुआत छत्तीसगढ़ से

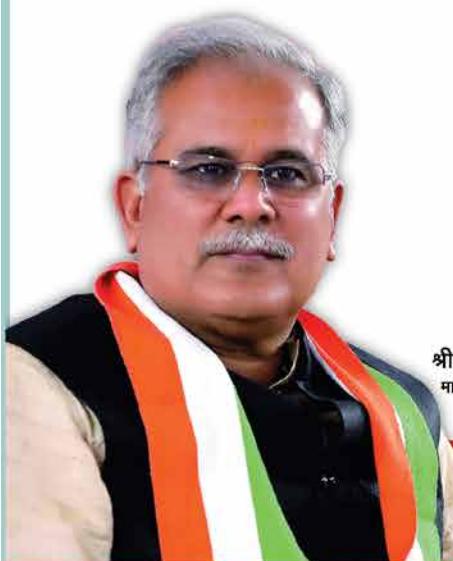


## राजीव गांधी किसान न्याय योजना-

- ◆ धान, मक्का, गन्ना के 19 लाख किसानों के खातों में 4 किस्तों में जाएगी 5700 करोड़ रु. की राशि
- ◆ प्रथम किस्त की 1500 करोड़ रु की राशि का वितरण 21 मई 2020, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी के शहादत दिवस से प्रारंभ

## भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना-

- ◆ भूमिहीन कृषि मजदूरों की सुनिश्चित आय की व्यवस्था हेतु कार्ययोजना बनाने के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित



श्री भूपेश बघेल  
माननीय मुख्यमंत्री  
छत्तीसगढ़



पादा निभाने का फौलादी इरादा



# You fly Safely Nonstop...



**Available in 5, 10 & 20pcs Box  
(with & without Respirator)**



**Available in  
100ml, 200ml & 500ml**



Manufacturing & Marketed By:

**HR LUZON**

For Inquiry : +91 63535 40490 / 74370 37037

care@luzonhealthcare.com | sales@hrhygiene.com



**ASK FEMMI**



for more details  
WhatsApp : +91-74900-29004

Available on  
**amazon** **Flipkart** **snapdeal** **PAYTM**  
Also available in all leading medical stores.